हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 2008

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

विषय सूची

वीरवार, 20 मार्च, 2008

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)1
सदन की एक समिति का गठन	(10)20
सदस्यों का नाम लेना	(10)27
सदस्यों को नेम करने के फैसले को रद्द करना	(10)29
गैर-सरकारी संकल्प—	(10)32
कुटीर उद्योगों, विशेषकर पारंपरिक उद्योगों की अवनति के संबंध में	
बैठक का समय बढ़ाना	(10)66
गैर-सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(10)66

मूल्य : 67

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 09.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Upgradation of 66 K.V. Sub-station to 132 K.V. Sub-station at Madlaoda

*** 950. Smt. Raj Rani Poonam :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 66 K.V. Sub-station to 132 K.V. Sub-station at Madlaoda in district Panipat?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : The existing sub-station at Madlaoda is already of 132 K.V. level and its present installed capacity is sufficient to feed the load of the area.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगा कि इस सब-स्टेशन को 20×25 MVA का ट्रांसफार्मर लगाकर ऑगमैंट किया है जिस पर 150 लाख रुपये की लागत आई है जो 23.11.2007 को कमीशन कर दिया गया था। इसके अलावा सरकार यह भी सोच रही है कि एक 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन ब्राह्मण माजरा में और 44 के वी.ए. का सब-स्टेशन डाहर में भी हम बनायेंगे।

श्रीमती राज रानी पूनम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इस सब-स्टेशन को 132 के०वी०ए० से अपग्रेड करने का सरकार का कोई प्रावधान है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह सब-स्टेशन 132 के०वी०ए० का तो पहले से ही है। माननीय सदस्या ने यही प्रश्न पूछा था कि क्या 66 के०वी०ए० के सब-स्टेशन को 132 के०वी०ए० सब-स्टेशन में अपग्रेड करने का सरकार का कोई विचार है। इसके जवाब में मैंने पहले ही बता दिया है कि 132 के०वी०ए० सब-स्टेशनों को 23.11.2007 को फरदर ऑगमैंट करके कमीशन कर दिया गया है जिस पर 150 लाख रुपये की लागत आई है। इस इलाके को बेहतर सुविधा देने के लिए 33 के०वी०ए० के सब-स्टेशन ब्राह्मण माजरा और डाहर में भी बनायेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब लोकल लेवल पर करनाल में 132 के०वी०ए० का सब-स्टेशन लगाने का प्रपोजल है और उस सब-स्टेशन को लगाने के लिए म्यूनिस्पिल काउंसिल ने रैजोलूशन पास करके सरकार को भेज दिया है। मैं शहरी विकास मंत्री जी और बिजली मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब लोकल लेवल पर कोई केस पास होकर सरकार को भेज दिया जाता है तो उसको सरकार फोलो अप करे ताकि यह काम जल्दी हो जाये क्योंकि 3-4 महीने हो गये हैं सरकार की तरफ से कोई रिसपोंस नहीं मिला है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जमीन के स्थानान्तरण का मामला है जो माननीय शहरी विकास मंत्री जी के विभाग से जुड़ा हुआ है लेकिन माननीय शहरी विकास मंत्री जी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में शहरी विकास मंत्री जी को और मुझे लिखकर भिजवा दें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जमीन का हस्तांतरण जल्दी हो जाए।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पहले भी पूछा था। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो 132 के०वी०ए० के सब-स्टेशन 15-15 साल पहले बनाये गये थे उनको फरदर एक्सटैंशन करने का सरकार का कोई प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बिजली की जो तारें टूटी पड़ी हैं उनको ठीक करवाने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है क्योंकि मेरे हल्के के भाड़ावास गांव में बिजली की तारें टूटी पड़ी हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय सदस्या स्पैस्फिक सब-स्टेशन जिन-जिन गांवों के हैं वे लिखकर भिजवा दें हम जांच करवाकर उनको सूचित करवा देंगे।

Upgradation of Power Sub-station

***858. Dr. Sita Ram :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade or augment the power Sub-stations in district Sirsa ; if so, whether there is any proposal to upgrade 132 K.V. Sub-station of Asha Khera also?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : During the period from March, 2005 to January, 2008, five new 33 K.V. Sub-stations and 28.9 Km 33 KV lines have been constructed, existing one 220 K.V., seven 132 KV & six 33 K.V. Sub-stations augmented at an investment of Rs. 26.33 crore in District Sirsa.

In the next two years, it is proposed to construct eight new 33 KV Sub-stations and 64.52 Km. associated lines as well as augment one 33 K.V. and two 132 KV Sub-stations at an investment of Rs. 15.69 crore in District Sirsa.

At present, there is no proposal to upgrade the 132 KV Sub-station Asha Khera. However, there is a proposal to create a new 220 K.V. Sub-station in the area around Asha Khera to meet the load growth of the area and land is being identified for the purpose. The feeding source of this Sub-station will be from a planned 400 K.V. Sub-station at Nuhiyawali in Sirsa district which is likely to be

commissioned in 2010-11. The 220 K.V. Sub-station in the area surrounding Asha Khera and its associated transmission lines will be commissioned in about 3 years at a cost of approximately Rs. 30 crore.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने आशाखेड़ा के सब-स्टेशन की अपग्रेडेशन के बारे में कहा है कि "नहीं" लेकिन जो 132 के०वी०ए० सब-स्टेशन है इस सब-स्टेशन से कई गांवों को बिजली जाती है और जब बिजली के पीक आवर्स होते हैं और बिजली का शिडयूल होता है उस समय बिजली बार-बार ट्रिप करती है, बिजली के कट लगते हैं और जब हम अधिकारियों से इस बारे में पूछते हैं कि यह ट्रिपिंग क्यों हो रही है तो वे कहते हैं कि इस सब-स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वह छोटी कैपेसिटी का है। इसलिए मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जब तक इस ट्रांसफार्मर को बड़ा नहीं किया जाता तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि इस उपकेन्द्र का फीडिंग स्रोत जिला सिरसा के नुहियांवाली में एक 400 के०वी० के प्रस्तावित उपकेन्द्र से होगा जो वर्ष 2010-11 में चालू होना सम्भावित है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इससे पहले हमारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहां बिजली का उत्पादन महत्वपूर्ण है वहीं बिजली की ट्रांसमिशन व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है और मैं उनकी चिन्ता से अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था आशाखेड़ा में 132 के०वी० सब-स्टेशन की अपग्रेडेशन करेंगे या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमने यह कह दिया कि हम 132 नहीं 220 के०वी० का नया सब-स्टेशन बनाएंगे and 220 K.V. is much higher than 132 K.V. अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमने जो कदम उठाए हैं वे बड़े एलोबरेट हैं और मैंने उनकी भी चर्चा करके बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑगमैंटेशन और क्रिएटिंग आफ न्यू सब-स्टेशंज तीनों को लेकर हम काफी गंभीर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य जी को और सदन को बताना चाहूंगा कि मार्च 2005 के बाद हमने अब तक 68 नए सब-स्टेशंज बनाए हैं, 182 सब-स्टेशनों को पूरे हरियाणा में ऑगमैंट किया है, 1137 किलोमीटर की बिजली की नई लाइनें लगाई हैं जिन पर कुल खर्चा अब तक 538 करोड़ 57 लाख रुपये आ चुका है। माननीय सदस्य की चिन्ता के साथ मैं अपने आप को जोड़ते हुए सदन को बताना चाहूंगा कि इस समय to reinforce our transmission, distribution and infrastructure की हमारी प्रपोजल है। हम 164 नए सब-स्टेशन 18 से 24 महीनों के अंदर बनाएंगे, 94 एग्जिस्टिंग सब-स्टेशनों को ऑगमैंट करेंगे और 2678 किलोमीटर लाइनें सरकार अगले 18 से 24 महीनों में खींचेगी और इन पर 2142 करोड़ रुपये खर्चा आएगा जो हरियाणा के गठन के बाद अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय जी से जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं आया। इन्होंने और चीजें तो पढ़ दी लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा है कि जो आशाखेड़ा सब-स्टेशन है इसकी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाएंगे या नहीं क्योंकि 2010-11 तक दो-तीन साल कौन इंतजार करेगा। मेरा सवाल यह है और मंत्री जी को इसका स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी मेरी बात को समझ नही पाये हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि आशा खेड़ा में 132 के०वी० का सब-स्टेशन ऑगमैंट करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है लेकिन इस क्षेत्र को और पूरे सिरसा जिले को अच्छी बिजली मिले उसके लिए सरकार 32 के०वी० के 8 नये सब-स्टेशन सिरसा जिले में लगा रही है। Speaker Sir, I think, Dr. Sita Ram ji, does not know the distinction between a 220 K.V. Sub-station and 132 K.V. Sub-station. Now, what can I do about it? Speaker Sir, he should come to me and I will explain him the modality. We are creating a new 220 K.V. Sub-station in the immediate vicinity of Asha Khera. Speaker Sir, once we are creating 220 K.V. Sub-station where is the need to augment 132 K.V. Sub-station at Ashakhera ?

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में आ गई है कि आशा खेड़ा में 132 के०वी० का सब-स्टेशन नहीं लगाया जायेगा। लेकिन मैंने यह भी पूछा है कि क्या वहां पर अभी बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा ताकि ट्रिपिंग की समस्या न हो।

इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। (विघ्न)

Sarav Shiksha Abhiyan

***937. Dr. Sushil Indora :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Sarav Shiksha Abhiyan has been started to eliminate the curse of illiteracy and for promoting the education ; and

(b) the year-wise and district-wise amount spent under this scheme during the period from March, 2005 to date?

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) :

(a) Yes Sir,

(b) A statement is placed on the table of the house.

Statement

Details of Yearwise and Districtwise amount spent under the SSA during the period from March 2005, to date

(Rs. in Lacs)

S. No.	Distt.	2005-06	2006-07	2007-08 (Upto 31.01.08)
		Amount Spent	Amount Spent	Amount Spent
1.	Ambala	779.49	1713.78	1002.35
2.	Bhiwani	1734.68	2339.77	1581.34
3.	Faridabad	2009.38	2670.32	1637.29
4.	Fatehabad	1034.35	1797.37	982.40
5.	Gurgaon	1725.05	1692.04	1123.83

(Rs. in Lacs)

S. No.	Distt.	2005-06	2006-07	2007-08 (Upto 31.01.08)
		Amount Spent	Amount Spent	Amount Spent
6.	Hisar	1436.25	1857.34	984.12
7.	Jhajjar	501.52	919.35	544.77
8.	Jind	973.13	1248.49	757.11
9.	Kaithal	866.35	1313.94	912.98
10.	Karnal	1415.67	1707.7	932.92
11.	Kurukshetra	917.56	1498.2	1044.37
12.	M/Garh	832.33	1093.67	644.21
13.	Mewat		1960.01	1432.03
14.	Panchkula	337.75	731.92	491.39
15.	Panipat	694.78	1194.07	748.13
16.	Rewari	682.00	985.65	663.02
17.	Rohtak	585.49	809.31	499.49
18.	Sirsa	1023.82	1967.62	942.41
19.	Sonepat	698.04	1059.81	703.36
20.	Y. Nagar	1365.45	1573.73	1423.08
21.	SPIU	245.45	254.59	216.95
	Total	**19858.60**	**30388.69**	**19267.55**

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत अनुभवी और सीनियर मंत्री हैं और मेरे लिये ये विशेषकर आदरणीय भी हैं। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब यह निकलता है कि सबको शिक्षा मिले। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दर्शाया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न जिलों में 19267.55 लाख रुपये खर्च हुआ है और सर्व शिक्षा अभियान ने अपना टार्गेट भी पूरा किया है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना बजट अलॉट किया गया था और जो पैसा खर्च किया गया है वह किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया है?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय साथी ने बजट अलॉटमैंट की बात की है, इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2005-06 में 249.88 लाख रुपये का बजट रखा गया था जिसमें से 198.58 लाख रुपये खर्च किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान 365.91 लाख रुपये का बजट रखा गया जिसमें से 303.88 लाख रुपये खर्च हुआ और जो करैंट ईयर है उसमें 31.1.2008 तक 357.6 लाख रुपये अलॉट किए गए हैं जिसमें से 192.67 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं तथा बाकी की फिगर अभी आनी बाकी हैं तकरीबन 250 करोड़ रुपये खर्च हो जायेगा। अध्यक्ष

[श्री मांगे राम गुप्ता]
महोदय, इसमें जो पैसा बचता है वह अगले साल ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि बिल्डिंग वगैरा कंसट्रैक्शन करनी होती हैं जिनका एस्टीमेट बाद में बनाया जाता है और अगले साल पैसा यूज हो जाता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह तो बतायें कि यह पैसा किन-किन कार्यों के लिए खर्च किया गया है?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, 2007 में भारत सरकार ने एक स्कीम दी थी कि पूरे देश में उन्होंने हर बच्चे को शिक्षा देनी है और विशेषकर 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो गरीब हों, झोंपड़ी में रहने वाले हों उनके लिए पूरी तरह से कोशिश की जाये कि उन्हें शिक्षा मिले, वे अनपढ़ न रहें। इस सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के तहत नौवीं प्लान के तहत 85 : 15 प्रतिशत के रेशो के हिसाब से भारत सरकार और स्टेट गवर्नमैंट ने पैसा खर्च करना था। दसवीं प्लान के तहत 75 : 25 प्रतिशत के रेशो से पैसा खर्च करना था और ग्यारहवीं प्लान के तहत 50 : 50 प्रतिशत के रेशो के हिसाब से पैसा खर्च करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस स्कीम के कई आब्जैक्ट्स हैं। जैसे प्राइमरी स्कूलों को बनाना, बच्चों को किताबें देना, मिड डे मील मुहैया करवाना, स्कूल में कमरे और टायलैट्स बनवाना आदि यानि की जो भी बच्चों की जरूरत पढ़ाई को लेकर हैं उनको पूरा करना इस स्कीम के मेन आब्जैक्ट्स हैं। मैंने अपने जवाब में पूरी डिटेल दी हुई है, उसमें से किसी स्पेसीफिक के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मुझे बतायें। स्पीकर सर, यह जो हमारी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की स्कीम थी इसमें हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि आज गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें काफी सफलता मिल रही है। इसमें हमें सभी का सहयोग चाहिए जिससे हम इसमें प्रगति के नये आयाम स्थापित कर सकें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब बड़े विस्तार से दिया है लेकिन इसमें फिर भी कुछ रह गया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सर्व शिक्षा अभियान का यह भी मकसद था कि प्राईमरी एजूकेशन में गरीब बच्चे स्कूल से ड्राप आउट न हों, वे स्कूल छोड़कर प्राईवेट स्कूलों में या अपने घर न जायें। इसलिए क्या शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम सरकार ने उठाये हैं। इसके अतिरिक्त क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने बच्चे सरकारी स्कूलों से ड्राप आउट हुए हैं? क्योंकि समाज में एक डिसपैरिटी आ जाती है, वैसे तो हमारे गांव-गांव में सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। यह बात भी सही है कि ग्रामीण स्कूलों में ट्रेंड टीचर्ज हैं भले ही उनकी संख्या कम हो। तो क्या इन टीचर्ज की कमी को दूर करते हुए सरकार द्वारा ऐसी गुणात्मक शिक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा जिससे सामाजिक एवं शैक्षणिक डिसपैरिटी भी न आये और गरीब बच्चों द्वारा जो सरकारी स्कूलों से विभिन्न स्तरों पर ड्राप आउट किया जाता है वह भी रुके।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी और सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा इस बात के पूरे प्रयास किये गये हैं कि कोई भी

बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के बाद ड्राप न कर सके। इस मकसद को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए बड़े-बड़े इंसैंटिव्ज दिए गए हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि उनको फ्री किताबें दी जायेंगी, फ्री यूनिफार्म दी जायेंगी और फ्री मिड-डे मील दिया जायेगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 ब्लॉक्स में शिक्षण संस्थान खोले गये हैं उनमें वोकेशनल एजूकेशन भी दी जा रही है और अगर उनके लिए कोई रैंजीडेंशियल या कोई दूसरी प्रॉबल्म हो तो उसके लिए भी प्रबन्ध किया जायेगा। इसके साथ ही हर बच्चे को जो किसी गांव से आता है उसके लिए साईकिल वगैरह प्रदान करने का भी प्रावधान सरकार ने किया है। इसके अतिरिक्त गरीब बच्चों को मैडीकल सुविधा और कोचिंग क्लासिज की सुविधा भी सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। गरीब बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जा रही है और खेलों के प्रति उनके मन में रूचि पैदा करने के लिए खेलों से संबंधित सभी सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार द्वारा सभी वांछित प्रयास किये जा रहे हैं ताकि बच्चा स्कूल में आकर घर जाने के बारे में और स्कूल छोड़ने के बारे में सोच भी न सके। अच्छे टीचर्ज लगाये जा रहे हैं। कुल मिला कर मैं यह कह सकता हूं कि सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए इतनी सुविधायें और ऐसा माहौल प्रदान किया जा रहा है कि भविष्य में कोई भी गरीब बच्चा स्कूल में आने से हिचकिचायेगा नहीं। इसमें हमें बहुत भारी सफलता भी मिली है। स्पीकर सर, इस बारे में कल भी हाउस में चर्चा हुई थी कि हमारी सरकार द्वारा एक ऐसी अनोखी स्कीम राज्य में बी०पी०एल० के बच्चों के लिए चलाई गई है जो कि सारे देश में सबसे पहले सिर्फ हरियाणा में ही चलाई गई है। इस स्कीम के तहत बी०पी०एल० के बच्चों और विशेषकर शैडयूल्ड कास्टस के बच्चों को पहली क्लास से पांचवीं क्लास तक लड़के को 100/- रुपये और लड़की को 150/- रुपये प्रति मास मिलेंगे, छठी से नौवीं तक लड़के को 150/- रुपये और लड़की को 200/- रुपये प्रति मास मिलेंगे, दसवीं में दाखिला लेने पर लड़के को 200/- रुपये और लड़की को 300/- रुपये प्रति मास मिलेंगे और हायर क्लासिज में जाने पर लड़के को 300/- रुपये और लड़की को 400/- रुपये प्रति मास मिलेंगे। इससे बड़ा इंसैंटिव और क्या हो सकता है। अब अगर एक बच्चा एक बार स्कूल में दाखिला ले लेगा तो वह किस कारण से ड्राप करेगा क्योंकि हमारी सरकार ने ड्राप करने के कोई चांसिज नहीं छोड़े हैं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राईमरी स्कूलों में मिड-डे-मील स्कीम है उसके अन्दर क्या किसी प्रकार की कोई अनियमिततायें पाई गई हैं? क्या खरीद के मामले में भी कोई अनियमिततायें पाई गई हैं और अगर पाई गई हैं तो उसमें सरकार के स्तर पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उनकी यह चिंता वाजिब है। कुछ जगहों पर मिड-डे-मील की परचेजिंग में अनियमिततायें हुई हैं। जब यह बात हमारे नोटिस में आई तो हमने उसकी इंक्वायरी करवाई है। दोषियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किये गये हैं। कई केसिज में विजीलैंस इंक्वायरी भी चल रही है और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सरकार ने एक

[श्री मांगे राम गुप्ता]
फैसला लिया कि जो सबसे बड़ा एक लकूना था जिसके कारण ये परचेज में गड़बड़ी हो रही थी हमने उस गड़बड़ी की जड़ को समझा है और हमने चोर को नहीं चोर की मौसी को ही मारा है। पहले एक अप्रूव्ड सोर्स के माध्यम से फील्ड में परचेज करने का काम चल रहा था। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सोर्स बना हुआ था कि चाहे कितने ही ऊंचे भाव में कोई चीज खरीद ली जाती और उस अप्रूव्ड सोर्स का ठप्पा लगवा कर बिल जमा करवा दिये जाते थे और उस पर कोई ऑब्जैक्शन नहीं होता था। हमने उसको स्टडी किया और उस मामले को कैबिनेट में रखवा कर खत्म कर दिया। भविष्य में हमारे विभाग में ही नहीं किसी भी विभाग में ऐसा कोई अप्रूव्ड सोर्स नहीं रहेगा जो खुद माल नहीं बनाता हो। अप्रूव्ड सोर्स के माध्यम से परचेजिंग नहीं होगी। ऐसी जो डुप्लीकेसी बनी हुई थी कागजी कार्यवाही करके अप्रूव्ड सोर्सिज का ठप्पा लगा दिया करते थे अब वह सारे हरियाणा में बैन करवा दी गई है। अध्यक्ष महोदय, अब चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मिड-डे-मील बनाने के लिए स्कूलों में जो कर्मचारी रखे जाते हैं क्या उनको कोई तनख्वाह दी जाती है? क्या मिड-डे-मील के कारण स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और क्या मिड-डे-मील बनाने के लिए स्कूलों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईड किया गया है?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मिड-डे-मील से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसको बच्चे तैयार नहीं करते। राशन के लिए और दूसरा सामान रखने के लिए अलग से स्टोर बने हुए हैं और इस काम के लिए अलग से आदमी रखे गये हैं। खाना बनाने के लिए अलग जगह है और छुट्टी के समय ही खाना दिया जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री भूपेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्कूलों में 5-5 हजार रुपये गैस कनैक्शन खरीदने के लिए दिये गये थे। उसमें से 1700 रुपये प्रिंसिपल को दिये गये थे बाकी 3300 रुपये की गैस चूल्हे की परचेजिंग हुई थी। उस परचेजिंग में बहुत गड़बड़ी हुई थी। जब बाजार में जाकर उस गैस चूल्हे की कीमत असैस की गई तो वह 400 रुपये पाई गई। इस परचेजिंग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मामले में क्या कोई कार्रवाई की गई है?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जहां इस बात की चिन्ता है उसके साथ ही साथ इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि इस घोटाले को भी हमने ही पकड़ा था। जब हमारे नोटिस में यह आया कि गैस चूल्हों की खरीद में गड़बड़ी हुई है तो हमने उस माल को जब्त किया और इन्क्वायरी करवाई। जिस-जिस जिले में ऑफिसर्ज ने गड़बड़ी की थी उन अधिकारियों को हमने सस्पैंड किया है और विजिलैंस को इन्क्वायरी दी है तथा दोषियों के खिलाफ केस रजिस्टर करने का फैसला लिया जा रहा है। भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है वे भी अब पछता रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कुछ साईंस टीचरों और साईंस लैक्चर्रज को भी सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है उससे बड़ी क्लासिज की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्या मंत्री जी साईंस के टीचर्ज और लैक्चर्ज को वापिस स्कूलों में भेजने का कोई आश्वासन देंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो सकता है कि किसी एक-आध स्कूल में कोई साईंस टीचर सर्व शिक्षा अभियान में लगा हो लेकिन हमारी प्राथमिकता तो साईंस को बढ़ावा देना है। अगर कोई साईंस टीचर प्राईमरी क्लासिज में लगा होगा तो हम उसको वापिस स्कूल में ही भेज देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, एक-आध नहीं बल्कि यह संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ लैक्चर्रज भी सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं जिससे बड़ी क्लासिज के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम साईंस के टीचर्स को भी और लैक्चर्रज को भी स्कूल और कॉलेजों में वापिस भेजेंगे ताकि बड़ी क्लासिज के बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, दादरी का डायट ब्लॉक है उसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत कमरे बने हुए हैं जिनमें सामान ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ है। पीछे हम पी०ए०सी० के साथ वहां पर गये थे। पिछली सरकार के समय में वहां पर जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर रख दिया गया है जो कि लम्बे अरसे तक इस्तेमाल नहीं हो सकता तथा सामान रखा होने के कारण उन कमरों का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्या माननीय मंत्री महोदय, इस बारे में जांच करवा कर जो भी दोषी व्यक्ति अथवा अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस प्रकार की शिकायत किसी ने मेरे सामने लाने का प्रयास किया है। पी०ए०सी० की रिपोर्ट की कोई सूचना अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। हमारा प्रयास है कि ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में इस प्रकार का सामान जरूरत से ज्यादा खरीदा गया। हम इस बारे में इन्क्वायरी करवाएंगे और चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी है जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा देंगे। वैसे तो पिछली सरकार के बारे में राम कुमार गौतम जी ने आपके सामने ही फैसला कर दिया था कि जब तक ऐसे लोगों को सजा देकर जेलों में नहीं डालेंगे और उनका सामान नीलाम नहीं करवाएंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में ऐसी बात तो नहीं कहता लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे नोटिस में ऐसी कोई शिकायत आएगी तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम मामले की पूरी इन्क्वायरी करवाएंगे और चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। हमने पहले भी प्रयास किया है कि हम किसी भी दोषी को नहीं छोड़ें और गलत काम करने वालों को सजा दें।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मिड-डे-मील स्कीम के तहत गांवों में जो स्कूल हैं उनमें बच्चों का खाना बनाने के लिए किसी महिला को रखा जाता है। जब यह स्कीम परमानैंट स्कीम है तो मिड-डे-मील खाना बनाने के लिए परमानैंट तौर पर किसी लड़की को रखा जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए सारे लोग कहते रहते हैं कि बहिन जी वहां पर हमें लगवा दें वे कभी किसी को कहने हैं कि मुझे लगवा दो इस प्रकार से ये पोस्टें लड़ाई का माध्यम बनी रहती हैं। स्पीकर सर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या ऐसी स्कीम में परमानैंट नौकरी नहीं बनाई जा सकती है?

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, कोशिश यह की जाती है कि मिड-डे-मील बनाने के लिए गांव की ही किसी महिला को लगाया जाए और इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि भगवान न करे अगर कोई महिला विडो हो जाए या कोई महिला बेसहारा हो जाए तो यह काम करने का मौका उसी को दिया जाता है। जहां तक मिड-डे-मील बनाने के लिए परमानैंट तौर पर किसी महिला को लगाने की बात है, मैं समझता हूं कि वह एक पार्ट टाईम काम है। दोपहर को करीब 100 बच्चों का खाना बना कर अपने घर चली जाती है। उसको सारा दिन अगर स्कूल में बिठा कर रखें तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके जिम्मे और कोई काम नहीं है। वह स्कूल का खाना बनाने के बाद अपने घर जाकर अपना कोई और काम कर सकती है।

Construction of Footpath

***877. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct footpath on both sides of road from Dinod Gate to Railway Station, Bhiwani, if so, the time by which such Footpath are likely to be constructed?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : It is not feasible to construct foot path on this road due to restricted right of way.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार टोटल सड़क पर फुटपाथ नहीं बना सकती है या कुछ ऐसा पोर्शन जो कन्जैस्टिड नहीं है वहां पर फुटपाथ नहीं बना सकती है। क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह लाया गया था कि जब यह डिपार्टमैंट श्री परमवीर जी के पास था तो इसका प्रपोजल एक बार पहले भी बना था और इस प्रपोजल की फाईल ऊपर तक भी आई थी। उस वक्त मैं कभी उनके दफ्तर में तथा कभी कमिश्नर साहब के दफ्तर में इस फाईल को ढूंढता रहा। उस वक्त यह स्कीम इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त यह फाईल ट्रेस नहीं हो पाई थी। क्या माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में बताएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी दिनोद गेट से रेलवे स्टेशन, भिवानी तक दोनों तरफ फुटपाथ बनवाना चाह रहे हैं। स्पीकर सर, यह सड़क टोटल 18 फुट चौड़ी है और जो average land available है वह 30 फुट है। अगर वहां पर वाटर

सप्लाई, सीवर, टैलीफोन लाईन्ज और इस प्रकार की जो पब्लिक यूटिलिटी की सुविधाएं हैं जो वहां पर निकलती हैं और अगर हम वहां पर फुटपाथ बना देंगे तो उससे वहां पर चारों तरफ जाम होगा क्योंकि वह सारा बिल्ट अप एरिया है। इसमें दूसरी दिक्कत यह है कि स्टोर्म वाटर ड्रेनेज की भी वहां पर व्यवस्था नहीं है और अगर कल को कहीं इस प्रकार की सुविधा प्रदान करनी पड़ जाएगी तो उसमें समस्या रहेगी। मेरे विभाग के लोगों ने मुझे वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई थी कि उस बाजार के अन्दर बड़ा भारी कन्जैशन है और अगर हम वहां पर फुटपाथ बना देंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि वहां लोग अपनी गाडियां भी खड़ी करनी शुरू कर देंगे तथा उसके बाद वहां पर जाम लगना भी शुरू हो जाएगा। रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण पैसेज है वहां पर यह जनहित में नहीं होगा कि हम फुटपाथ बनाएं।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वह सारी की सारी सड़क कंजैस्टीड नहीं है। कहीं थोड़ी सी जगह पर ही कंजैस्टीड होगी। जहां तक सीवर और पानी की पाईप लाईन की बात मंत्री जी ने कही है तो वह तो वहां पर बहुत पहले ही डाली जा चुकी है। अगर यह फुटपाथ बनेगा तो वहां पर जो लोग सामान सड़क पर रखते हैं वे उसको फुटपाथ पर रख लेंगे जिससे उस सड़क पर जो कंजैशन है वह भी खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वहां पर फुटपाथ बनाने के बारे में प्रपोजल बनाकर अधिकारियों ने भेज दिया था लेकिन वह फाईल मुझे नहीं मिली जिसकी वजह से वह काम रह गया था। क्या मंत्री जी अब वहां पर उस फुटपाथ को बनाने के बारे में विचार करेंगे?

10.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो फुटपाथ वाला पोरशन है वहां पर वाटर सप्लाई विभाग की और सीवरेज की लाईन्ज डली हुई है। अगर वहां पर फुटपाथ बना दिया गया और उसके बाद वहां पर किसी पाईप में दिक्कत आ गई तो उस फुटपाथ को दोबारा से तोड़ना पड़ेगा। यह जो दिनोट गेट से रेलवे स्टेशन भिवानी की सड़क है यह 1300 मीटर लम्बी है। यह पोसीबल नहीं हो सकता है कि कहीं पर तो फुटापाथ बना दें और कहीं पर छोड़ दें। अगर ऐसा करते हैं तो उसकी स्मीटरी नहीं रहेगी। मैं अपने किसी अधिकारी को इनके साथ वहां पर भेज दूंगा और ये वहां पर मौके पर देख लें कि कंजैशन है कि नहीं है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कैथल में पेहवा चौक से करनाल बाई-पास तक बहुत चौड़ी सड़क है। वहां पर सड़क के दोनों तरफ एस०पी०, डी०सी० के रैजीडैंस और सरकारी दफ्तर हैं। वहां पर कोई दुकानें नहीं हैं। क्या मंत्री जी उस सड़क पर डिवाईडर और फुटपाथ बनाने के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के विचार कर लिए गए हैं, जो वहां पर फालतू पेड़ थे उनको भी कटवा दिया गया है। सिर्फ इसमें पैसा सैंक्शन होना रह गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस काम के लिए पैसा दे दें और यह बताएं कि इस काम को कब तक शुरू करवा देंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया है इस बारे में माननीय सदस्य सैप्रेट नोटिस दे दें। मैं इनको इस बारे में यह बताना चाहूंगा कि

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
यह जो इन्होंने डिवाईडर और फुटपाथ बनाने की बात कही है इस बारे में हम एग्जामिन करवा लेंगे और जो कुछ भी संभव होगा वह हम करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे साथी भारद्वाज जी ने बताया है कि भिवानी में फुटपाथ न होने की वजह से कंजैशन है। अगर वहां पर फुटपाथ बन जाएगा तो लोग सामान उस पर रख लेंगे, जिसकी वजह से वहां पर कंजैशन कम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ये फुटपाथ सामान रखने के लिए होते हैं या पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है। लेकिन वहां पर जो दुकानदार होते हैं वे अपना सारा सामान फुटपाथ पर रख लेते हैं। अगर दुकानदार सामान फुटपाथ पर रख लेंगे तो गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी होने लग जाएंगी जिससे पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। इस बारे में विभाग को चाहिए कि वे वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था पैदा न होने दें। इसमें सरकार के लोकल बॉडी के अधिकारियों को कार्यवाही करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज लोगों को यह आदत पड़ रही है कि वे सामान फुटपाथ पर रख लेते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ये सड़कों के साथ फुटपाथ बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाता है कि वे कहां-कहां पर बनाए जाएंगे और क्यों बनाए जाएंगे? अगर कहीं पर नहीं बनाए जाएंगे तो क्यों नहीं बनाए जाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैंने पहले भी एक क्वैश्चन के जवाब में डिटेल में यह बताया था कि नॉर्मल सिटी के अंदर फुटपाथ बनाने का काम हमारा नहीं है बल्कि यह काम लोकल बोडीज विभाग का है। स्पीकर सर, जहां पर हमारे विभाग की रोडज हैं वहां यदि इस प्रकार की मांग आती है जैसे रैजीडेंशियल एरिया हो जहां पर रोड काफी चौड़ी हो, जहां पर आसपास दुकानें न हों और जिस पाथ पर आने जाने में दिक्कत नहीं हो तथा जहां पर हम बना सकते हैं वहां पर हमने फुटपाथ बनवाये भी हैं इसलिए यह केस टू केस डिपैंड करता है। जहां पर कंजैशन होता है अगर हम वहां पर फुटपाथ बनवा दें तो इससे और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। स्पीकर सर, फर्ज करो कि कहीं पर रैजीडेंशियल एरिया है वहां पर तो हमें यह काम करने में दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कहीं पर आमने सामने दुकानें हैं और वहां पर कंजैशन है तो वहां हमें दिक्कत आती है। वैसे ये फुटपाथ लोकल बॉडीज विभाग बनाता है हमारा यह काम नहीं है। लोकल बॉडीज विभाग इनको अगर बनवाता है तो वह ही इनको बनवाने की व्यवस्था करे। लेकिन अगर हम इनको सब जगह बनवा दें तो इससे कंजैशन और ज्यादा हो जाएगी।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस सड़क का आधा पोर्शन ही ऐसा है जहां पर यह काम होना है। दिनोद गेट से लेकर रेलवे गेट तक, कृष्णा कालोनी सब्जी मंडी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक तो कोई कंजैशन नहीं

है वहां पर वह सड़क चौड़ी है वहां पर किसी भी प्रकार गाड़ियों के खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मंत्री महोदय इस बारे में बताएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा मैंने बताया कि हमारे अधिकारी इनसे इस बारे में बातचीत कर लेंगे । हमें कोई दिक्कत नहीं है । जहां पर कंजैशन की समस्या नहीं है वहां पर फुटपाथ बनाने के बारे में हम विचार कर लेंगे लेकिन सारे मामले को ऐग्जामिन करवाने के बाद ही मैं इस बारे में कोई आश्वासन दे पाऊंगा ।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं कई बार अधिकारियों के साथ गया हूं । उन्होंने कहा है कि हम यह बना देंगे । उन्होंने इस बारे में फाईल बनाकर भी नीचे से ऊपर भेज दी थी । मैंने इस बारे में ई०आई०सी० से पता किया था । उनका कहना था कि यह काम तो एस०ई० ही कर सकता है क्योंकि यह पावर एस०ई० को ही है । अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैंने पता किया तो पता चला कि उस समय के कमिश्नर श्री धर्मबीर जी के दफ्तर में यह फाईल थी, उस समय मैं उनके दफ्तर में चक्कर काटता रहा लेकिन वह फाईल नहीं मिली । अगर उस वक्त यह फाईल मिल जाती तो यह काम तभी हो जाता । स्पीकर सर, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर वह काम रुका पड़ा है । इसके बन जाने के बाद शहर की सुंदरता और बढ़ेगी तथा लोगों को भी इसका फायदा होगा और इसके अनेक लाभ भी होंगे ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर फिजीबल होगा तभी मैं इस बारे में कुछ बात कह सकूंगा । जब मैंने यहां पर एक बात कही है तो फाईल मेरे पास जरूर आएगी ।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, फाइल तो डिपार्टमैंट के पास है । मैं चाहूंगा कि अगर मंत्री जी उस फाईल को ढूंढवाकर ऐग्जामिन करवा लें तो इसके बाद सारी चीजें क्लीयर हो जाएंगी ।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, मंत्री जी ने ऑन दि फ्लोर ऑफ दी हाउस ऐश्योरेंस दी है कि वे इस मामले को ऐग्जामिन करवा लेंगे और ओफिसर्ज से सारा पता करवाएंगे । यदि फिजिबिलिटी हुई तो वे इस काम को करवा देंगे । डाक्टर साहब, क्या यह फाईल आपके दफ्तर में तो नहीं रखी है?

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : नहीं सर, वह डिपार्टमैंट के पास है ।

Construction of Stadium at Kaithal

***841. Shri Shamsher Singh Surjewala :** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state :—

(a) whether a stadium is under construction at Kaithal, if so, the stage of the work upto 31.01.2008 ; and

(b) the details of the total cost of the project together with the time by which it is likely to be completed ?

Minister of State for Forest (Smt. Kiran Choudhry) :

(a) Yes, sir. The District Level Sports Stadium is being constructed at village Patti Afgan near Kaithal Town. In the 1st phase, construction of boundary wall has already been started and as on 31.1.2008 work has been completed on three sides. The balance work on boundary wall will be completed within two months.

(b) The project is likely to cost Rs. 750.00 lacs. However, it is not possible to indicate the time frame for completion of the project at this stage.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, हमने यह बीस एकड़ प्राईम लैंड फ्री में स्पोर्टस डिपार्टमैंट को दिलवायी है । इस जमीन की बाजारी कीमत तकरीबन एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगी । बहुत हिम्मत लोगों ने की है, हौसला दिखाया है । मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना है, इसके अंदर सरकार ने कौन-कौन से इनडोर और आउटडोर गेम्ज प्लान किए हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि स्पोर्टस फैसेलिटीज को हमारी सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है । इसके अंदर भी बहुत सारी ईंफ्रास्ट्रक्चर फैसेलिटीज हम देने जा रहे हैं and by the time it is completed, it will have 6 to 8 lanes in the 4 metres grass running track, two indoor halls of size not less than 40×25 metres, swimming pool, room with toilet, showers etc., cross ventilation of multigen bay, training and physical conditioning equipment, sports hostel with 150 beds, with girls wing of 50 beds, quarters for managers and coaches, hockey ground, football ground, diving pool, volleyball cocks, basketball cocks, field for locally popular games, which is not included in the above games, जैसे कबड्डी और खो-खो । As, I said one or two playing fields for indigenous games like Kabaddi, Kho-Kho etc. will be provided alongwith the facilities like human performance laboratories, internal roads, boundary walls, water supply, electricity, office store, toilets etc. यह पूरा का पूरा इंडीजिनस प्लान है और इसमें सारी की सारी फैसिलिटीज होंगी ।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इसके लिए जो फंड हैं उसके बारे में इन्होंने जवाब दिया है-- "However, it is not possible to indicate the time frame for completion of project." इसके लिए फंड जो हैं जो इस वक्त नहीं हैं । क्या अपने डिपार्टमैंट से या हुडा से इस काम के लिए फंड प्रोवाइड करवाने का प्रबन्ध करेंगे ताकि यह काम हो जाए?

Smt. Kiran Choudhry : Mr. Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Member that we have already provided Rs. 19 lakhs for the first phase and three side boundaries have been completed only. Only one side has been left. The Chief Architect has already submitted his plan and as soon as the estimates are received from the Panchayati Raj Department, we will be completing the others.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा पैतृक गांव घोघड़ीपुर है जो कि निसिंग ब्लॉक में पड़ता है ।

इसमें स्टेडियम की प्रपोजल थी बाद में यह पास हो गया था और टैंडर भी हो गए थे, Just in one day, it vanished from the total scheme of things. मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से रिफरैंस भी भेजा है लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह पास हो गया है क्योंकि हमारे गांव में वह जमीन यूं की यूं पड़ी है क्या विभाग इस बारे में एश्योर करेगा कि वहां स्टेडियम बनेगा?

Smt. Kiran Choudhary : Mr. Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Member that we have already constructed about 155 block level stadiums and as yet we have not received any of these requisitions. If we will receive, we will definitely look into it.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : इसके तो टैंडर हो गए हैं और किसी ब्लॉक में नहीं बना है, यहीं बनना है।

श्रीमती किरण चौधरी : आपके प्रश्न का मैं बता देती हूं। यह स्टेडियम करनाल ब्लॉक में पड़ता है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : करनाल में नहीं बल्कि निसिंग ब्लॉक में पड़ता है।

Smt. Kiran Choudhary : All blocks have been covered in Karnal. एक स्टेडियम हर एक ब्लॉक में बनाना है that thing has already been done.

Shri Tejinder Pal Singh Mann : Sir, this was passed. This was totally regularized. Tenders were called. Hon'ble Chief Minister has also made the reference about this.

श्रीमती किरण चौधरी : इसको दिखवा लेंगे। अगर पास हो गया होगा तो दिखवा लेंगे। वैसे सारे ब्लॉक्स में हम कर चुके हैं लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम जरूर दिखवा लेंगे और इसकी इजाजत लेकर इस काम को करवाएंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो हमारे सरकारी कोच हैं वे स्टेडियम में बच्चों की टीम तैयार नहीं कराते और न ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं। जो बड़े-बड़े स्कूल्ज हैं जो ऐफोर्ड कर सकते हैं वहां पर जाकर वहां से ही पैसे लेते हैं और सरकार से भी पैसे लेते हैं और वहां जाकर के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जबकि इनको स्टेडियम में या सरकारी स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस बारे में सरकार का एक सर्कुलर है उसको मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है कि जहां बड़ी टीम उपलब्ध हो वहां हमारे कोच जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं उसी सर्कुलर का वे मिसयूज करते हैं। मेरे घर के पास एक सरकारी स्कूल है वहां पर ये कोच बहुत ही कम जाते हैं। क्या मंत्री महोदया इस बात से वाकिफ हैं?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मैंबर साहिबा को बताना चाहूंगी कि इस बारे में इन्होंने मुझसे पहले भी बात की थी और हमने जांच पड़ताल भी की है। आप जहां पर बताएंगी कि ऐसा कहीं हो रहा है तो उस पर भी नजर रखेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, करनाल में किसी भी स्पोर्टस स्टेडियम में न तो योगा का और न ही बास्केट बाल और न ही किसी दूसरे खेल के कोचिज स्टेडियम में जाते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय सदस्या इस बारे में लिखित में भिजवा दें हम उन के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने प्रत्येक गांव में स्पोर्टस स्टेडियम बनाये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि स्टेडियम तो हर गांव में तैयार हो गये हैं लेकिन न तो किसी कोच की नियुक्ति की है, न किसी माली की नियुक्ति की है जो उन स्टेडियमों की देखरेख कर सकें। इसलिए उन स्टेडियमों की हालत खराब होती जा रही है। क्या कोचिज और माली की नियुक्ति का प्रबन्ध इन स्टेडियमों में करने का काम किया जायेगा ताकि बच्चों को सुविधा मिल सके।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह अलग प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारे पास इस समय 21 कोचिज की वैकेन्सिज हैं इनको भरने के लिए हम एडवर्टाईजमेंट करने जा रहे हैं। जहां तक इन स्टेडियमों की देखरेख के लिए माली, चौकीदार और स्वीपर का सवाल है, इनके लिए जल्दी ही पोलिसी डिसीजन लिया जा रहा है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि हर ब्लॉक में एक-एक स्टेडियम बनाने का प्रावधान सरकार ने किया है। हांसी के दो ब्लॉक हैं, क्या वहां पर कोई स्टेडियम बनाने के लिए कोई मामला सरकार के विचाराधीन है, अगर है तो वह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। हांसी शहर में भी स्टेडियम की जरूरत है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हर ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाने का काम किया है। अगर किसी जगह जरूरत पड़ी तो अगली प्लान में इसके बारे में विचार कर लिया जायेगा।

आई०जी० शेर सिंह : स्पीकर महोदय, मेरे हल्के जुलाना ब्लॉक में एक स्टेडियम सैंक्शन हुआ था और लगभग दो साल हो गये हैं लेकिन वह अब तक आधा ही बना है और बीच में ही रुका पड़ा है। 50 लाख रुपये सरकार द्वारा हर स्टेडियम बनाने के लिए मंजूर किये गये थे। मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि यह स्टेडियम कब तक कम्पलीट हो जायेगा? क्या मंत्री महोदया इस बारे में एक्शन लेंगी?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जुलाना हल्के में नन्दगढ़ में स्टेडियम बन रहा है उसको हम जल्दी ही कम्पलीट करवा देंगे।

Selection of Environment Engineer

***886. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Environment be pleased to state :—

(a) whether any case of fraudulent selection and appointment of Environmental Engineers in the Haryana State Pollution Control Board has been detected during the period 2004 to 2007 ; and

(b) if so, the action taken against the delinquents ?

Minister of State for Forest (Smt. Kiran Choudhary) :

(a) Yes, Sir.

(b) FIR No. 12 dated 04-09-2007 was lodged at Police Station, State Vigilance Bureau, Panchkula against all the accused numbering eight.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि यह जो एन्वायर्नमैंट इंजीनियर्ज विभाग ने लिये हैं इसके लिए कितनी एप्लीकेशंज आई थी, उनमें से कितने कंडीडेट्स इलीजिबल शॉर्ट लिस्ट किये और जो इन्टरव्यू लिया वह कितने कंडीडेट्स का लिया?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 4 एन्वायर्नमैंट इंजीनियर्स की नियुक्ति के लिए रिक्विजीशन भेजी गई थी जिसके लिए 132 एप्लीकेशंज प्राप्त हुई थी उसके बाद इन पोस्टों को फिल अप किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं था कि शार्ट लिस्ट 120 किए हों और इंटरव्यू के लिए 121 कैंडीडेटस को बुलाया हो। मंत्री महोदया अपने नोट फ़ोर पैड को चैक कर लें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं चैक करके माननीय सदस्य को बता दूंगी, I don't have the information right now.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई है क्या यह सही है कि चौटाला जी के राज में प्रदेश के पर्यावरण को खराब करने के लिए जान-बूझकर के अयोग्य उम्मीदवारों को रिश्वत लेकर के, पैसा लेकर के जिनकी उम्र ज्यादा थी उनको इस विभाग में भर्ती किया गया था? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 4.9.2007 को यह एफ०आई०आर० दर्ज कराई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से आश्वासन चाहूंगा कि एफ०आई०आर० दर्ज कराने से काम नहीं चलेगा जो लोग उस वक्त इस भर्ती में शुमार थे। इन भर्तियों को करने में जो शामिल थे वे हैं उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। जिनको ये नियुक्तियां दी गई हैं आज उनकी क्या स्थिति है क्योंकि एफ०आई०आर० दर्ज करने से काम नहीं चलता? क्या मंत्री जी बताएंगे कि संविधान की धारा 311 या किसी भी सरकार के विभाग के कानून के मार्फत जो ऐसी धोखे से नौकरियां ली गई हैं उनको तुरन्त प्रभाव से नौकरियों से बाहर निकाला जाएगा और जो सैलरीज इन्होंने ली हैं उनको उनसे वापिस वसूला जाएगा? मंत्री जी इस बारे में बताने की कृपा करें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इस केस में विजीलैंस इन्कवायरी इंस्टीच्यूटिड है और तीन आदमी जिनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज की गई है उनको सस्पैंड कर दिया गया है। इन्कवायरी में आगे जो

[श्रीमती किरण चौधरी]

भी निकलेगा उसके अनुसार सख्ती से कार्यवाही की जाएगी क्योंकि जो गलत काम किया गया है उसमें किसी को कतई माफ नहीं किया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, विभाग ने एक तरफ तो इनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करा दिए हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब विभाग के नोटिस में आ चुका है कि ये नियुक्तियां ही गलत हैं तो इसमें विजीलैंस इन्क्वायरी क्या करेगी। यह तो लटकाने वाली बात है। क्या मंत्री महोदया इस बात के लिए आश्वस्त करेंगी कि जब ये नियुक्तियां ही गलत हैं तो न केवल उनको नौकरियों से हटायेंगे बल्कि जिन्होंने नौकरियों के लिए उनको नियुक्ति पत्र जारी किए हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी क्योंकि जो उस वक्त के अधिकारी थे और जो जानते थे कि इनकी उम्र ज्यादा है या ये अयोग्य हैं फिर भी उनको नियुक्ति पत्र दे दिए तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता चुकी हूं कि यह विजीलैंस इन्क्वायरी पूरी तरह से इंस्टीच्यूटिड है और इस इन्क्वायरी में जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाएगी। जहां तक विभाग का सवाल है, उन तीनों को हम सस्पैंड कर चुके हैं और जिन्होंने इस बात को प्वांयट आउट नहीं किया उनको भी शो काज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको चार्ज शीट कर दिया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इन नियुक्तियों में जो एस०सी०-ए और एस०सी०-बी कैटेगिरी के लिए स्थान थे क्या उन स्थानों की नियुक्तियां और उनका सिलैक्शन इन कैटेगिरीज के मुताबिक हुए हैं और अगर नहीं हुए तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय जो एस०सी०-ए कैटेगिरी है one genetleman Sh. Kapoor Singh who was belonged to S.C., उसको छोड़ दिया गया है क्योंकि 5 साल का एज रिलेक्सेशन का प्रावधान सरकार के सर्विस रूल्ज में है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने दलित और गरीब व्यक्ति जो योग्यता रखते हैं उनके साथ अन्याय किए हैं और यह बात मंत्री महोदया ने बताई भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जो ये नियुक्तियां इन्होंने की हैं और इसमें अयोग्यता पाई और जैसा एस०सी०-ए कैटेगिरी के बारे में बताया गया है कि इन्होंने 8 ऑफिसर्ज के खिलाफ मुकद्दमें दर्ज किए हैं तो ये क्या फ्राड मानते हैं और जो एफ०आई०आर० दर्ज हुई है उसमें क्या फ्राड है?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, फ्राड यह है कि जब एक्वीजिशन नोटिस भेजा गया तो जो उम्र थी that was between 17 years to 40 years. लेकिन जब उनकी भर्ती की गई उस समय उनकी उम्र 40 साल से ऊपर थी, उस समय सरकार ने लिखित में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा कि इनकी नियुक्तियां कराई जाएं, अमरजैंसी लैवल पर कराई जाएं। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यह गलत काम हुए हैं इसलिए विजीलैंस इन्क्वायरी इंस्टीच्यूटिड हुई है। जो गलत काम हुए हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही हो रही है। रिक्रूटमैंट्स जिनकी की गई है उनकी सस्पैंशन कर दी गई है और

इन्क्वायरी में जो भी निकलेगा उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी ताकि आने वाले समय में यह काम दोबारा न हो पाए और इस केस पर हमारी पूरी नजर है।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की सिलैक्शन हो और चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सिलैक्शन हो इनमें जो तथ्य सदन के सामने आए हैं इन सब में हरिजनों के साथ ज्यादती की गई है तो क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि वह सरकार और उस वक्त के मुखिया एंटी हरिजन थे?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुलाना जी ने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। But it is very obvious otherwise these things could not have been done.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुलाना जी यदि उनकी पार्टी में होते तो इनको स्वयं ही पता लग जाता कि वे कैसे लोग हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने यह मान लिया है कि जिनकी भर्ती की गई थी उनकी उम्र ज्यादा थी और एस०सी० कैटेगरी को भी इग्नोर किया गया। क्या मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगी कि तुरंत प्रभाव से पहले उनकी नौकरी खत्म की जायेगी और बाद में विजीलैंस इन्क्वायरी चलती रहेगी?

तारांकित प्रश्न संख्या - 842

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री एस०एस० सुरजेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Damage Caused Due to Severe Cold

***859. Dr. Sita Ram @**
Shri Radhey Shayam Sharma
Shri Somvir Singh
Shri Naresh Yadav : Will the Minister of State for Revenue and Disaster Management be pleased to state whether it is a fact that mustard and different vegetable crops in the State have been damaged due to severe cold/frost during financial year 2007-2008 ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the affected farmers ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : जी हां। तथापि वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि सर्दी/पाले के कारण हुआ नुकसान आपदा राहत कोष के प्रावधान के अधीन कवर नहीं होता।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, इस बार बहुत भारी ठंड पड़ी है जिसकी वजह से किसानों की फसलों को विशेषकर सरसों, गेहूं और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है तथा किसानों को काफी वित्तीय घाटा हुआ है। क्या सरकार उन किसानों को कम्पन्सेट करने के लिए विचार कर रही है जिनकी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान ठंड की वजह से हुआ है?

@ Put by Dr. Sita Ram

श्रीमती सावित्री जिंदल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो आपदा राहत कोष की स्कीम कार्यान्वित की गई है उसमें केवल चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना तथा महामारी से फसलों के हुए नुकसान से प्रभावित व्यक्तियों को ही शीघ्र राहत प्रदान करने का प्रावधान है। शीत लहर तथा पाले से हुआ नुकसान इस स्कीम के अधीन कवर नहीं होता है। लेकिन जनवरी व फरवरी, 2008 में फसलों को शीत लहर से काफी मात्रा में हुए नुकसान के मध्यनजर दिनांक 27.2.2008 को हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने केन्द्रीय गृह मंत्री तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री जी को शीत लहर को आपदा राहत कोष स्कीम के अधीन प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। इसके साथ-साथ यह भी अनुरोध किया गया है कि हरियाणा राज्य को कम से कम 125 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाए ताकि प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोष स्कीम के अनुसार राहत दी जा सके।

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जैसे मौजूदा सरकार ने प्रयास किया है कि शीत लहर और पाले से फसलों को होने वाले नुकसान को भी प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया जाये। इस बारे में हमारे एम०पी०, चौधरी दीपेन्द्र हुड्डा जी भी प्रधान मंत्री जी से मिले हैं। क्या पिछली सरकार के एम०पीज० ने उस समय की केन्द्र की एन०डी०ए० सरकार से मिलकर कोशिश की थी कि शीत लहर तथा पाले से जो फसलों को नुकसान होता है उसे प्राकृतिक राहत आपदा कोष में शामिल किया जाये? (विघ्न)

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में और हमारे एरिया में जो बागवानी के पौधे थे उनको और सरसों आदि की फसलों को ठंड से भारी नुकसान हुआ है। क्या मंत्री महोदया ठंड से हुए फसलों के इस नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने का आश्वासन देंगी?

श्रीमती सावित्री जिन्दल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि जैसा मैंने अभी बताया है कि हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को शीत लहर और पाले को आपदा राहत कोष स्कीम में शामिल करने का अनुरोध किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा शीत लहर और पाले को आपदा राहत कोष में शामिल कर लिये जाने के बाद ही प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour is over.

सदन की एक समिति का गठन

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, मैंने 18.03.2008 को एक क्वैश्चन के जवाब में बताया था कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इरीगेशन डिपार्टमैंट की बहुत सारी बेशकीमती जमीन अपने खास और चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से बेची गई थी। इस बारे में मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह टोटल 27 कैनाल रैस्ट हाउसिज़ की जमीन बेची गई थी जो कि तकरीबन 127.16 एकड़ जमीन थी और जिसको मात्र 3.83 करोड़ रुपये में बेच दिया गया था।

इसके साथ-साथ इरीगेशन डिपार्टमैंट की 776.78 एकड़ जमीन थी जिसमें कैनाल रैस्ट हाऊसिज भी इंक्लूडिड हैं ये टोटल 145 साईट्स थी जोकि मात्र 30.78 करोड़ रुपये बेच दी गई। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आते ही जब मैंने सिंचाई मंत्री के रूप में कार्यभार सम्भाला और तत्पश्चात् जब 05 अप्रैल, 2005 को मैं सिंचाई भवन में अपने अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ले रहा था तो मीटिंग के दौरान जब सोनीपत और कैथल के 8 रैस्ट हाऊसिज की ऑक्शन की बात मेरे नोटिस में आई तो मैंने उसी वक्त तुरन्त प्रभाव से इन तथाकथित 8 रैस्ट हाऊसिज की ऑक्शन पर रोक लगा दी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कई ऐसे लकूनाज़ हैं जिसके तहत इसमें ऐसे बहुत से रैस्ट हाऊसिज थे जिनको लगभग रिजर्व प्राईस पर ही बेच दिया गया। इनमें मलिकपुर कैनाल रैस्ट हाऊस, करनाल की रिजर्व प्राईस रखी गई 2.20 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसे 2.53 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेच दिया। इसी प्रकार से पोपड़ा कैनाल रैस्ट हाऊस, करनाल की रिजर्व प्राईस थी 3.07 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसे 3.44 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक्शन कर दिया, झानी भट्ठा, करनाल की रिजर्व प्राईस रखी गई 2.83 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसे 3.14 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक्शन कर दिया गया, डाटा रैस्ट हाऊस, हिसार की रिजर्व प्राईस रखी गई 1.90 लाख रुपये प्रति एकड़ और दो 2.30 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक्शन कर दिया गया, इसी प्रकार से थुराना रैस्ट हाऊस, हिसार की रिजर्व प्राईस रखी गई 1.70 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसे 1.76 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक्शन कर दिया गया, इसी प्रकार से हिसार के अन्दर जीवड़ा का कैनाल रैस्ट हाऊस है उसकी रिजर्व प्राईस 1.75 लाख रुपये प्रति एकड़ रखी गई और उसको 1.78 लाख रुपये प्रति एकड़ में बेच दिया गया। इसी प्रकार से झज्जर में धांधलान है उसकी रिजर्व प्राईस 1.35 लाख रुपये प्रति एकड़ रखी गई और उसे 1.53 लाख रुपये प्रति एकड़ में पिछली सरकार ने ऑक्शन करवा दिया, इसी प्रकार से जीन्द के अन्दर खरल रैस्ट हाऊस की रिजर्व प्राईस रखी गई 2.25 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसको 2.29 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक्शन कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इससे यह जाहिर होता है कि जो 27 रैस्ट हाऊसिज थे उनको इन्होंने अपने फायदे के लिए कौड़ियों के भाव बेच दिया। वैसे तो इन्होंने 35 रैस्ट हाऊसिज एवं कैनाल रैस्ट हाऊसिज को बेचने का लक्ष्य रखा था लेकिन उनमें से हमारी सरकार ने आते ही 8 रैस्ट हाऊसिज की ऑक्शन को समाप्त कर दिया था। यह मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहता हूं। बाकी इसमें आगे निर्णय आपको लेना है कि ऐसा करके जिन लोगों द्वारा इस प्रकार की अनियमितताये की गई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाये। ऐसा करके पिछली सरकार में यह हुआ था कि इन्होंने कौड़ियों के भाव में जमीनें बेच दी थी जो कि स्टेट के लिए असैट्स होती हैं और यह बात भी मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि उस समय प्रदेश के ऊपर ऐसा क्या वित्तीय संकट आ गया था कि इस प्रकार से इन्होंने रैस्ट हाऊसिज और सरकार की जो बहुत ही कीमती जमीन थी उसको मात्र थोड़े से पैसों में अपने चहेतों को और इंडीविजुअल लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिजर्व प्राईस से थोड़े-थोड़े से पैसे बढ़ाकर बेच दिया। मैं इससे संबंधित सारा रिकॉर्ड आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें यमुनानगर और करनाल के अन्दर दो साईट्स थी जिनकी रिजर्व प्राईस 1.05 लाख रुपये प्रति एकड़ रखी गई थी और रिजर्व प्राईस पर ही यानि 1.05 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ही बेच दिया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

से इन्होंने जो अनियमिततायें की उसके हमारे पास सारे आंकड़े हैं मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी भारी कमियां रही हैं। सर, यह मामला जब हमारे पास आया उसी वक्त हमने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। सरकार के असैट्स इन्होंने इस प्रकार से औने-पौने दामों में अपने चहेतों को बेचे हैं। कहीं पर तो रिजर्व प्राईस पर ही बेच दिये गये और कहीं पर दो-चार हजार रुपये ऊपर करके बेच दिये गये। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा घोटाला सिंचाई विभाग में किया गया है। इसी प्रकार से बी० एण्ड आर० विभाग में भी कुल 28.65 एकड़ जमीन सरप्लस दिखा कर ऑक्शन द्वारा मात्र 87.94 लाख रुपये में बेच दी गई। उसमें से कुछ जमीन एन०जी०ओज० को भी दी है। 6 साईट्स ऐसी हैं जो 10.80 एकड़ की हैं उसको भी इन्होंने ऑक्शन दिखा कर बेच दिया है। एक जमीन 0.35 एकड़ झांसी में एक एन०जी०ओ० जाट सभा को दी है। अध्यक्ष महोदय, ये सारे आंकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार की गड़बड़ियां पिछली सरकार ने की हैं। ये तो सिर्फ थोड़ी सी बातें सामने आई हैं अगर हम इसकी तह तक जायेंगे तो और विभागों में भी इसी प्रकार से घपले उजागर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ये सारे तथ्य आपके सामने रख दिये हैं अब निर्णय आपको करना है कि आप कोई हाउस की कमेटी गठित करेंगे या कोई और निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसमें सरकार क्या एक्शन लेना चाहती है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो एक डिप्टी कमीश्नर और एस०डी०एम० की कमेटी बनाकर देने की कोशिश की थी। मैंने तो आपके सामने तथ्य रख दिये हैं। अब आपको निर्णय करना है कि हाउस कमेटी बनाई जाये या कोई और निर्णय करना है। मेरे ख्याल से तो हाउस कमेटी बनाना ही बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष : यह एक एग्जिक्यूटिव मामला है। आप अपने लेवल पर ही कोई कमेटी बनाकर यह निर्णय करें कि जितनी ऑक्शन हुई हैं क्या उनमें ओपन ऑक्शन हुई है, क्या कोई कंसीलमैंट उसमें हुई है, क्या उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई तथा क्या-क्या कारण थे, कौन-कौन आदमी किससे जुड़े हुए थे तथा क्या आपकी लीगलिटी में ये ऑक्शन्स कैंसिल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनके सारे केसिज की इन्क्वायरी सी०बी०आई० कर ही रही है।

श्री अध्यक्ष : स्टेट की इनवैस्टीगेशन ऐजेन्सीज हैं, उससे आप यह इन्कवायरी करवा सकते हैं। जो आपकी स्टेट ऐजेन्सीज हैं उनसे करवायें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर लगी है कि रेवाड़ी जिले में मुकन्दपुर बसई एक गांव है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे हैं पहले उनकी बात सुन लें।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, एक और विषय पर चर्चा चल रही थी और श्री मांगे राम गुप्ता जी ने तथा कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने उस समय कहा था कि हम पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने तो पूरी

जानकारी एकत्र करके सदन के सामने रख दी है। अध्यक्ष महोदय, because the issue was raised in the House श्री मुलाना साहब ने, स्थानीय निकाय मंत्री जी ने और दूसरे कई साथियों ने भी यह मुद्दा उठाया था। यह पूरे हाउस का ही कंसर्न था। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न उठाये गये थे। पहला तो यह था कि कौन-कौन सी वे जमीनें हैं जिनको इन्होंने औने-पौने दामों पर अपने चहेतों को ऑक्शन करवाया है? चाहे वह सिंचाई विभाग की थी, चाहे बी० एण्ड आर० विभाग की थी, चाहे स्थानीय निकाय की थी या पंचायती राज संस्थानों की जो चौधरी देवीलाल इंस्टीच्यूशंस को फ्री में दे दी गई या औने-पौने दामों में ऑक्शन कर दी गई। इसलिए Sir, this was the concern of the House and for that reason Minister has also made a statement thereon. I will request you that हाउस कमेटी बना दें तथा डिपार्टमैंट को सम्मन भेज दें, पूरी रिपोर्ट आ जायेगी और उसके बाद जो हाउस निर्णय करेगा, सरकार उसके ऊपर कार्यवाही भी करेगी। पहले सभी विभागों की रिपोर्ट आ जाएगी और हाउस की एक कमेटी आप बना दें। स्पीकर सर, वह सारी जानकारी उसके अन्दर आ जाएगी। आदरणीय मुलाना साहब यहां पर बैठे हुए हैं इनके नेतृत्व में हाउस की एक कमेटी का गठन हो जाए। जो सदस्य आप उचित समझें उनको इस कमेटी के सदस्य बना दें। अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने यह मुद्दा रेज किया था वे इस कमेटी के अन्दर एक मैम्बर हो जाएं और दूसरे माननीय साथी इस कमेटी में आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के साथी आ जाएं और लोक दल से भी साथी इस कमेटी में आ जाएं। अध्यक्ष महोदय, आप इस कमेटी में इन्दौरा साहब को ले लें या श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को ले लें ताकि वे अपना पक्ष भी कमेटी के अन्दर रख सकें।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब जिन कमेटियों के सदस्य हैं उनकी मीटिंगों में भी नहीं आते हैं। बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की किसी भी मीटिंग में वे आज तक नहीं आए। हाउस की ही एक और कमेटी बनी थी वे उस कमेटी की मीटिंग में भी कभी नहीं आए। चाहे कितनी भी कमेटियों में उन्हें ले लें अगर उन्होंने मीटिंग में नहीं आना है तो कमेटी में लेने का क्या फायदा है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कल भी वे हाजिरी लगा कर चले गए और उस कमेटी में भी नहीं आए जो लोन वेवरज के लिए आपने आदरणीय श्री मांगे राम गुप्ता जी की अध्यक्षता में बनाई थी।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा ईशू है और इसके बारे में सभी को पता है। आम पब्लिक को भी पता है कि किस प्रकार से अपनी सरकार के वक्त में इन लोगों ने अपने चहेतों या रिश्तेदारों या उन लोगों के द्वारा जो इनसे मिलते-जुलते रहते थे, सरकारी प्रापर्टी को खुर्द-बुर्द किया है। मेरा निवेदन यह है कि आप कमेटी तो बना दें लेकिन उस कमेटी का रिजल्ट दिखना चाहिए। अगले हाउस के सैशन से पहले इस कमेटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिए और डिपार्टमैंट से भी पूरी रिपोर्ट आ जानी चाहिए और उस पर कोई न कोई लीगल ऐक्शन भी होना चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक मुद्दे की बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से विभाग अपनी जरूरत के अनुसार

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
जमीन खरीदता भी है और बेचता भी है। विभागों में इस तरह की परम्पराएं और नियम भी हैं कि विभाग अपनी आवश्यकता के मद्देनजर अगर कहीं पर किसी जमीन की यूटीलिटी नहीं है तो उस जमीन को बेच देता है। अगर जमीन की जरूरत है तो वह जमीन खरीद लेता है। अगर मंत्री जी को ऐसा लगता है कि कहीं पर ऐसी कोई अनियमितता हुई है तो वे इसकी विभागीय जांच करवा लें। वे अपने आप को इतना असहाय क्यों मान रहे हैं? वे स्वयं मंत्री हैं, इरीगेशन विभाग के मंत्री तथा पी०डब्ल्यू०डी० विभाग के मंत्री यह बताएं कि वे इतने असहाय क्यों हैं, वे इस बारे में विभागीय जांच करवा कर सारे मामले का पता करवा सकते हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, इसमें विभागीय जांच हो जाए तो सारा मामला सामने आ जाएगा और दूध-का-दूध, पानी-का-पानी हो जाएगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय इन्दौरा साहब से यह जानना चाहता हूं कि ये हाउस की कमेटी से घबराते क्यों है, ये हाउस की कमेटी से डरते क्यों हैं? ये इस कमेटी के सदस्य बनें तो सारी बात सामने आ जाएगी। अगर हाउस की कमेटी बन जाती है तो लोक दल के साथी और इन्दौरा जी को इतनी घबराहट क्यों हो रही है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात रखी है कि सरकार जमीन बेचती भी है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि सरकार के ऊपर क्या ऐसा वित्तीय संकट आ गया था सरकार को इतना भारी घाटा हो गया कि सरकार ने जमीन बेचने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जमीनें दी भी हैं। कई दफा धर्मशाला बनाने के लिए, कॉम्यूनिटी सैंटर बनाने के लिए सरकार जमीन देती है लेकिन प्राईवेट लोगों को जमीन देना और वह भी रिजर्व प्राईस पर ऑक्शन करके जमीन देना ठीक नहीं था। रिजर्व प्राईस से ऑक्शन की राशि में कुछ न कुछ तो फर्क होना चाहिए लेकिन जमीन को रिजर्व प्राईस पर ऑक्शन में बेच देना या रिजर्व प्राईस से 3-4 हजार रुपये ऊपर ऑक्शन कर देना शक जाहिर करता है। स्पीकर सर, सही बात तो यह है कि इनकी नीयत में खोट है। कोई भी आदमी पब्लिक यूटिलिटी के लिए किसी संस्था को जमीन देता है, पंचायत भी जमीन देती है और धर्मशाला वगैरा बनाने के लिए गवर्नमैंट भी जमीन दे देती है। कई सभाओं को भवन के लिए भी सरकार जमीन दे देती है लेकिन यह जमीन पब्लिक परपज़ के लिए होती है लेकिन इन्होंने तो इन्डिविजुअल जमीनें दी हैं। इसके बारे में जो बात माननीय सुरजेवाला जी ने रखी है कि हाउस की एक कमेटी आप गठित कर दें ताकि जो सही बात है वह सामने आ सके। आप इस कमेटी को टाईम बाउंड कर दें कि इतने पीरियड में यह अपनी रिपोर्ट दे देगी।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल सदस्यगण, जैसे मलिक साहब का सुझाव था कि नैक्सट सैशन तक इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए इसमें मुलाना साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन कर देते हैं जो अगले सैशन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नैक्सट सैशन तक तो बहुत समय हो जाएगा। यदि यह रिपोर्ट थोड़ा जल्दी पेश हो तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्सट सैशन ही ठीक है। श्री फूलचन्द मुलाना जी इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, कर्ण सिंह दलाल, श्रीमती सुमिता सिंह, श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री राधेश्याम शर्मा अमर इसके मैम्बर्ज होंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान, श्री नरेश मलिक या श्री राम कुमार गौतम जी में से किसी एक को इस कमेटी में ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान तथा श्री नरेश मलिक जी के नाम भी इस हाउस कमेटी में शामिल कर दिये जाएं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, इस बारे में विभाग अपने आप में सक्षम है, तो फिर कमेटी के गठन की क्या जरूरत है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या आप इस बारे में हाउस में वोटिंग करवाना चाहते हैं कि कमेटी का गठन न किया जाए? (शोर एवं व्यवधान) Keeping the sense of the House, I constituted the Committee. (Noises & interruption)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी इन्दौरा जी कमेटी के बनने से क्यों घबराते हैं? इन्दौरा जी, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। डैमोक्रेसी का मतलब यह है कि हम आप लोगों को मौका देंगे। (विघ्न) हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो इसलिए हम जल्दबाजी में कोई ऐक्शन नहीं लेना चाहते हैं। हमारी बायस्ड ओपीनियन नहीं है। हम सब की सलाह से काम करना चाहते हैं और हाउस की कमेटी बनने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार कार्यवाही करने के लिए सक्षम है तो ये कमेटी क्यों बना रहे हैं। मैं इस कमेटी के बनने का विरोध करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I was the man of this opinion that जब यह बात आई थी कि स्टेट एजैंसी नहीं है तो इस बारे में मैंने यह कहा था कि स्टेट की इन्वैस्टीगेशन एजैंसी है और उनसे ही इन्वैस्टीगेशन करवा लें। But after keeping the sense of the House because so many members have expressed their views कि उसमें हाउस की कमेटी हो, I constituted the Committee. अगर आप इस बारे में वोटिंग चाहते हैं तो हम वोटिंग करवा देते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इस कमेटी में रामकिशन फौजी जी और आई०जी० शेर सिंह जी भी मैम्बर्ज होंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : *************** । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, असल में जो प्रोब्लम इन भाइयों की है, वह आप भी, हुड्डा साहब भी और सारा हाउस भी समझता है। अध्यक्ष महोदय, ये सारे भाई जानते हैं कि जहां पर ये खड़े हैं, वहां पर खड़ा होना इनकी मजबूरी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको एश्योरेंस दिलवाकर इनका कल्याण करवाएं। (शोर एवं व्यवधान) इनको भी पता है कि जिस वर्ग से ये हैं उनकी तो शक्ल के ही वह खिलाफ हैं। उसने तो इनके उस वर्ग का बहुत बुरा कर रखा है। (शोर एवं व्यवधान) इस सब के

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री रामकुमार गौतम]
बावजूद भी उनके साथ खड़ा होना इनकी मजबूरी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको एश्योरैंस दिलवा दो आगे के लिए इनका खाका ही कट जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : *************** ।

श्री अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

श्री राम कुमार गौतम : हम इनको बहुत प्यार करते हैं। I love you all people. (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सभी भाई बहुत ही अच्छे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) पण्डित जी आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे भाई हैं बेसिकली ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं इनको बहुत प्यार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सारा हाउस जानता है, सारी दुनिया जानती है और हरियाणा का बच्चा-बच्चा जानता है कि सैटिंग का जो समय था that time is over. पहले जो सैटिंग का सिलसिला था वह इनकी पार्टी का जो मुखिया है वह सदन में आता नहीं है, उनकी और आपकी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भजन लाल के बीच में एक सैटिंग थी। यह भाई उसको टिकट दिला लाया, कहां बैठा है धर्मबीर? अध्यक्ष महोदय, आदमपुर कांस्टीच्यूएंसी में 70 हजार वोट इन्होंने उसके खिलाफ दिलवा दिए थे। अध्यक्ष महोदय, वे वोट अभय चौटाला को दिलवा दिए थे। अध्यक्ष महोदय, जितने भी कैंडिडेट्स हुड्डा साहब के ग्रुप के थे, इनकी आपस की लागबाजी के कारण उन सभी को हरा दिया गया और उसकी वजह से हमारे यहां पर कुछ अच्छे भाई आ गए हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, वोट तो लोगों का अधिकार है और वोट उन्हीं ने डाले हैं वोट कैसे कोई डलवा सकता है। क्या हरियाणा की जनता समझदार नहीं है? हरियाणा की जनता जागरूक है। यह तो इन्होंने लोगों को इमोशनल किया है और लोगों से झूठे वायदे करके यहां पर आए हैं।

श्री राम कुमार गौतम : कोई बात नहीं वे अगली दफा निकाल देंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, इनको आप चैम्बर में बुला लें और वहां पर इनके टोटके सुन लें।

Mr. Speaker : Every Hon'ble Member has the right to speak but it is my duty to maintain the decorum and dignity in the House. (interruption) डाक्टर साहब, आप सुनते तो हैं नहीं।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, जो आदमी महज एम०एल०ए० बनने के लिए ऐसी जगह चला जाए जो इनके जाने के लायक नहीं थी तो वह इनके लिए सही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कल जो तवा चढ़ रहा था अगर उसको आप लोग सुन लेते तो फिर आपको पता चलता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर साहब, सारी हरियाणा की जनता जानती है कि जो यह सैटिंग का हिसाब किताब था that time is over. स्पीकर साहब, जिस तरह से सांप की मुंडी पर अगर लट्ठ मार दो या उसको बीच बिचाले में से तोड़ दो तो उसका मरना जो डैफनेट है लेकिन उससे पहले उसका जहर थूलेगा और वह पूंझड़ी मारेगा। स्पीकर सर, अब तो चौटाला साहब पूंझड़ी मार रहे हैं और अब ये बैकवर्ड सम्मेलन कर रहे हैं जिनका इन्होंने बीज मार रखा है, हरिजन सम्मेलन भी ये कर रहे हैं जिनकी शक्ल देखकर ये राजी नहीं हैं। इसी तरह से इनके चेले व्यापारियों से फिरौतियां लेते थे, उनकी दुकानें लूटते थे लेकिन अब ये उनके भी सम्मेलन कर रहे हैं। स्पीकर साहब, उनका नारा सीधा था। चौधरी भजनलाल का समय आया तो चौटाला जी सीधा कहते थे कि अरे भाई मोडियों को मारेंगे, हमारे जाट भाई भोले भाले किसानों को बहकाकर वे वोट ले जाते थे और जातिवाद का नारा लगाते थे।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, मोडिया क्या हैं?

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, उस भाषा में बिश्नोई भाइयों को मोडिया कहते हैं but that time is over.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ये किस मुद्दे पर बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, मैं उनसे खुद पूछ रहा हूं कि पंडित जी, आप किस मुद्दे पर बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठो तो सही, मैं उनसे पूछ रहा हूं।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मैं मुद्दा बताऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, इनका कोई मुद्दा नहीं है।

सदस्यों का नाम लेना

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, गौतम साहब जीरो ऑवर में अपनी बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded.

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : स्पीकर साहब, *********

श्री अध्यक्ष : बलवन्त जी, आप ऐसे नहीं बोल सकते। वे अपना मुद्दा बता रहे हैं इसलिए आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के माननीय सदस्य श्री साहिदा खान हाउस की वैल के नजदीक आकर जोर जोर से बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : साहिदा खान, आप अपनी सीट पर जाइये। (शोर एवं व्यवधान) Sahida Khan, I warn you.

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए।

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Sahida Khan, I warn you. साहिदा खान, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) I again warn you.

श्री साहिदा खान : स्पीकर साहब, *********

Mr. Speaker : Sahida Khan, I name you. अगर कोई अपनी चेयर छोड़कर हाउस की वैल के नजदीक आएगा तो he will be named.

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री साहिदा खान सदन से बाहर चले गए।)

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, *********

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। Nothing to be recorded.

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, ********* (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे को पता है कि जीरो ऑवर में कोई भी मैम्बर कोई भी बात बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) बलवन्त सिंह, आप बैठिए।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूं। I am coming to the point. (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इनको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, अरे भाई आपका हुड्डा साहब से क्षमादान करवा देंगे। आप चिन्ता क्यों करते हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, *******

Mr. Speaker : Balwant Singh, please take you seat. (शोर एवं व्यवधान) Balwant Singh Sadhaura, I warn you. (Interruptions) I warn you.

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, ******

Mr. Speaker : Balwant Singh Sadhaura, I again warn you. I name you.

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री बलवन्त सिंह सढौरा सदन से बाहर चले गए।)

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, ****** (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य डॉ० सुशील इन्दौरा हाउस की वैल में आ गए और जोर जोर से बोलने लगे।)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, ******

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप अपनी सीट पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) Indora ji I warn you.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, ******

Mr. Speaker : Mr. Indora, I warn you.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, ******

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Mr. Indora, I again warn you. (Interruption) I name you.

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य डॉ० सुशील इन्दौरा सदन से बाहर चले गए ।)

श्री अध्यक्ष : जो भी ये बोल रहे हैं इनका रिकार्ड न किया जाए । जीरो ऑवर में कोई श्री आनरेबल मैम्बर्ज कोई भी मुद्दा उठा सकता है ।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य डाक्टर सीता राम और रामफल चिढ़ाना हाउस की वैल में आकर जोर जोर से नारेबाजी करने लगे ।)

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, इनको सुनने की ताकत होनी चाहिए । जो भी ये मुझे सुनाना चाहते हैं वह मुझे सुना दें, हम इनके सामने कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे । आप कुछ भी कह लेना मुझे ऐतराज नहीं है । हम सारी बात सुनेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

10.55 बजे **श्री अध्यक्ष :** जीरो ऑवर में कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है । (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों को नेम करने के फैसले को रद्द करना

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथियों को सदन में वापस बुला लें ताकि वे भी यहां पर अपनी बात कह सकें ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी चेयर पर जाकर रिक्वैस्ट करें । आप चेयर पर जाओ और वहां से रिक्वैस्ट करो । आप अपनी चेयर पर जाकर रिक्वैस्ट करें ।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो हमारे साथी बाहर किए हैं उनको आप वापस बुला लें । यदि वे हाउस की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, ये साथी यदि अनुरोध कर रहे हैं मेरा आपसे निवेदन है कि इनके साथियों को सदन में बुला लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : मैंने तीन-तीन बार वार्न किया था । What is the meaning of warning? वार्निंग के क्या मीनिंग हैं ?

डॉ० सीता राम : पहले आपने मुझे निकाला । आपने मुझे एक बार देखा और आपने कह दिया कि 'I name you.' आप कह रहे हैं कि तीन बार वार्न किया ।

श्री अध्यक्ष : चेयर को छोड़ने से पहले आपको सोचना चाहिए ।

डॉ0 सीता राम : मुझे पता है कि यह चेयर का सम्मान नहीं है लेकिन जिस सदस्य को पता ही नहीं है कि वह क्या बोल रहा है उसे आप बोलने की इजाजत दे रहे हैं । इनको सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला ही नजर आते हैं । ये लोगों को इमोशनली प्रभावित कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में यह कहना है । (विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जब आपने मुझे मौका दिया है तो फिर ये बोलने के लिए क्यों खड़े हैं । सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हम अपनी बात उसी समय रखेंगे जब आप हमारे बाकी के साथियों को यहां वापस बुला लेंगे । जब हमारे साथियों को यहां वापस बुला लेंगे तभी यहां सदन की कार्यवाही चलेगी ।

श्री अध्यक्ष : उनको तभी बुलाने पर विचार किया जा सकता है जब आप गारंटी लोगे कि they will behave properly. अगर खबरें छपवाने के लिए और अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए आप वाक आउट करते हैं तो यह ठीक बात नहीं है । ऑनरेबल मैंबर जीरो ऑवर में बोल रहे हैं । माननीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने घोटाले का मुद्दा उठाया था उस पर ये बोल रहे थे । (शोर एवं व्यवधान) वे क्या गलत बात कह रहे थे ।

11.00 बजे **डॉ० सीता राम :** अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो सरकार उसको देखकर कार्यवाही कर ले । गालियां निकालना और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना यह कहां की परम्परा है हमारे साथियों को जो हाउस से निकाले गये हैं उनको वापिस बुलाइये । सर, मैंने अपनी बात कह दी है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डाक्टर सीता राम जी आप अपनी सीट पर बैठिये, आपके साथियों को बुला लेंगे । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बुला लेंगे । लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आगे ऐसी बात न हो ।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, अनकंडीशनल बुलाइये । (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर सीता राम इस सदन में दूसरी बार चुनकर आये हैं । इन्हें इस बात की जानकारी है कि चेयर का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है । हम चेयर के साथ शर्तें नहीं रख सकते । चेयर ने उदार हृदयता दिखाई है । सदन के नेता ने भी अभी अनुरोध किया है कि आप इनकी रिक्वैस्ट को कंसीडर करें । सभी सदस्य आ जायें । माननीय पण्डित जी भी अपनी बात कहें । ये माननीय साथी भी अपनी बात कहें और इस सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें । मैं आपसे अपने साथियों की तरफ से अनुरोध करूंगा कि आप उन साथियों को बुला लें । हम सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालने देंगे । सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलायेंगे । चेयर का हम सभी सदस्य आदर करते हैं । विपक्ष के साथी, बी०जे०पी० के साथी और इण्डिपैंडेंट साथी सभी साथी चेयर का सम्मान करते है । इस प्रकार का सौहार्द हम बनाये रखेंगे ।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के भी नियम हैं कि इस सदन के सदस्यों को लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है । आपने नियमों की पुस्तिका छपवाई है उसमें सभी व्यवस्था दी गई है । हर मैम्बर को सदन में बोलने का पूरा अधिकार है, प्रैक्टिस कोई भी है जब कोई मैम्बर अपनी बात कहे तो किसी दूसरे सदस्यों को अगर उसके बारे में कोई आपत्ति है तो वह खड़ा होकर उस बात का जवाब दे । लेकिन बीच में इन्ट्रप्ट करने से न उसकी बात सुनी जाती है न दूसरे की । मेरा निवेदन है कि हमारे संसदीय मंत्री ने जो बात कही है मैं उनसे सहमत हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इनके साथियों को बुला लिया जाए लेकिन जो सदन की प्रणाली है उसका वे पालन करें ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, गौतम जी आप जीरो आवर में क्या बोल रहे थे उसको कन्टीन्यू करें।

डॉ० सीता राम : सर, गौतम साहब किस मुद्दे पर बोल रहे हैं। ******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. गौतम जी, आप जीरो आवर में क्या बोल रहे थे।

डॉ० सीता राम : सर, ******

श्री अध्यक्ष : डॉ० सीता राम जी, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। (विघ्न) मुद्दा यह था कि पिछले सरकार ने ऑक्शन में जो लूट-खसौट मचाई थी, जमीन बेची गई थी उसके बारे में गौतम जी बोल रहे थे।

डॉ० सीता राम : सर, ******

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं 100 प्रतिशत उसी के बारे में अपनी बात कह रहा हूं इनको मेरी बात पहले सुननी चाहिए उसके बाद में ये अपना जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहें। पण्डित जी इस बारे में कमेटी बना दी है जब कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद आप बोल लेना।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनाने से किसी सदस्य का बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है क्या? कमेटी बनाई हुई तो क्या हुआ। कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात सदन में कह सकता है यह उसका अधिकार है और उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। आप इनके कहने से क्यों किसी माननीय सदस्य को बोलने से रोक रहे हो। ये तो रोकेंगे ही। आप बोलने दीजिए। (विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ऐसे गौतम जी के पास क्या तथ्य हैं अगर कोई तथ्य हैं तो उसे कमेटी देख लेगी।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य मेरी बात सुनेंगे। मैं सच्चाई की बात कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहता। अगर मेरी बात झूठ हो तो यह हाउस जो सजा देगा वह भी मुझे मंजूर है। (विघ्न) मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं कि जब ओम प्रकाश चौटाला ने टेक ओवर किया था उस समय रेत के भाव क्या थे? उसने एक भाई को ठेकेदार बना दिया और उससे कहने लगा कि देख भाई बात सुन तू है ठेकेदार, तू कितने पैसे की नौकरी की उम्मीद करता था। वह कहने लगा कि चौधरी साहब, 10 हजार की मिल जाती तो बहुत थी। कहने लगा चल तेरे को 20 हजार की नौकरी दे दी और रेत के भाव पता कर लो जितने भाव उस दिन थे उससे दो गुना, ढाई गुना तेज कर दिए और वह बेचारा नौकरी पर ही था। इसी तरह जो जमीनें थीं उसमें पहले कह दिया होगा कि 4 लाख ले आइए और एक लाख मैं तेरे नाम कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) 100 परसैंट यही बात मिलेगी, या तो उससे पहले पैसे खा लिए होंगे।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। ये कहते हैं कि कह दिया होगा तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कह दिया होगा नहीं कहें बल्कि जो सत्य है वह कहें। आज जो महंगाई बढ़ी है, रेत के रेट बढ़े हैं, क्रशर्ज के रेट बढ़े हैं क्या उनमें भी कमीशन लिया गया है। जो स्टील के रेट बढ़े हैं क्या इसमें भी कांग्रेस पार्टी ने कमीशन लिया है। (शोर एवं व्यवधान) ये खुद छोड़ कर जाने वाले हैं। इनको अपने ठिकाने का तो पता नहीं और दूसरों को नसीहत देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आज जो टाइम्स आफ इंडिया में रिवाड़ी जिले के मुकंदपुर गांव के बारे में खबर है, उसकी तरफ मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रिवाड़ी जिले का एक गांव मुकंदपुर बसई है। पुराने रजवाड़ों की व्यवस्था के अनुसार पहले वहां पर भरतपुर रियासत का रजवाड़ा हुआ करता था अब फिर न जाने किस तरह से वहां के लोगों ने उस आधे मुकंदपुर गांव को खरीदने का काम किया है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशासन सजग है क्योंकि डी०सी० ने एस०डी०एम० से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर वे स्वयं निगरानी रखें और अगर इस गांव को एक्वायर करने की भी नौबत आए तो सरकार को एक्वायर करना चाहिए। यदि इस गांव को फिर से बसाने की कोई व्यवस्था करने की भी बात आए तो सरकार को इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए।

गैर-सरकारी संकल्प--

कुटीर उद्योगों, विशेषकर पारंपरिक उद्योगों की अवनति के संबंध में

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Dr. Sushil Indora, MLA, will move a resolution.

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय-मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

> ''यह सदन प्रदेश में कुटीर उद्योगों, विशेषकर पारंपरिक उद्योगों की निरंतर अवनति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है क्योंकि कुटीर उद्योग ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल तथा अकुशल श्रमिक वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है।''

अध्यक्ष महोदय, जो गैर सरकारी संकल्प मेरे नाम के सामने आया है और उसको कार्यवाही में सम्मिलित किया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस कमैंट के साथ हमें दबड़काया जाता है या हम दबड़क कर चले जाते हैं। हमें धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है इसका फैसला तो उच्च आसन पर बैठे लोग ही कर सकते हैं या फिर सदन के नेता कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे आचरण पर शक किया जाता है यह आपके सामने है। (विघ्न) मैं सदन की गरिमा का पूरा ध्यान रखते हुए अपने गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरा साथ दें। अध्यक्ष महोदय, भारत देश गांव का देश है और हमारे देश में 70 से 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। पुराने समय से ही गांवों के अपने पारम्परिक उद्योग रहे हैं और गांव में रहने वाले लोग उन पारंपरिक उद्योगों के जरिये अपना-अपना रोजगार चलाते रहे हैं। यही कारण है कि उनकी उन्नति से भारत का विकास हुआ है। आप सभी जानते हैं कि एक

समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि पहले गांव के आधार पर ही विकास का आधार होता था। यही कारण है कि गांवों के विकास के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, पहले सूई से लेकर ओखली-मूसली जिनसे खाद्य पदार्थों को कूटकर खाने लायक बनाया जाता है आदि का काम गांव के स्तर पर ही हो जाता था। हर चीज गांव में मिल जाती थी यानि कि गांव में रहने वाले लोगों की मूलभूत जरूरतें गांव में ही पूरी हो जाती थी। गांव में ही गांव के लोगों को रोजगार मिल जाता था। जो किसान भाई थे वे अपने सीमित साधनों से जहां अपने लिए आजीविका का काम चलाते थे वहीं अपने सहयोगी दस्तकार भाइयों की आजीविका भी चलाते थे। चाहे कोई हथकरघा के दस्तकार थे, चाहे कोल्हू चलाने वाले भाई थे, चाहे चक्की चलाने वाले भाई थे हर किसी की जरूरतें गांव के लैवल पर पूरी हो जाती थी। अध्यक्ष महोदय, पुराने समय में जो तेली का कोल्हू था वह पारम्परिक उद्योग का एक हिस्सा था। इसी तरह से कुम्हार भाई जो बर्तन बनाते थे उनसे भी लोगों को रोजगार मिलता था। लुहार भाई की कुल्हाड़ी और कस्सी से किसानों को रास्ता मिलता था। इसी तरह पिंजाई से रजाई बनाने वाले भी उस समय समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। इसी तरह से चाहे कोई जूती बनाने वाला था, खादी के कपड़े बनाने वाला था या आटे की चक्की चलाने वाला था ये सभी एक दूसरे के लिए जरूरतें पैदा करते थे और सबकी जरूरतें गांव के लैवल पर ही पूरी हो जाती थी तथा सभी को गांव के लैवल पर ही रोजगार मिल जाता था। अध्यक्ष महोदय, उस समय कुशल और अकुशल सभी को उनके काम के मुताबिक रोजगार मिलता था और सभी लोग गांव के स्तर पर अपना गुजारा कर लेते थे तथा सभी में सामाजिक प्रेम प्यार भी बना रहता था। हालांकि उस समय गांव सामाजिक वर्णता के आधार पर बंटे हुए थे और लोगों के काम भी सामाजिक वर्णता के आधार पर बंटे हुए थे लेकिन सभी में सामाजिक प्रेम की भावना बनी रहती थी। किसान भाई खेती करके अनाज पैदा करते थे और दूसरे भाई भी अपने-अपने रोजगार से एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे तथा सभी आपस में मिल बांटकर खाते थे। उस समय जो भी सामाजिक काम होता था उसको सभी लोग मिलकर करते थे। चाहे गऊशाला बनाने की बात हो, चाहे धर्मशाला बनाने की बात हो, चाहे विवाह-शादी में शगुन के आधार पर मदद करने की बात हो या किसी और प्रकार से सामाजिक सेवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, गांव के लैवल पर ही सभी एक दूसरे की मदद करते थे जिससे सभी में बहुत ज्यादा प्रेम प्यार बना रहता था। इसके अतिरिक्त गांव के स्तर पर ही व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले वैद्य उस समय जड़ी-बूटियों से काढ़ा बनाते थे और लोगों की बीमारियों का इलाज करके उनकी मदद करते थे तथा अपनी जीविका भी चलाते थे और साथ ही साथ वे वहां पर अपने उस ट्रैडीशनल पारम्परिक ज्ञान का प्रयोग करके समाज के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते थे। ऐसे ही खाद्यान्न सामग्री से जुड़े बहुत से अनेक संसाधन थे जैसे हमारे लोग पापड़, बड़ियां और सेवियां बनाते थे। ऐसे ही सांगर जो जांटी से लगता था उसको सुखाकर घड़े में ही भर लेते थे। इसको आज भी फाईव स्टार होटलों में बड़े चाव के साथ खाया जाता है। इसी तरह फोफली और फोगला को भी हम सुखाकर इकट्ठा कर लेते थे ताकि जरूरत के हिसाब से हम आपस में मिल बांट कर प्रयोग कर लें इस प्रकार हम एक दूसरे की जरूरतों को भी पूरा करते थे। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनंद सिंह दांगी चेयर पर पदासीन हुए।)** चेयरमैन साहब, ये ऐसी रिवायतें थी, ऐसा प्रेम और प्यार था कि हम एक

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

दूसरे की जरूरतों को भी पूरा करते थे और इससे बेरोजगार लोगों को भी रोजगार के साधन मुहैया होते थे। इससे सामाजिक ढांचे को भी बढ़ावा मिलता था। समय बदला और समय बदलने के साथ-साथ हर चीज बदलती गई, जरूरतें भी बढ़ती और बदलती चली गई। जरूरतों के बढ़ने के कारण छोटी-छोटी मशीनें आई। हथकरघा उद्योग शुरू हुआ, होजरी के उद्योग शुरू हुए। खेस, दरी व चादरें मशीनों पर बनने लगी, जूते, कपड़े मशीनों से बनने लगे, रस्से, जाल वगैरह भी मशीनों से बनने लगे, खेलों का जो सामान था वह मशीनों से बनने के साथ-साथ गांवों में हाथों से भी बनता था इससे लोगों को रोजगार मिलता था और चीजें भी मशीनें बनाने लगी लेकिन इस सबके बावजूद भी हमारे कुटीर और लघु उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। कुटीर और लघु उद्योगों की बात हो और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम न आये तो यह एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि ग्रामीण विकास के लिए पारम्परिक कुटीर उद्योगों की जरूरत है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और देश का विकास हो सके क्योंकि गांव के विकास में ही देश का विकास निहित है। ऐसे ही महात्मा गांधी जी के साथ-साथ चलते देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू जी थे जो कि ज्यादा समय विदेशों में भी रहे। मैं यह नहीं कहता कि उनका लगाव कुटीर उद्योगों की तरफ नहीं था।

श्री विनोद कुमार शर्मा : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सभापति महोदय, पण्डित जवाहर लाल नेहरु तो देश की आजादी के लिए बहुत बार जेलों में गये थे। क्या इन्दौरा जी बतायेंगे कि इनकी पार्टी के कितने नेता आजादी के लिए जेलों में गये।

श्री सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये इस बारे में हमारे नेताओं से ही जाकर पूछ लें क्योंकि इनके हमारे नेताओं के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं। ये मुझे क्यों बीच में लाना चाहते हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपने जीवन का काफी समय विदेशों में गुजारा और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी बात भी नहीं थी कि वे कुटीर उद्योगों के खिलाफ थे लेकिन उनकी विदेशों के हिसाब से विकास की एक सोच थी। यह बात भी ठीक है कि आदमी जहां रहता है उसकी सोच पर भी वहां का असर होता है कि वहां के विकासात्मक ढांचे को फोलो किया जाये। क्योंकि उन्होंने विदेशी सभ्यता को काफी देखा था, अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स देखी थी, बड़े-बड़े कारखाने देखे थे और मैं खुद भी ऐसी जगहों पर गया हूं जहां पर मुझे स्वयं लोगों ने इस बारे में बताया। मैं यह भी नहीं कहता कि यह विकास की सोच अच्छी नहीं थी। यह सोच अच्छी थी क्योंकि वक्त के साथ बदलने की सोच अच्छी है लेकिन पुरानी परम्पराओं को भुलाना भी नाइंसाफी है। हम अगर बड़ी इकाइयों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो अच्छी बात है लेकिन इसके लिए हम छोटी इकाइयों को नुकसान नहीं पहुंचायें इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे देश का विकास होगा। लाखों लोगों को छोटी-छोटी इकाइयों के माध्यम से रोजगार मिलता है और उनकी आजीविका का साधन बनता है। लेकिन धीरे-धीरे वक्त बदला है। आज के वक्त की बात कहें तो पहले जहां कुटीर उद्योग आम आदमी के हाथ में थे जहां किसान अपने सीमित साधनों के बावजूद भी अपनी खेती की रखवाली

कर लेता था वहीं ये वक्त के साथ बदलते चले गये और विकास और उद्योग पूंजीपतियों के हाथों में आते गये। सभापति महोदय, शुरूआत यहां से हुई कि हमने विकास की ऊंची दर हासिल करने के लिए चमक-दमक वाली नीतियां बनाई और पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में हमने अपने कुटीर उद्योगों को भुला दिया। उनकी तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया और विकास के पहिए कुटीर उद्योगों को रौंदते चले गये। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से सरकारों का हाथ रहा। चाहे वह प्रदेश की सरकार थी, चाहे केन्द्र की सरकार थी। मैं सरकारों का हाथ इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि सरकारों ने बदलाव लाने के लिए ऐसी नीतियां बनाई जिससे सब कुछ बदल गया और कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण वे पूंजीपतियों के हाथों में खेलते चले गये। जहां पहले हर हाथ को काम मिलता था, हर आदमी अपनी आजीविका कमा सकता था, वहीं विकास की अंधी दौड़ में वह विकास एक विकास ही रह गया और 100 हाथ खाली हो गये। सभापति महोदय, छोटी से छोटी सुई से लेकर ऊंखली-मूसली बनाने तक का काम आज किसी टाटा ने ले लिया, किसी बिडला ने ले लिया या किसी मोदी ने ले लिया है। आज जूते बनाने के बड़े-बड़े कारखाने लग गये, स्पिनिंग के बड़े-बड़े मिल लग गये और आर्थिक नीति निर्धारण का काम इन पूंजीपतियों ने अपने हाथ में ले लिया कि हम इस देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। मशीनी युग में तो कुछ लोगों के हाथों में ही काम चला गया और बहुत से लोग बेरोजगार होते चले गये क्योंकि जिनके पास सीमित साधन थे वे अपनी आजीविका तो कमा सकते थे लेकिन पूंजीपतियों की दौड़ को कम्पीट नहीं कर सकते थे, उनके साथ नहीं चल सकते थे। उसका नतीजा यह हुआ कि वे पिछड़ते चले गये। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। आर्थिक विकास की दर का लाभ कुछेक लोगों को होने की बजाय आम आदमी को मिलना चाहिए क्योंकि यह बात माननीय वित्त मंत्री जी ने भी यहां हाउस में कही थी लेकिन हो उसके बिल्कुल विपरीत रहा है। विकास कुछेक पूंजीपतियों के हाथों में चला गया है जबकि होना यह चाहिए था कि सरकार इन कुटीर उद्योगों के बारे में विशेष ध्यान देती, उनको साधन मुहैया करवाती। ग्रामीण क्षेत्रों के जो श्रमिक हैं उनको प्रोत्साहित करती, उनको आर्थिक लाभ देती। उनको विशेष ट्रेनिंग देने का प्रावधान करना चाहिए था। सभापति महोदय, मैं कौशल की बात भी करना चाहता हूं। वैद्य का बेटा होगा तो वह वैद्य का कौशल सीखेगा, लुहार का बेटा लुहार का काम सीखेगा लेकिन कौशल के काम को अनदेखा कर दिया गया, इसीलिए लोग अपने परम्परागत धंधे को छोड़ रहे हैं। सभापति महोदय, शिक्षा का अभाव रहा। जहां उसको शिक्षा देकर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए था वहां उसका अभाव रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहा जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती गई। जब बेरोजगारी बढ़ती गई तो गरीब श्रमिक और गरीब किसानों ने आहिस्ता-आहिस्ता शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। शहरों में आकर भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हुई। उन लोगों ने कालोनियां बना लीं। कल-परसों यहां हाउस में अवैध कालोनियों का जिक्र हो रहा था। उन लोगों के शहरों में आने से अवैध कालोनियों का निर्माण शुरू हो गया क्योंकि उनको कहीं न कहीं रहना ही था। आहिस्ता-आहिस्ता गरीब आदमी काम की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ गये और जो गांवों में रह गये वे बेरोजगारी की तरफ बढ़ गये।

श्री सभापति : आज के दिन सरकार गरीबों की मदद के लिए 100-100 गज के प्लाट कालोनी की तरह डिवैल्प करके दे रही है। (विघ्न) डॉ० साहब, आप लोग किसी पर

[श्री सभापति]

विश्वास नहीं करते हो। प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सरकार जो काम कर रही है आप लोगों को उनकी सराहना तो करनी चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, इस तरह से बेरोजगारी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती चली गई और कुटीर उद्योग ठप्प होते चले गये। महात्मा गांधी जी का स्वदेशी का नारा क्षीण हो गया और उसके अक्स ढीले पड़ गए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी बनो, स्वदेशी पहनो और स्वदेशी ही खाओ लेकिन ये सारे के सारे नारे क्षीण हो गये हैं। इसके साथ ही साथ इस सरकार ने पूंजीपतियों के साथ मिल कर आर्थिक नीतियों के निर्धारण का प्रोग्राम बनाया है। सरकार ने अपनी नीतियों में पूंजीपतियों को रियायतें देकर विकास की दर को नीचा करने का कार्य किया है। हम विकास चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि विकास हो, सारा देश चाहता है कि विकास हो लेकिन उसके लिए नीति निर्धारण पूंजीपतियों के हाथ में न हो कर सरकार अपने हाथ में ले और इस प्रकार की नीतियां निर्धारित करे जिससे आम आदमी को चाहे श्रमिक हो, चाहे वह मजदूर हो, विकास के लाभ में उसका उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना कि उसमें उसके सहयोग का हिस्सा है। लेकिन जो नीतियां निर्धारित की गई हैं उनसे उसका हिस्सा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। रोजगार के नाम पर पूंजीपतियों ने कहा कि हम रोजगार देंगे, इसके लिए हम मॉल बनाएंगे, एस०ई०जैड० बनाएंगे, बड़ी-बड़ी दुकानें खुलवाएंगे, बड़े-बड़े रिटेल आउटलैट खोलेंगे या डिपार्टमैंटल स्टोर खोलेंगे। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नारे दिये लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों का लाभ किसको मिला? उस व्यापार का आर्थिक लाभ पूंजीपतियों को मिला है जो पिछड़ा और गरीब आदमी है वह उनके मुंह की तरफ देखता रह गया है। सभापति महोदय, इस मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसकी जरूरत सारे देश में है और वह है स्पैशल इक्नॉमिक जोन। मैं एस०ई०जैड० की बात कहना चाहता हूं। एस०ई०जैड० के आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यह अच्छी बात है। यह बात वे सदन में जरूर रखें कि रोजगार किस को देंगे तो इस बात से हमें बहुत खुशी होगी। हम चाहते हैं कि कुशल और अकुशल चाहे कोई भी श्रमिक हो, मजदूर हो उसको रोजगार मिले। सभापति महोदय, अब मैं इसमें एस०ई०जैड० की नियमावली का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि 25 प्रतिशत भूमि पर उद्योग लगेंगे। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से जो आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं यह सही हैं और अगर कहीं पर कोई गलत बात होगी तो सरकार उसको करैक्ट करके मुझे भिजवा दे। नियमावली के मुताबिक 20 प्रतिशत भूमि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए होगी जिसमें दुकानें और मॉल बनेंगे, 16 प्रतिशत भूमि पर रैजिडैंशियल एक्टिविटीज होंगी यानि इस भूमि पर रहने के लिए घर बनेंगे, 5 परसैंट भूमि पर ऐण्टरटेनमैंट एक्टिविटीज होंगी, 5 प्रतिशत भूमि पर संस्थाएं यानि इन्स्टीच्यूट्स होंगे जिनमें स्टेडियम्ज, पार्कस, अस्पताल, धर्मशालाएं, स्कूल आदि बनाए जाएंगे और 30 प्रतिशत भूमि पर व्यापारिक स्थल बनाएं जाएंगे जिनमें रिटेल आउटलैट, जैसे छोटे-मोटे बूथ, व्यापारिक स्थल आदि हो जाएंगे। सभापति महोदय, मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी मंशा में कोई खोट नहीं है, मैं अपनी मंशा में कोई खोट नहीं देखता लेकिन मुझे सरकार की मंशा में खोट लगता है जो किसान है उसके पास अपने गुजारा करने योग्य भूमि नहीं है।

जितनी जमीन उसके पास है उससे न तो उसका अपना पेट भरता है, न ही उसका अपना खर्चा पूरा होता है। जो मजदूर है उसको जो मजदूरी मिलती है उससे उसका पेट नहीं भरता। जो मजदूरी उनको मिलती है वह इतनी थोड़ी है कि उससे उसका गुजारा नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, यह बात मुझे समझ में नहीं आई कि इतनी थोड़ी सी भूमि है उस पर 20 लाख लोगों को रोजगार कैसे देंगे।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, आपकी सोच भी थोड़ी छोटी नज़र आ रही है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, मैंने पहले ही कहा है कि मेरी मंशा में कोई खोट नहीं है लेकिन अगर कहीं कोई सवाल उठता है तो उस सवाल के बारे में क्लैरिफिकेशन लेना हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : चेयरमैन सर, यह प्राईवेट मैम्बर रैजोल्यूशन है। चेयरमैन सर, गैर-सरकारी संकल्प पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इसमें मेरा कोई दखल अन्दाजी करने का मकसद नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य इस बारे में बोलते हुए रास्ता भटक गए हैं इसलिए मैं इनको इनका रैजोल्यूशन पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि इनका जो रैजोल्यूशन है वह इस प्रकार से है--

> "यह सदन प्रदेश में कुटीर उद्योगों, विशेषकर पारंपरिक उद्योगों की निरंतर अवनति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है क्योंकि कुटीर उद्योग ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल तथा अकुशल श्रमिक वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है।"

सर, स्पैशल इक्नौमिक जौन किसी भी दृष्टि से कुटीर उद्योग नहीं है। इनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर इनका आईडिया सिर्फ यह है कि प्राईवेट मैम्बर रैजौल्यूशन के माध्यम से आलोचना करना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका जवाब दे देंगे। इन्हें तो सरकार को नीतिगत निर्णय लेने के लिए सकारात्मक सुझाव देने चाहिएं। मैं तो यह कहता हूं कि आलोचना केवल आलोचना के लिए न की जाए। इन्होंने बोलते हुए कई अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं उनको नोट भी कर रहा हूं। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि ये इस गैर सरकारी संकल्प पर हैल्दी सुझाव दें। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप बबलिंग न करें, आप बोलते हुए रास्ते से भटक गए थे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, यह सवाल जवाब का समय नहीं है। मुझे पहले अपनी बात कहने दें और फिर मंत्री जी इस बारे में जवाब दे दें। सभापति महोदय, सदन में सिर्फ एक ही वरिष्ठ मंत्री जी बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : मांगे राम जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। आप एस०ई०जैड० के बारे में इनसे पूछ लें।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : सभापति महोदय, आपने मुझे जो इण्डस्ट्रीलिस्ट का दर्जा दिया है, इस बारे में मैं माफी चाहूंगा कि मेरे पास एक छोटी सी भी इन्डस्ट्री नहीं है। सभापति महोदय, यह जो इन्दौरा जी एस०ई०जैड० के बारे में कह रहे हैं कि वहां पर कहां से नौकरियां दी जाएंगी। इसके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस 25 प्रतिशत भूमि पर उद्योग लगेंगे उस पर कौन काम करेगा, उस पर लोग काम करेंगे। 20 प्रतिशत

[श्री मांगेराम गुप्ता]
भूमि पर जो कमर्शियल स्टोर और शॉप्स बनेंगी उसमें भी लोग काम करेंगे। 5 प्रतिशत भूमि पर एजुकेशन इन्स्टीच्यूट खुलेंगे उसमें भी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर हरियाणा के लोगों को प्रायरिटी दी जायेगी और हरियाणा के लोगों को ही काम मिलेगा।

श्री सभापति : मंत्री जी, यह टोटल एरिया के एक प्रतिशत भूमि पर ही बनेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, मैं एक बात और आपके माध्यम से माननीय साथी जी से कहना चाहूंगा कि अगर ये एस०ई०जैड० पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो करें। हमें इस बारे में कोई एतराज नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहूंगा कि ये इस बारे में रैजोल्यूशन ले आएं और इस पर आधा घंटा, एक घंटा या दो घंटा चाहें तो डिस्कशन कर लें। हमें कोई एतराज नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि इनके नेता जब मुख्यमंत्री थे, उनके समय में ही यह अधिग्रहण किया गया था। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कागज निकाल कर दिखा देता हूं। उस समय उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री होते हुए साईन किए हुए हैं। यह कागज आप देख सकते हैं।

श्री सभापति : इस एस०ई०जैड० के मुद्दे पर भी रैजोल्यूशन आना चाहिए। ये इस बारे में गलत बातें कहकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : चेयरमैन सर, मैं भी इस बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : गौतम जी बोलें, आप क्या बोलना चाहते हैं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, इनको जो भी बोलना है वह मेरे बाद बोल लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दी जाए। (विघ्न)

श्री सभापति : ठीक है, गौतम साहब आप बाद में बोल लेना।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : सभापति महोदय, इन्दौरा जी इस रैजोल्यूशन के माध्यम से सरकार में खोट ढूंढना चाहते हैं, जो कि इनको मिलेगा नहीं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : मैं किसी भी सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं अपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री सभापति : इन्दौरा जी, आप कोई हैल्दी सुझाव दें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, मेरे गैर सरकारी संकल्प में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल तथा अकुशल श्रमिक वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं। मैं एस०ई०जैड० के बारे में यह नहीं कह रहा हूं कि उनसे रोजगार नहीं मिलेगा, अगर उनसे रोजगार मिलता है तो अच्छी बात है। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो इतना कहना है कि इस बारे में स्पष्ट किया जाए क्योंकि एस०ई०जैड० को यह सरकार बड़े जोर शोर से बढ़ावा दे रही है। चेयरमैन सर, मेरा तो विनम्र अनुरोध यही था कि इस के साथ-साथ सरकार कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दे क्योंकि अगर एस०ई०जैड० ही बनते चले गए तो गांवों के जो परम्परागत उद्योग हैं वह खत्म होते जाएंगे। इन हैरीटेज

को बचाने का काम हमारा है। अगर एस०ई०जैड० बनते चले गये तो कल को गांवों के अंदर कोई काम नहीं मिलेगा। मजदूर पिस कर रह जाएगा। मेरा पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से यही कहना है कि आपको भी अपनी बात कहने का पूरा वक्त मिलेगा। आप दो घंटे, चार घंटे या अगले हफ्ते तक इसको कैरी कर लीजिए। चेयरमैन सर, मेरा यही कहना था। आप मेरी मंशा पर शक न करें। मुझे एक शंका हुई तो मैंने उसको सदन के सामने रख दिया। चेयरमैन सर, सरकार बड़े दबंग दावे कर रही थी कि एस०ई०जैड० से बीस लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री सभापति : इन्दौरा जी, यह तो सरकार कई बार बता चुकी है शायद आपने ध्यान नहीं दिया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : कोई बात नहीं सर, सरकार आज भी बता देगी। हम तो जनता की बात कर रहे हैं। अगर ये इस बारे में जनता को बता दें तो ठीक रहेगा। चेयरमैन सर, इस तरह की सारी बातें ही गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कही जाती हैं।

श्री सभापति : आप कोई सुझाव तो दें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, मैं अपना वाक्य तो पूरा कर लूं। मैं एस०ई०जैड० के बारे में कह रहा था कि इससे व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। लेकिन अगर इन एस०ई०जैड० को किसान की खेती योग्य जमीन पर बना देंगे तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। इतने सारे एस०ई०जैड० एन०सी०आर० के नजदीक बनेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। एन०सी०आर० के नजदीक तो बड़े-बड़े उद्योगपति या मल्टी नैशनल कम्पनीज अपने-अपने एस०ई०जैड० बनाने का लालच देंगी क्योंकि वहां पर उनका व्यापार बढ़ेगा। लेकिन चेयरमैन सर, एन०सी०आर० के नजदीक तो वैसे ही बहुत डिवैल्पमैंट हो जाती है सरकार को वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन साहब, जैसा मांगे राम जी ने कहा कि कृषि योग्य भूमि पर एस०ई०जैड० नहीं बनाए जाएंगे लेकिन मुझे याद है जब मैंने एक सवाल के जवाब में श्री लछमण दास अरोड़ा जी से पूछा था कि क्या हरियाणा प्रदेश में वेस्ट लैंड है तो उन्होंने बताया था कि ऐसी भूमि न के बराबर ही है। इसका मतलब तो यह है कि एस०ई०जैड० जो बनेंगे वह कृषि योग्य भूमि पर ही बनेंगे। अब जो एस०ई०जैड० के ढेरों प्रस्ताव लाए जा रहे हैं इनका मकसद हमें समझ में नहीं आ रहा है। चेयरमैन सर, जो कुटीर उद्योग हैं वे ग्रामीण अंचल को विकास दे सकते हैं। अगर गांवों के विकास पर कुठाराघात होगा तथा यदि गांवों के मजदूरों का, किसानों का शोषण करते हुए एस०ई०जैड० बनाए जाएंगे तो इससे ये और ज्यादा गरीब हो जाएंगे।

श्री सभापति : इन्दौरा जी, डिज्नीलैंड का क्या मतलब है?

श्री सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, आपके पास रिकार्ड है मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। चेयरमैन सर, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े कारखाने लगाकर चाहे सूई का कारखाना हो, चाहे जूती बनाने का कारखाना हो, चाहे कपड़े बनाने का कारखाना हो, इनसे गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। चेयरमैन सर, मैं यह नहीं कहता कि देश के विकास को टाटा, बिड़ला और मोदी ऊंचाईयों पर न ले गए हों लेकिन देश को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचाया है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि इनके भी बड़े-बड़े बाप आ गये। जैसे

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

रिलायंस आ गया, टी०डी०आई आ गया, नरूला आ गया, डी०एल०एफ० आ गया। सट्टे के बाजार में व्यापारी रातों-रात करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं और बिना खून पसीना बहाये ही अरबपति बन जाते हैं और मजदूर वर्ग के लोग उनकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। (विघ्न) इस तरह के सट्टे के व्यापारी कुटीर उद्योग के लोगों का हक मार रहे हैं। सभापति महोदय, हमें उनको रोकना होगा। हमें ऐसी नीतियां अपनानी होंगी जो कि श्रमिक वर्ग की तरफ आंख उठाकर देखती हों और श्रमिक वर्ग सरकार की तरफ देखे और सोचे कि उसको इस सरकार के माध्यम से रोजगार मिलेगा, उसकी आजीविका का साधन चलेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : सभापति महोदय, इनकी सरकार के वक्त में सिरसा में बड़े स्तर पर सट्टे का व्यापार चलता था जिसको श्री ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद प्राप्त था। उस समय इन्होंने कितने व्यापारी मारे। बहुत सी सट्टे की दुकानें खुलवा रखी थी।

श्री सभापति : ये कह रहे हैं कि उस बात को छोड़ो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, इस सरकार ने तो यहां तक कर दिया कि खुदरा व्यापारी को भी छुट्टी दे दी। छोटे दुकानदार कहां जाएंगे, जो छोटी-छोटी सी दुकानें खोलकर बैठे हैं, वे कहां जाएंगे। वर्तमान सरकार तो सिर्फ बड़े औद्योगिक घरानों को ही प्राथमिकता दे रही हैं जो किसान सुबह सब्जी लेकर मंडी में बेचने के लिए निकलता था और शाम तक उस सब्जी को बेचकर अपना गुजारा चलाता था, वह तो असहाय हो गया। जो दुकानदार छोटे से मकान में 200-400 रुपये लगा कर छोटी सी दुकान खोल लेता था वह अब कहां जाएगा, ऐसी कोई नीति सरकार को अपनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों का कामकाज चलता रहे। अगर औद्योगिक घराने मोटा पैसा लगाकर एक व्यापार में आएंगे तो क्या उन छोटे दुकानदारों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, जिनका सीधा संबंध कुटीर उद्योग से है, क्या वे अपना सामान बेच सकेंगे? (विघ्न)

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : सभापति महोदय, जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री सभापति : डॉ० साहब आपको इस बारे में बाद में बोलने का मौका दिया जाएगा।

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, Hon'ble member is disturbing me. (interruption) O.K. I continue my speech. सभापति महोदय, मेरी जो शंका थी, मैं जो बात कहना चाहता था वह यह है कि हरियाणा की सरकार को उस गरीब का, उस दुकानदार का हितैषी होना चाहिए और गरीब की परवाह करनी चाहिए। खुदरा व्यापारी जो काम करता है और छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों से सामान लेकर बेचता है, उनको बढ़ावा देने की स्कीम होनी चाहिए। बड़े व्यापारी मॉल खोलेंगे तो मॉल में तो समृद्धिशाली लोग ही जा सकते हैं। चेयरमैन सर, प्रदेश की सरकार विकास की उच्च दर होने का दावा करती है और वार्षिक विकास की दर को कीर्तिमान बताया गया है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह इनकी सोच हो सकती है लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तव में बेरोजगारी बढ़ी है। हौजरी के व्यापारी और पानीपत में हथकरघा उद्योग के लोग जो हैं। ये उस आर्थिक विकास की

वजह से बर्बाद हुए हैं, न की अपने कार्यक्रम से। क्योंकि ऊंची विकास दर पाने के लिए पूंजीपतियों ने सारी अर्थ-व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है। गरीब आदमी जो हथकरघा, हौजरी, कुटीर उद्योग के लोग हैं वे पिछड़ते चले गये और उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत आ रही है। सर, मैं समझता हूं कि पिछले दशक में देश में जो बेरोजगारी की प्रतिशतता थी वह तकरीबन 6 प्रतिशत थी जो वर्तमान हालात में 8 प्रतिशत से ऊपर चली गई है। मेरे पास राष्ट्रीय असंगठित उद्योग निगम की रिपोर्ट है जो हाल ही में आई थी जिसमें कहा गया है कि देश के राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत यह है कि 77 प्रतिशत लोग सिर्फ 20 रुपये दैनिक पर अपना जीवन यापन करते हैं। एक गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा और सरकार कह रही है कि श्रमिकों को काम मिला है। मेरे पास इस बारे में आंकड़े हैं उनमें कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश विकास की ओर जा रहा है (विघ्न) सर, मैं कुटीर उद्योगों के बारे में देश और प्रदेश की बात कर रहा हूं आंकड़े जो छांटने होंगे तो सरकार छांटे। मैं छांट लूंगा तो फिर सरकार क्या करेगी? (विघ्न)

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, हरियाणा में कुटीर उद्योगों की क्या पोजीशन है आप इसके बारे में सदन को बतायें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं ये फिर भटक गये हैं इनका जो प्राईवेट मैम्बर रैजोल्यूशन है वह कुटीर उद्योगों विशेषकर पारंपरिक उद्योगों के बारे में हैं जिसके बारे में इन्होंने सदन में प्रस्ताव दिया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, क्या यह प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, डाक्टर साहब को सदन में यह बताना चाहिए कि हरियाणा में कुटीर उद्योगों की हालत कैसी है? ये आसाम, तमिलनाडु के फिगर कोट करेंगे और कहेंगे कि हरियाणा में कुटीर उद्योग कम हो गये हैं।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, आप यह बतायें कि एस०ई०जैड० गुड़गांव में बन रहे हैं या चौटाला गांव में बन रहे हैं। आपने जो रैजोल्यूशन दिया है उस पर बोलिये। हाउस को मिसलीड मत कीजिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूं यह तो सरकार बतायेगी। मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं तो उनके आधार पर ही बता रहा हूं।

रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, माननीय सदस्य का गैर सरकारी संकल्प है वह प्रदेश के कुटीर उद्योगों विशेषकर पारंपरिक उद्योगों के बारे में हैं जिसके बारे में इन्होंने सदन में प्रस्ताव दिया है। इस बारे में इन्हें बताना चाहिए। इनके पास अगर हरियाणा के कुटीर उद्योगों के बारे में आंकड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं मैं इनको ये आंकड़े दे दूंगा। आप थोड़ा इन्तजार कर लीजिए तब तक सुन लीजिए।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, आप सुझाव दीजिए। आप उन्हीं बातों को बार-बार रिपीट कर रहे हैं इससे ज्यादा आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, हाउस में टीका-टिप्पणी करने की परम्परा हो गई है यह कोई प्रक्रिया नहीं है। (विघ्न) This is not the way. मैं देश और प्रदेश का जिक्र इसलिए करना

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
चाहता हूं कि यह आर्थिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, आपने यू०पी० और राजस्थान में कहा था उसका क्या रिजल्ट निकला। आप प्रस्ताव पर बोलिये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। मैं रैजोल्यूशन पर ही बोल रहा हूं आपको यह लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप रूलिंग दे दीजिए। (विघ्न)

श्री सभापति : बोलिये, आप क्या कहना चाहते हैं?

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अच्छे सुझाव दे। हम भी सुझाव देंगे। (विघ्न) मुझे नेम करके धक्के देकर बाहर निकाला गया और फिर मेरे पास प्रार्थना आई कि आप वापिस आ जाओ और मैं वापिस आ गया। मैं तो नारे लगाते हुए हाउस से बाहर चला गया था। (विघ्न) सभापति महोदय, अब भी अगर आप कहें तो मैं चला जाऊंगा। मुझे चेयर की तरफ से जो आदेश होगा मैं उसको सिर माथे करूंगा। सभापति महोदय, अब मैं देश की कुछ बातें कहना चाहूंगा। गत वर्षों में सरकार ने ऐसे कई उद्योगों में विकास किया जिन्होंने देश को ऊंचाईयों पर पहुंचाने का काम किया है लेकिन इससे गरीब श्रमिक का और गांव में रहने वाले का कोई खास लेना देना नहीं है। इससे गरीब आदमी को कहीं उम्मीद नहीं है कि इन उद्योगों से मिलने वाली रोजी-रोटी से उसका काम चल सकेगा। आज के दिन आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए जो काम किए गए हैं उसमें कई उद्योग हैं जैसे दवा निर्माण, ऑटो निर्माण आदि। आटो निर्माण में जैसे अभी पिछले दिनों टाटा कम्पनी ने सवा लाख रुपये में लखटकिया कार की बात की थी। सूचना प्रोद्योगिकी, संचार, मनोरंजन और बैंकिंग ये आज के युग में ऐसे-ऐसे उद्योग आ रहे हैं जिनका देश में असर पड़ने के साथ-साथ उनका असर हमारे प्रदेश में भी पड़ेगा और ये देश की आर्थिक वृद्धि दर को निर्धारित करने का काम करते हैं। (विघ्न) हमने इन्फर्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी में भी बहुत उन्नति की है और अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने चंडीगढ़ में भी आई०टी०पार्क बनाने की बात की थी। सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि हमने प्रगति नहीं की, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने प्रगति की है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आज पूरी दुनिया छोटी हो गई है। पहले अमेरिका जाना हमारे लिए एक सपना होता था। आज ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से व्यापार के लिए आने जाने के रास्ते बढ़े हैं। हमने हर तरफ विकास किया है। ऑटो मार्कीट में हमने बहुत उन्नति की है। सभापति महोदय, इन क्षेत्रों में उन्नति करते-करते हम दिशाहीन हो गए हैं और हम भटक गए हैं और कृषि के क्षेत्र को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, हम कृषक को भूल गए हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए हमें कृषक की तरफ भी ध्यान देना होगा और उसकी लागत मूल्य को हम कम करते और उसके साथी दस्तकारों का भी हम ध्यान रखते तो ज्यादा अच्छा होता। पहले जिस आदमी को खेत में मजदूरी मिल जाती थी वह अपनी अजीविका चला लेता था लेकिन आज उसको शहर में भी मजदूरी नहीं मिलती और वह रोजगार ढूंढता रह जाता है तथा बेचारा भूख से तड़पता रह जाता है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो औद्योगिक आधार पर देश के व्यापार के लिए मापदंड बने हैं इससे

केवल मुट्ठी भर लोगों को फायदा होगा। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि अर्थ व्यवस्था के विकास को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका लाभ कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रहकर समाज के सभी व्यक्तियों को बराबर रूप से मिले। यह अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि गलत बात है लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, उसका इम्पलीमैंटेशन कैसे होगा? जो लाभ मुट्ठी भर लोगों के पास जाना है वह लाभ गांव के गरीब आदमी के पास पहुंचे, गांव के आम आदमी के पास रोजगार पहुंचे। सभापति महोदय, मेरी राय है कि वर्तमान अर्थनीति देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा रही है इसलिए मेरा कहना है कि देश का वास्तविक विकास उसके संसाधनों में है। हमारे देश के संसाधन उसके कुटीर उद्योग हैं जिनसे आम आदमी को रोजगार मिलता है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान सरकार की एक रोजगार योजना की तरफ दिलाना चाहूंगा कि ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गांव के गरीब लोगों को रोजगार देने की एक असफल चेष्टा सरकार की तरफ से की गई है। इसमें सरकार को देखना चाहिए कि वास्तव में कितने लोगों को फायदा पहुंचा है। इसमें जो नियम निर्धारित किए गए थे उनकी पालना भी प्रोपर तरीके से नहीं हुई है। मेरे सिरसा जिले में यह स्कीम चल रही हैं। जहां पर किसान के खेत होते थे वहां पर जोहड़ खोद दिए गए। यह योजना प्रदेश में पहले दो जिलों में चल रही थी अब इसको चार जिलों में किया जा रहा है। क्या बाकी जिलों में गरीब आदमियों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए?

श्री फूलचंद मुलाना : सभापति महोदय, ये बजट पढ़कर देखें। अब यह स्कीम पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, यही बात मैं इनसे कहलवाना चाहता हूं लेकिन जिस समय इनको कहनी चाहिए उस समय कहें लेकिन पता नहीं इनको किस बात की जल्दी है। ये पहले ही बोल पड़ते हैं, इनको धैर्य रखना चाहिए। सभापति महोदय, इस बारे में सी०ए०जी० की रिपोर्ट क्या कहती है उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। इस स्कीम का कियान्वयन कैसे हुआ है, उसको दो साल के करीब हो गये हैं। उसमें सच्चाई कितनी है यह तो सरकार अपने जवाब में बता दे। लेकिन सी०ए०जी० की रिपोर्ट में लिखा है कि इस स्कीम के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की निर्धारित राशि थी उसमें से 3 प्रतिशत लोगों को 18 दिन के लिए रोजगार मिला। जिसके हिसाब से तकरीबन 100 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। इसके अलावा जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए था वह पैसा कहां गया, कौन खा गया यानि कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इसलिए सरकार इस तरफ ध्यान दे। सभापति महोदय, मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दे। सरकार को पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी का नारा देना चाहिए। कुछ आईटम ऐसे हैं जिनको कुटीर उद्योगों के तहत बनाने के लिए हमें जरूरत के तौर पर लाना होगा और कुटीर उद्योगों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक मदद को भी बढ़ाना होगा। सभापति महोदय, पिछले तीन साल से सरकार कह रही है कि वे गांवों में 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन आज के दिन गांवों में पांच-पांच, सात-सात घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। अगर कुटीर उद्योगों को बिजली नहीं मिलेगी तो वे कैसे चलेंगे। सरकार तीन साल से कोशिश कर रही है लेकिन किसी को भी बिजली नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, आप सभी जानते हैं कि कहीं भी विकास

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

के लिए पानी चाहिए होता है लेकिन आज के दिन प्रदेश में बहुत सी जगहों पर पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है तो विकास कहां से होगा। जो गांव नहरों की टेल पर बसे हैं वहां भी नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा है तो लोग वहां कैसे रहेंगे? सरकार का दायित्व है कि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा करे। आज के दिन प्रदेश में न पीने के लिए पानी है, न सिंचाई के लिए पानी है, न बिजली है और न सड़कें हैं। इसलिए सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना होगा और आधारभूत ढांचे को सुधारना होगा तभी जाकर गांवों में कुटीर उद्योग लगेंगे और उनको बढ़ावा भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त कच्चा माल सस्ते में उपलब्ध करवाना होगा और जो तैयार माल होगा उसको बेचने की भी व्यवस्था करनी होगी। सभापति महोदय, एक तरफ हम एजूसैट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ओवरसीज इम्पलोयमैंट स्कीम के तहत मजदूरों को विदेशों में भेजने की बात भी करते हैं। इसके बजाय सरकार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनमें तैयार माल को एक्सपोर्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचती? अपने कुशल कारीगरों को विदेश भेजने के बजाय अगर हम उनको यहीं कुटीर उद्योगों में काम

12.00 बजे

देकर उनमें बने माल को एक्सपोर्ट करके उनसे यहां लाभ लेना चाहें तो उन द्वारा बनाये गये माल को विदेशों में निर्यात करके उनको अच्छे आमदनी के साधन और मुनाफा दिला सकते हैं और इससे उनको रोजगार भी मुहैया कराया जा सकता है। इससे कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है। सर, मेरा सुझाव है कि कुटीर और लघु उद्योगों के लिए सस्ते और सुलभ कच्चे माल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष तौर से आर्थिक सहायता के साथ-साथ संसाधनों की भी जरूरत है। मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाये जिसमें इस पर चर्चा हो कि किस प्रकार से कुटीर उद्योगों को बढ़ाया दिया जाये। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लैवल पर एक कमेटी बनाई जाये जिसमें वहां बैठकर लोग चर्चा करें कि कैसे इन लोगों को लाभ हो सकता है, कैसे हथकरघा उद्योग बढ़ सकता है और कैसे पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है?

श्री सभापति : डॉ० साहब आप अपने सुझाव भी तो दो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैंने अपना सुझाव दे दिया है कि इस विषय पर एक कमेटी बनाई जाए। मैंने यह भी कहना है कि कुछ आईटम को तो कुटीर उद्योगों में ही मिलाना चाहिए। उसकी परिभाषा ही कुटीर उद्योग के साथ जोड़कर कर दी जाये। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, इस प्रकार से अनेक प्रयास होने चाहिएं। चेयरमैन सर, इसी अनुरोध के साथ मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही लोक महत्व का विषय है। मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि वे इस बारे में अपने विचार रखें। इसके साथ ही मैं सदन का और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का पूरा मौका दिया और इसी के साथ सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह जो गैर सरकारी प्रस्ताव है वह इसको अडॉप्ट करे और इस पर कार्यवाही करें। इसी के साथ मैं यह प्रस्ताव मूव करता हूं। धन्यवाद सर।

Mr. Chairperson : Motion moved—

"This House expresses its great concern over the continuous demotion of the cottage industries, particularly traditional industries in the State as the cottage industry is only capable to provide

employment to the skilled and unskilled labourer class of the rural areas of the State."

श्री शादी लाल बतरा (रोहतक) : सभापति महोदय, डॉ० इन्दौरा ने आज इस सदन में जो प्रस्ताव रखा कि हरियाणा में कुटीर उद्योग खत्म हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है इसमें शायद इन्होंने सारे वाक्यात का जायजा नहीं लिया। पूरे हालात का जायजा नहीं लिया और किस साल की बात ये कर रहे थे और आज हम कौन से साल में हैं इसका भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, 1966 में हरियाणा बना उस वक्त हरियाणा की कुल आबादी 91 लाख थी और आज हरियाणा की आबादी 2.35 करोड़ हो चुकी है। उस वक्त हरियाणा में कौन से उद्योग थे और आज कौन से उद्योग हैं। इसके क्या कारण थे? उस वक्त हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय क्या थी और आज मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय क्या है? इन सब बातों का भी जिक्र नहीं किया गया है। उस वक्त हमारी प्रति व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी क्या थी और आज प्रति व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी क्या है इसका भी जिक्र नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी किसी चीज का फैसला करना होता है तो उससे पहले वाले समय के साथ उसका मुकाबला किया जाता है कि पहले क्या था और आज क्या है और अगर कमी आई है तो क्यों आई है और अगर बढ़ौत्तरी हुई है तो क्यों हुई है। सबसे पहले आज अगर हम शिक्षा के क्षेत्र को लें तो शिक्षा के क्षेत्र में जब श्री राजीव गांधी ने कम्प्यूटर का प्रबन्ध करने के आदेश दिये और यह कहा है कि कम्प्यूटर का प्रयोग बड़े पैमाने पर होना चाहिए तो कुछ विपक्षी नेताओं ने यह कहा था कि अगर हिन्दुस्तान में कम्प्यूटर आ गया तो कितनी आबादी बेरोजगार हो जायेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और जैसे हिन्दुस्तान में पहले ही बहुत ज्यादा बेरोजगारी है कम्प्यूटर के आ जाने से यहां पर एक प्रकार से नाश ही हो जायेगा। उनका कहना था कि कम्प्यूटर के आ जाने से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जायेगी और जब कम्प्यूटराईजेशन हुआ तो उससे हमारा लाईफ स्टैण्डर्ड क्या हो गया और इससे कितनी एम्पलायमैंट बढ़ी इसके लिए इन्दौरा साहब ने कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद इन्होंने यह कहा है कि प्रदेश में एस०ई०जैड० आ रहे हैं। एस०ई०जैड० की जो शुरूआत हुई थी वह मौजूदा सरकार के समय में न होकर पिछली सरकार के समय में हुई थी। उन्होंने ही एस०ई०जैड० के लिए भूमि का अधिग्रहण भी किया था और आज की मौजूदा सरकार ने कहा कि नहीं हम एस०ई०जैड० के लिए कोई जमीन अधिग्रहण नही करेंगे। अगर कोई भी एस०ई०जैड० आता है तो वह किसानों से बात करके सीधे जमीन ले सकता है। इसके लिए वह अपने स्तर पर बात कर ले। यह उनके व्यापार की बात है। डॉ० इन्दौरा यह कह रहे थे कि एस०ई०जैड० आ गये लेकिन इन्होंने एक बात और नहीं सुनी कि हिन्दुस्तान की आजादी के समय हमारे पास किसानों के पास जमीन कितनी थी और उस आजादी के बाद जब सिक्योरिटी ऑफ लैण्ड टैन्योर एक्ट आ गया और सीलिंग लग गई और सीलिंग लगने के बाद आज किसानों के पास जमीन बहुत कम रह गई है। किसी के पास आधा एकड़, किसी के पास एक एकड़ और किसी के पास दो एकड़ जमीन बची है। इतनी थोड़ी जमीन में खेती नहीं हो सकती। लेकिन उसको साधन देने होंगे ताकि वह आगे बढ़ सके और अपने परिवार का गुजारा कर सके तथा समाज की मुख्य धारा में रह सके। चौटाला सरकार तो यह चाहती थी कि मुख्य धारा से कितने लोग कटें। कितने लोग चाकू से, पिस्तौल से और

[श्री शादी लाल बत्तरा]

कट्टे से गुजारा करके आयें और हमें भी खिलाएं। इन्होंने ग्रामीण अंचल का सहारा लिया। ग्रामीण अंचल में शिक्षा कम थी और वे लोग जल्दी भटक जाते थे। हरेक नौजवान को कहते थे कि यह लो पिस्तौल और लूटकर लाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। इनका ध्यान कुटीर उद्योग की तरफ था ही नहीं। इनका ध्यान तो एक ही तरफ था कि इस स्वर्ग को इस समाज को नेस्तनाबूद करना है। पहले कुटीर उद्योग क्या था? ये कहते हैं कि जूती बनती थी और उसके बाद क्या होता था, कुछ भी नहीं। आज किसान की बात की जाये तो कुटीर उद्योग के रूप में मशरूम की खेती होती है। शहद का उत्पादन शुरू हो गया है। उसके बाद अगर उनकी पैकिंग करके शहरों में भेजते हैं तो यह कम्पीटीशन कहा जाता है। इन्दौरा जी, हकीम की बात कर रहे थे लेकिन अब लेटैस्ट टैक्नोलॉजी आ गई है, बाईपास सर्जरी आ गई है। अगर आप पहले की नवजात बच्चों की मृत्यु दर देखें तो पायेंगे कि पहले बहुत ज्यादा थी लेकिन आज एक लाख पर 222 रह गई है। उसी प्रकार प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर देखी जाये जो पहले एक लाख पर 300 थी लेकिन अब एक लाख पर 145 रह गई है। हकीम के पास जायें लेकिन हकीम के पास वह टैक्नोलॉजी नहीं है। एक बार एक आदमी एक हकीम के पास अपनी भैंस को लेकर गया। उसका गला सूजा हुआ था। हकीम ने देख लिया कि इसके गले में खरबूजा फंसा हुआ है। उसने एक ईंट उठाई और भैंस की गर्दन पर मार कर उस खरबूजे को फोड़ दिया और भैंस ठीक हो गई। उस आदमी ने सोचा कि हकीम बनना तो बहुत आसान है। कुछ दिन के बाद दुर्भाग्य से उस आदमी की मां बीमार हो गई। उस आदमी ने सोचा कि इस काम के लिए हकीम के पास जाने की क्या जरूरत है, उसने एक ईंट उठाई और अपनी मां की गर्दन पर मार दी उसकी मां की मौत हो गई। अब आप ही बताइये कि हकीम के पास जायें या लेटेस्ट टैक्नालॉजी के पास जायें। मेरे विचार में जो बीमारी है पहले उसके कारण का पता लगना चाहिए तब ही बीमारी का इलाज किया जा सकेगा। पहले कहते थे कि फलां आदमी बैठे-बैठे मर गया बेचारे की किस्मत अच्छी थी। यह कोई नहीं जानता था कि हर्ट-अटैक से मौत हुई है। आज वह जमाना नहीं रहा, आज हमें जमाने के साथ बदलने की जरूरत है। इसी तरह से शिक्षा के बारे में कहा गया। इन्दौरा जी कैसी शिक्षा चाहते हैं? ये 20वीं सदी की बात कर रहे हैं या 21वीं सदी की बात कर रहे हैं या आने वाले समय की बात कर रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि आने वाले समय में अपनी आजीविका कैसे कमाएं? आज कम्प्यूटर का जमाना है, टैक्नोलॉजी का जमाना है। अगर हमें दुनिया के मुकाबले में ऊपर जाना है तो उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। ऐसी शिक्षा देनी होगी जो हमें आगे ले जाये। एक बात इन्दौरा जी ने अवश्य ठीक कही है कि दुनिया छोटी हो गई है, ग्लोबलाईजेशन आ चुका है तो क्या ग्लोबलाईजेशन में हम अपने आपको फिर आईसोलेट कर दें, अपने आपको रोक लें कि हम एक गांव में बैठे हैं और हमें कुटीर उद्योग से आगे नहीं जाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरा हिन्दुस्तान पीछे आ जायेगा और दुनिया में इसका कोई स्थान नही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें कोई भी निर्णय लेना है तो हमें देखना होगा कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है और यह देश क्या कर रहा है और हम अपने देश को कहां पर ले जाना चाहते हैं। यहां पर विशेष आर्थिक जोन की बात चल रही थी। अध्यक्ष महोदय,

माननीय मुख्य मंत्री के साथ मुझे भी चीन जाने का मौका मिला था। वहां सेज को देखने के बाद उनके जो कमैंट्स थे, मैं आपको वे कमैंटस भी कहना चाहता हूं। उनके कमैंट्स थे कि आज इंडिया में इतनी शिक्षा आ गई है, आज इंडिया का नौजवान इतना सक्षम हो चुका है कि वह अपने घर में बैठकर अपना काम चला रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर आज इन्डस्ट्री चाईना में है तो ऑफिस इण्डिया में है और वह अपना बिजनैस इण्डिया से ही कण्ट्रोल कर रहा है। सभापति महोदय, चाईना में अंग्रेजी की कोई शिक्षा नहीं थी, कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं थी और उसने जितना भी इम्प्लॉयमैंट लेना था वह यहां पर बिना अंग्रेजी या कम्प्यूटर की शिक्षा के ही लिया था। यही कारण है कि आज गुड़गांव में कितने ही कॉल सैंटरज हैं। इन कॉल सैंटरज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वे कहां से आते हैं। यह ठीक है कि वहां पर आज बच्चे देहली से काम करने के लिए जा रहे हैं। क्या हम यह न सोचें कि दिल्ली की जो शिक्षा है उसी तर्ज पर हम अपने शहरों में भी शिक्षा को इम्प्रूव करें। अगर हम अपने बच्चों को टैक्नीकल एजुकेशन दें तो हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं वे वहां पर काम कर सकेंगे। अगर कॉल सैंटर गुड़गांव में है और वहां पर काम करने के लिए देहली के बच्चे आते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि चाहे गांव हो या शहर हो हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएं। इस मौजूदा सरकार ने शिक्षा तथा टैक्नीकल ऐजुकेशन में पहले से तीन गुणा बजट कर दिया है। इस बजट को तीन गुणा करने के पीछे अभिप्राय एक ही है कि ग्रामीण नौजवान को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे अपना रोजगार हासिल कर सकें। यही वजह थी कि पहली क्लास से इंग्लिश में पढ़ाई शुरू कर दी ताकि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि आगे चलकर वे अपने आप को अच्छा नागरिक साबित करें और अपनी आजीविका के लिए बाहर निकल कर काम करने में पारंगत हो जाएं। आज डाक्टर इन्दौरा साहब यह प्रस्ताव लाए हैं--

> "This House expresses its great concern over the continuous demotion of the cottage industries, particularly traditional industries in the State as the cottage industry is only capable to provide employment to the skilled and unskilled labourer class of the rural areas of the State."

अब मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। आज के युग में सिर्फ कॉटेज इन्डस्ट्रीज इम्पलॉयमैंट नहीं देगी। कॉटेज इण्डस्ट्रीज से आगे बढ़ना सम्भव होगा। सभापति महोदय, मौजूदा सरकार ने आदर्श गांव बनाने का निर्णय लिया था। जब आदर्श गांव बनाने का निर्णय लिया था तो उस वक्त एक सोच आई थी कि क्या गांव में गलियां पक्की कर देने से आदर्श गांव बन जाएगा। वहां पर सीवर और पानी दे दें तो क्या गांव आदर्श गांव बन जाएगा लेकिन उसके साथ ही साथ एक सोच यह भी थी कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो उसकी आय के साधन बढ़ने चाहिएं। जब आय के साधन बढ़ाने की स्टडी की गई तो फिर यह बात सामने आई कि अगर हम ऐसा कर भी दें तो हम गांव में कम्पीट नहीं कर पाएंगे इसलिए उसको आगे बढ़ाना होगा। गांव में जो भी सामान बनेगा वहां गांव में उसकी कन्जम्पशन नहीं होगी और उसके लिए शहर में आना होगा। शहर में आ कर दूसरी जगहों पर भी अपना उत्पादन बेचना होगा। एक सवाल यह भी था कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी और शहर वालों

[श्री शादी लाल बत्तरा]

की कॉस्ट आफ प्रोडक्शन क्या होगी। अगर शहर वाले गांव में जाकर सामान बनाते हैं तो उनको ज्यादा लाभ मिलता है क्योंकि उनके पास अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है। मौजूदा सरकार इस बात को बड़ा ऐन्क्रेज कर रही है कि कोई भी आदमी वहां पर अपना काम करे। क्योंकि वहां पर गांव में कोई व्यवस्था नहीं है और जो नई पीढ़ी आई है जो नई पीढ़ी चली है उसकी सोच बदली है और वे कहते हैं कि हमें काम करना है और काम करके आगे बढ़ना है। यह जो हमारी जमीन थी पहले वे उस जमीन के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि जमीन की होल्डिंग इतनी थी कि वे खेती का काम करते थे और साथ ही दूसरे काम भी कर लेते थे। आज वे कहते हैं कि जमीन बची ही नहीं इसलिए हमें बाहर निकलना ही होगा। आज हमें बच्चों को आगे शिक्षा भी देनी है ताकि वह शहर में जाकर वहां पर अपना काम कर सकें। आज हरियाणा में देखें तो चाहे कोई भी गांव ले लीजिए हर गांव में वह सुविधा उपलब्ध होगी जिसके चलते हम अपना जीवन सुविधा से बिता सकेंगे और यह ठीक भी है। मैं मौजूदा सरकार का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने यह सोचा कि आदर्श गांव हों एल०ए०डी०टी० के साथ 10-10 लाख रुपये हों। जिस जिले में वाटर वर्क्स का पानी न हो वहां पर पानी की सप्लाई हो, सड़कें और स्कूल बन गए हैं। अब कितने स्कूल अपग्रेड हो गये? उसके लिए यहां पर टैक्नीकल ऐजुकेशन के लिए ग्रामीण अंचल में काफी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं उनके पीछे एक ही कारण था कि अगर हमें हरियाणा का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा। अगर हमने हरियाणा में हर व्यक्ति को आगे ले जाना है तो पहले हमें गांव के किसान और मजदूर को आगे ले जाना होगा क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हमें जमाने के साथ तबदील भी होना होगा। जमाने के साथ हमें तबदील होना पड़ेगा लेकिन हम अपने आप को यहीं तक सीमित न करें। आज एक ही कमरे में बैठकर जूती नहीं बन सकती है। जूती बनाने के लिए अगर हमें काम करना है और अगर जूती बनानी है तो उसके काम की पूरी स्टडी करनी होगी। आज जूती बनाने के भी कई पोर्शन और कई प्वायंट्स होते हैं। कोई सोल बना रहा है, कोई जूती सियेगा, कोई आगे का काम करेगा और उस जूती के आगे ऐम्ब्रॉयडरी भी हो रही है। उसी जूती पर अलग-अलग कलर भी हो रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कीमत बाजार से मिल सके और बाजार में कीमत भी मिलती है। जब उसका काम करते हैं तो सारे मामले पर सोच-विचार कर यह देखना होता है कि उस पर आगामी प्रभाव क्या पड़ेगा उसकी कीमत क्या हो, यह सोच कर ही इस बारे में कोई निर्णय लेना पड़ेगा तभी वह काम आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉ० इन्दौरा साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह प्रस्ताव आज की जरूरत के मुताबिक ठीक नहीं हैं, उनको भी अपने आपको तबदील करना होगा और मुकाबले के लिए आगे आना होगा। अगर हम यह कहें कि यह ठीक है और हमें यहां पर जूती बनानी है तो जूती में आगे जितना डिवैल्पमैंट हुआ है जितना रिसर्च कार्य हुआ है उस सारी रिसर्च का प्रयोग करके कम्पीटीटिव प्राईस पर जूती भी बनेगी और उसको बाहर भी भेजेंगे ताकि लोग उसको पसन्द भी करें। इसी तरह से यहां पर किसानों की बात हुई थी तो किसानों के लिए केन्द्र की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी की घोषणा की है लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार ने भी लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत कोआप्रेटिव बैंकों के ऋण माफ किए हैं। उन किसानों द्वारा कर्जा लेने के पीछे मजबूरी थी और वह

मजबूरी क्या थी कि उन किसानों की इन्कम नहीं थी और उनकी पैदावार न होने की वजह से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। अगर गुजारा नहीं होगा तो वे कर्जा ही लेंगे। सभापति महोदय, हरियाणा की सरकार ने, केन्द्र की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया कि अगर हमें प्रदेश और देश को आगे ले जाना है तो हमें किसानों और मजदूरों को ऊपर उठाना होगा। इस वजह से इन्होंने ये कर्जे माफ करने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान और मजदूर समाज की मुख्य धारा में रहें। अगर वह समाज की मुख्य धारा में रहेगा तो देश और प्रदेश का काम अच्छी तरह से चल सकेगा। सभापति महोदय, यह जो किसानों और मजदूरों के लिए फैसला लिया गया है यह बहुत ही लोकप्रिय फैसला है। इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांध ी जी का, मनमोहन सिंह जी का और हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का ध न्यवाद करता हूं। आज शिक्षा में भी गरीब लोगों के लड़कों और लड़कियों को 100 रुपये और 150 रुपये प्रति माह छात्रवृति दी जा रही है। आज सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से गरीब आदमी मुख्य धारा में आया है। सभापति महोदय जी, यह जो गैर सरकारी संकल्प डॉ० सुशील इन्दौरा जी लेकर आए हैं इसमें इनको चेंजिज लानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इसमें केवल एक दो सुझाव ही देना चाहूंगा। सभापति महोदय, जब मैं 2005 में चुनकर आया था उस वक्त भी मैंने यह सुझाव दिया था। आज जमीन में जो खाद डाली जा रही है उसकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज जमीन में डी०ए०पी० और यूरिया डाली जाती है। अगर हम यह खाद न डालें तो उपज कम होती है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस खाद की वजह से हमारे नौजवानों में हार्ट-अटैक की बीमारी फैलती जा रही है। हमारे एक 30 साल के नौजवान साथी को इन खादों की वजह से हार्ट-अटैक हो गया है। इन खादों में जहर की मात्रा है जो हमारे शरीर में जा रही है। सभापति महोदय, आजकल एक केंचुआ खाद चल रही है और जिन किसानों के पास कम भूमि है वे उसका प्रयोग करें तो उनकी फसल पहले से डयोढ़ा होगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि सरकार की तरफ से इस केंचुआ खाद की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम यह जो जहर आज यूरिया और डी०ए०पी० के माध्यम से खा रहे हैं आने वाले समय में वह न खाएं। सभापति महोदय, मेरा सरकार को यही सुझाव था। धन्यवाद।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, हमारे साथी सुशील इन्दौरा जी ने गैर सरकारी संकल्प में कुटीर उद्योग का विषय तो बहुत अच्छा लिया है। मेरे काबिल दोस्त की मंशा इस संकल्प के माध्यम से सरकार में खोट ढूंढने की है जो कि इनको नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, कोटेज इन्डस्ट्री क्या है इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि the cottage industry is a term that was used prevalently during the 18th and 19th Century to describe the home-based system of manufacturing. This term is also usually, referred to goods or services that produced at home. जैसे सिलाई की, क्राफ्टिंग की, मार्केटिंग की, टाईपिंग की, बुक कीपिंग की और रिपेयर की जितनी भी ये सारी चीजें आती हैं वे सारी की सारी कुटीर उद्योगों में आती हैं। **(इस समय**

[डॉ० शिव शंकर भारद्वाज]

श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, दो और टर्म्ज हैं जो कुटीर उद्योगों के साथ की है। एक को हम कहते हैं एस०एस०आई० यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरी को कहते हैं टायनी यूनिट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वह हैं जो एक करोड़ रुपये से कम कीमत की हैं और टायनी इंडस्ट्रीज वे हैं जो 25 लाख रुपये तक की हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि तीन साल के इस सरकार के कार्यकाल में सरकार की जो भी नीतियां रही हैं उनमें हर स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। चाहे छोटे उद्योग हों या चाहे बड़े उद्योग हों अगर बड़ा उद्योग पनपेगा तो उनके साथ उसकी एन्जलरी यूनिट्स भी पनपेंगी। स्पीकर साहब, मेरे काबिल दोस्त ने यह भी चिन्ता व्यक्त की कि जो बड़े-बड़े कारपोरेट सैक्टर आ रहे हैं वे छोटे उद्योगों पर, कुटीर उद्योगों पर कुठाराघात पहुंचाएंगे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार भी इस बारे में चिंतित है। इस बारे में प्रावधान भी है और कानून भी बनाए गए हैं, पोलिसी भी बनायी गयी है। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि the Government of India continues to provide protection to Small Scale Sector through the policy of reserving items for exclusive manufacturing in Small Scale Industries. The industrial undertakings other than the Small Scale Industrial undertakings raised in the manufacture of the items reserve for the exclusive manufacture of Small Scale Sector are required to obtain an industrial license and undertake an export of 50% or more of them. जो दूसरे सैक्टर्ज हैं जिनको लाईसैंस दिया जाएगा उनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा ऐक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में 1967 में 44 आईटम्ज थी लेकिन बाद में ये बढ़ते-बढ़ते 800 आईटम्ज हो गयी। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का ध्यान हमेशा से रखा गया है। 1967 से लेकर अब तक की सरकारों की जो पोलिसी रही है उसमें हमेशा से ही कुटीर उद्योगों का, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का ध्यान रखा गया है। मैं आपके माध्यम से अपने मित्र के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि पूरे देश में करीब 34 लाख यूनिट्स ऐसी हैं जिनको कॉटेज इंडस्ट्रीज में गिना जा सकता है और करीब 146 लाख लोगों को इनमें रोजगार मिला हुआ है। ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं these are second to give employment. इनका महत्व हमेशा भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे भिवानी में दो उद्योग ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि नैशनल लैवल पर बहुत ही प्रोमीनैंट हैं। मैं अगर यह कहूं कि ये नैशनल लैवल पर सबसे ज्यादा प्रोमीनैंट हैं तो इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी। डॉ० इन्दौरा जी जानते हैं कि वहां पर एक उद्योग तो मैडीकल साईड से ही है। इसमें ऑपरेशन की टेबल और लाईट्स बहुत अच्छे तरीके से बनायी जाती हैं। आप देखेंगे कि पूरे देश में करीब-करीब भिवानी से ही इस तरह की लाईट्स एवं टेबल सप्लाई होती हैं। भिवानी में इस तरह के उद्योग घर-घर लगे हुए हैं। इसका रॉ मैटीरियल करीब-करीब भिवानी में ही मिलता है। जब बड़ी-बड़ी कांफ्रैंसिज होती हैं जैसे ऐसोसिएशन सर्जज ऑफ इंडिया या एनेसिथिजिया तो उनमें भी भिवानी के ही लोग अपने-अपने स्टॉल लगाते हैं। काम्नेट कम्पनी तो एक ऐसी कम्पनी है जो बहुत बढ़िया किस्म का माल बनाती है और मनमाने दामों पर बेचती है। इसी तरह से सर्जीडैन्ट कम्पनी है, बैको सर्जीडैन्टस कम्पनी है इस तरह से वहां पर ऐसी 150 कम्पनीज हैं जोकि वहां पर अच्छी तरह से चल रही हैं। ये पिछले बीस वर्षों से अच्छा कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से दाना एवं प्लास्टिक

निवार बनाने की फैक्ट्रीज भी 100 से ज्यादा वहां पर हैं । इनमें बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है । मेरा ख्याल है कि भावनगर और भिवानी ही दो ऐसे शहर हैं जहां पर इस प्रकार के उद्योग हैं । इस प्रकार की भिवानी की फैक्ट्री में हमारे काफी वर्कर्ज ट्रैंड हो गये हैं, स्किल्ड हो गये हैं । उनको काफी इम्प्लायमैंट इनसे मिल रही है । भिवानी की फैक्ट्री डायरैक्ट अपना माल नेपाल और मलेशिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं । निवार का जब स्कूल के थैले बनाने में, दरी बनाने में इस्तेमाल होता है तो हमारे शहर से ही जगह-जगह निवार जाती है । इन्दौरा जी की जैसे बात है, जो पारम्परिक बातें हैं जो आज भी जारी हैं । आज भी लोहार के पास कस्सी, तसला, फाली आदि सामान मिलता है । उन सब चीजों में आज भी कोई कमी नहीं आई है । हां, यह जरूर है कि अब खेती के काम के लिए ट्रैक्टर आदि बहुत ज्यादा हो गए हैं इसलिए थोड़ी बहुत औजारों की संख्या में कमी अवश्य आई है लेकिन आज भी उनकी जरूरत है और आज भी वे बनते हैं । बड़े उपकरण आ जाने की वजह से भी नैचुरली कमी आना स्वाभाविक है । अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में एक गांव बीरन है वहां कई वर्षों से आज भी लकड़ी के मनिए बनते हैं वे सब के सब उसी प्रकार से आज भी बन रहे हैं । (विघ्न) हमारे यहां मैडीकल इंडस्ट्री के सामान भी बनते हैं । भिवानी में हॉस्पीटल का फर्नीचर बनाने की इंडस्ट्री लग गई है और काफी अच्छे स्तर का फर्नीचर वहां बन रहा है और बन ही नहीं रहा है वरन विदेशों में भी ऐक्सपोर्ट हो रहा है । जहां तक रोजगार मामलों का जिक्र है । प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है । हमारे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों को काम मिल रहा है, हर हाथ को काम मिल रहा है । मेरे काबिल साथी ने इस बात पर शंका जाहिर की है लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का नाम हैण्डलूम उद्योग में आगे रहा है । हमारे यहां का हैण्डलूम का सामान बहुत विख्यात है और तमिलनाडु तक जाता है । इसके अलावा हरियाणा प्रदेश का स्टील जहां तक हमारा विदेशों के बारे में ऐक्सीपरियैंस है, अमेरिका में भी देखने को मिलता है । अमेरिका में मैसी स्टोर है यह ग्यारह-बारह मंजिल में बना हुआ है । उसमें जाकर मैंने देखा कि वहां जो स्टील के बर्तन थे वे हिंदुस्तान के बने हुए थे । आजकल मेरे हल्के भिवानी में कुछ इंडस्ट्री लग रही हैं उनमें प्रौडक्शन तो शुरू नहीं हुई है लेकिन उन फैक्ट्रियों को लगाने के लिए वे लोग आए हैं जो अपने प्रौडक्ट्स को आलरेडी ऐक्सपोर्ट कर रहे हैं । जैसा मेरे काबिल साथी श्री शादी लाल बत्तरा जी ने बोलते हुए बताया कि कम्प्यूटर आने के साथ-साथ काफी तरक्की आई है । आप सोच के देखें कि श्री राजीव गांधी जी सैम पित्रोदा को अपने साथ न लाते और सिर्फ परम्परागत कामों में ही लगे रहते तो आज जो टैक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, क्या वह देखने को मिलती । आज आप कहीं भी बैठे-बैठे कार में बैठे-बैठे, ट्रेन में बैठे-बैठे और यहां तक कि हवाई जहाज में बैठे-बैठे भी फोन पर बात कर सकते हैं । यह सब संभव नहीं हो सकता था ! We will have to march with the rest of the world. जो संसार की गति है, पेस है उसके साथ हम नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे । यह मैं मानता हूं कि परम्परागत चीजों को कायम रहना चाहिए और वह रहती भी हैं । सरकार की यह मंशा भी है कि उन चीजों को प्रोत्साहन मिले । बड़े उद्योग यदि आगे चलेंगे तो छोटे उद्योग भी साथ-साथ ही चलेंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं । धन्यवाद ।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : स्पीकर सर, इन्दौरा जी का जो प्रस्ताव है वह वैसे ठीक है। उनका इरादा कुछ भी रहा हो और पौलिटिकल भाषण को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो कुटीर उद्योग जो हैं उनका वाकई में देश में बहुत ही बुरा हाल है। देश में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां बहुत आ गई हैं। यह जो बेचारे आर्टिजन क्लास के लोग थे बीच में कई सरकारें ऐसी भी आईं जिनकी नीतियों की वजह से आर्टिजन क्लास को बहुत झटका लगा। समय की यह मांग है कि इन लोगों को कम से कम ब्याज दर पर लिबरल लोनिंग होनी चाहिए। सरकार को इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए और सब्सिडी भी बढ़ानी चाहिए और जो बिजली के रेट हैं जैसे किसान को जिस रेट पर बिजली मिलती है उसी रेट पर इन कुटीर उद्योग मालिकों को भी 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही बिजली मिलनी चाहिए और सबसे जो जरूरी चीज है वह कुटीर उद्योग के भाईयों के लिए है क्योंकि by and large यह लोग ज्यादातर गरीब एस०सी० और बी०सी० तबके से आते हैं। इसलिए सरकार ऐसी होनी चाहिए जो इन लोगों के पीस ऑफ माईंड के लिए खतरनाक न हो। कुटीर उद्योगों के लिए शान्ति, अमन और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। बीच में ऐसी सरकारें आई जिनकी वजह से बड़े-बड़े उद्योग तो पहले ही पलायन कर गये और छोटे जो बेचारे थे वे गांव छोड़कर कहीं शहर में बस गये वहां भी उनकी दुर्गति हुई। ये भाई माईंड न करें। झगड़ा एक आदमी का होता था लेकिन इनके चेले सामाजिक बहिष्कार करा देते थे। उनका गांव से पलायन हो जाता था। सरकार आंकड़े इकट्ठे कर ले। स्पीकर सर, by and large जो गरीब लोग हैं वे पलायन कर गये, कुटीर उद्योग के बारे में तो वे जब सोचें जब वहां पर जिन्दगी महफूज हो। वहां जो सबसे जरूरी चीज है वह इनकी पीस ऑफ माईंड है, लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजीशन बढ़िया और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। स्पीकर सर, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। लाबी गांव में बहुत मुद्दत पुराने मुजारे थे वे चौधरी देवीलाल के परिवार के मुजारे थे। जब इनैलो की सरकार आई तो इन्होंने गुण्डे बुलाकर, पुलिस बुलाकर, तहसीलदार बुलाकर उन बेचारे मुजारों को गांव से भगा दिया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ से दिल्ली जी०टी० रोड वाली सड़क बन रही थी। हमारे विपक्ष के भाई जिस पार्टी में शामिल हैं उनके नेता की सरकार थी। उन्होंने कहा कि यह सड़क कौन बना रहा है ठेकेदार को बुलाओ। ठेकेदार बुला लिया गया। उसको कहा कि तुम मेरी सल्तनत में सड़क बना रहे हो। तूने अब तक मेरे से न तो मुलाकात की और न ही मुझे अब तक नज़राना पेश किया। सड़क मेरी सल्तनत में बना रहे हो। उस ठेकेदार ने कहा कि सर, हमारे को जो कान्ट्रैक्ट मिला है वह सैन्टर से मिला है और जो हमने कमीशन देना था वह सैंटर में दे चुके हैं। सड़क का ठेका जो छूटता है वह हमारा सैन्टर से छूटता है इसलिए स्टेट से हमारा कोई कनैक्शन नहीं होता। तब उसको कहा कि तू नहीं जानता यह ओम प्रकाश चौटाला का स्टेट है। यहां अगर सड़क बनाना चाहते हो और जिन्दगी सेफ चाहते हो तो इतने करोड़ रुपये ले आना वरना सड़क को बंद कर देंगे। यह रिकार्ड की बात है उस ठेकेदार ने यह कहा कि क्योंकि आजकल क्रप्शन का जमाना है मैंने तो जो कुछ किया है वह ऊपर से ही किया है अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा और वह यह कह कर उस काम को बीच में ही छोड़कर चला गया। (विघ्न) मैं जो कुछ कहता हूं सच्चाई कहता हूं अगर ऊपर वालों ने गड़बड़ी करी होगी तो वह भी माड़ी बात ही थी। हमारी पार्टी बी०जे०पी० ने चौटाला जैसे का राज चलाया यह ओछापन नहीं था तो

और क्या था ? मैं स्पष्ट बात कहता हूं सही बात चाहे मेरे भाई की हो, चाहे और किसी की हो। उसके बाद वह ठेका मुझे एग्जैक्ट एमाउंट तो नहीं पता, पी०डब्ल्यू०डी० के भाई कैलकुलेट करके बता देंगे इन भाइयों की आखें खुल जायेंगी कि वे जिस गिरोह में विपक्ष के भाई शामिल हैं फिर कई साल तक जी०टी० रोड बनना बन्द रहा और उसके बाद कई करोड़ रुपया फालतू में लगकर बहुत साल के बाद वह रोड दोबारा बना। अध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए जरूरत है कि उनको लिब्रल लोनिंग की व्यवस्था हो, ब्याज की प्रतिशतता बिल्कुल कम हो और मैक्सीमम सबसिडी हो। गांव में कंजीनियल माहौल हो। इन उद्योगों के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वह है कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक हो। अध्यक्ष महोदय, आप इनका ब्यौरा मंगवाएं कि 5 साल में कितने गरीब गांव से उजड़ कर चले गए थे, कितने इंडस्ट्रियल यहां से प्लायन करके चले गए। जब ये सरकार में आते हैं तो आम आदमी को ऐसे डर लगता है जैसे कोई हौवा आ गया हो। कुटीर उद्योग वाले तो इनकी शक्ल से डरते हैं। मैं इन ******* भाइयों की मजबूरी समझता हूं क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूं। Basically they are very nice people. I respect them. मैं इनकी इज्जत करता हूं। (शोर एवं व्यवधान) आप तो हमारे रिश्तेदार हैं, आप तो रिश्तेदारी निभाया करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमें जो अनपार्लियामैंट्री शब्द कहा है वह रिकार्ड नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) सम्मानित सदस्य केवल अपनी बात रखें।

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप नॉन ओफिशियल रैजोल्यूशन पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम किसी के सहारे नहीं आए, हमें जनता ने चुनकर भेजा हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी ने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द का प्रयोग किया है वह रिकार्ड न किया जाए। ये तो आपको nice people कह रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से ये आपको रिलेटिव बता रहे हैं।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, सूरजभान के ये समधी हैं और सूरजभान हमारा बड़ा भाई है। ये तो गलत महकमें में चले गए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जिसको हाउस में हाजिर सभी लोग मानेंगे। कई भाई अंधेरे में डले ढोने के लिए होते हैं और उनको नोलेज नहीं होता कि इस समय घड़ी कौन सी है। मैं भी बावला था, मैं कोई सयाना आदमी नहीं हूं। मैं जब भी पोलीटिक्स में आया, मैं यूं सोचा करता था कि रामकुमार गौतम तू तो इस स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा और तू फलाने को ओ०एस०डी० लगाइए। मैं सिसक-सिसक कर छटी बार एम०एल०ए० बना हूं। 5 साल जिंदगी के मैंने सुबह से लेकर रात तक गांव में छोड़ दिए। किसी भाई के दिमाग में गलतफहमी हो कि आने वाला समय कभी भी इनका होगा तो यह कल्पना के बाहर की बात है। ये जो लोग आते थे इनका सैटिंग का फार्मूला था, चौधरी भजन लाल के बीच में और चौटाला के बीच में, That time is over. जब इनके नारे चलते थे। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : इससे कुटीर उद्योग को कोई सैट बैक पहुंचा है क्या?

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योग का नाम लेना भी इन भाइयों के महकमे के लिए माड़ा है। ये तो कुटीर उद्योग को उजाड़ने वाले महकमें के हैं। कुटीर उद्योग का इनके महकमे से क्या काम है। जो सैटिंग का समय था that time is over अब इस समय इनको नोलेज नहीं है कि इनका जो मेन नारा था, जो जातवाद का नारा था, भोले-भाले किसानों को बहकाते थे वह खत्म हो चुका है। Now, Sh. Bhupinder Singh Hooda is the Chief Minister of the State. इनको पता होना चाहिए कि कई जिलों में तो इनका बीज ही मर लिया। They are no more in those districts. लेकिन कुछ रूझान हमारी तरफ भी हुआ है, अब ये जिस बात पर लग रहे हैं उसमें कुछ नहीं निकलना। बैकवर्ड और हरिजन सम्मेलन करते हैं जो इनके नाम के साथ अच्छा नहीं लगता। इसके अतिरिक्त व्यापारी सम्मेलन करते हैं और लोगों को कहते हैं कि बी०जे०पी० से समझौता करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें एक बार जो आदमी दोस्ती में गण्डासा मरवाता है क्या वह दोबारा गण्डासा खायेगा। ये मेरे भोले-भाले साथी जो उनके पीछे लगे हैं इनको पाला बदल लेना चाहिए, नहीं तो ये भी मारे जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आगे मुझे दोबारा समय दिया जावे मैं एजूकेशन के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इन्दौरा जी ने अभी एक बात रखी कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि मोची का बेटा मोची का काम करे, लुहार का बेटा लुहार का काम करे और बढ़ई का बेटा बढ़ई का काम करे। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इन्दौरा जी को डाक्टर कहा जाता है लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि माननीय साथी आदमियों के डाक्टर हैं या पशुओं के डाक्टर हैं। क्योंकि जो बात इन्होंने कही है यह बात बिल्कुल सरकार की व्यवस्था के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीतियां उदार हैं और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी दरियादिल हैं। ये प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि चाहे लुहार का बेटा हो, चाहे कारपेंटर का बेटा हो यानि किसी भी गरीब भाई का बेटा हो वह इंजीनियर बने, पायलैट बने, डाक्टर बने या कोई बड़ा नेता बने। लेकिन इन भाइयों की सोच अनपढ़ों जैसी है मुझे समझ नहीं आ रहा इनको डाक्टर किस आधार पर कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे साथी इन्दौरा जी ने एस०ई०जैड० के बारे में जिक्र किया कि बेशकीमती जमीन पर एस०ई०जैड० सरकार लगा रही है और जहां एस०ई०जैड० लग रहा है वहां देहात के लोग क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को अवगत करवाना चाहता हूं कि एस०ई०जैड० की स्थापना मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी होने जा रही है। वहां की जो जमीन है उसमें खारा पानी है। उसको डहर की जमीन बोला जाता था जहां पर कभी बाढ़ का पानी आता था लेकिन जमीन के नीचे का पानी जहर की तरह है जिसको यदि कोई पक्षी पी ले तो वह पांच मिनट के अंदर-अंदर मर जाता है। इस तरह वह जमीन बेकार थी वहां पर कोई फसल नहीं होती थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी की सरकार के समय में भी उस जमीन को एक्वायर करने के लिए दफा-4 के नोटिस दिए गए थे और मुआवजा 2.60 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना था। इस बारे में मैंने रिकॉर्ड भी दिखलाया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी चार एकड़ जमीन थी और जब इनके द्वारा वह जमीन एक्वायर की

जानी थी जब हमने सोचा कि हम तो लुट गये, बरबाद हो गये। लेकिन परमात्मा ने मेहरबानी की और तीन महीने बाद चुनाव हो गये तथा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद उसी जमीन के 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे दिए गए हैं। जो पैसा हमें हमारी चार एकड़ जमीन का मिला है उस पैसे से हमने बाहर जाकर कुछ जमीन भी खरीद ली है, मकान भी अच्छे बना लिये हैं और छोटा-मोटा काम धन्धा भी शुरू कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कुटीर उद्योग की भी बात उठाई है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां पर एस०ई०जैड० बनेगा वहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी बनेगी। बिल्डिंग कहीं से उठाकर नहीं लाई जायेंगी, वहीं बनेंगी। जब वहां बिल्डिंग बनेंगी तो उनमें कारपेंटर को, मिस्त्री को यानि सभी मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा और जंगले लगाये जायेंगे, पर्दे लगाये जायेंगे, बिल्डिंग की फिनिशिंग भी होगी उससे कुटीर उद्योग को भी निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने कंडीशन रखी है कि एस०ई०जैड० के अंदर जो भी उद्योग स्थापित होगा उसमें कम से कम 25 प्रतिशत रोजगार लोकल श्रमिकों को मिलेगा। लेकिन आज 2.60 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने वाले लोग एस०ई०जैड० की बुराई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश में कहीं भी कैसीनो या जुआघर नहीं खोलने जा रहे हैं। प्रदेश में जो भी नई योजना आती हैं या जो भी नये उद्योग आते हैं उनमें हमारे मुख्यमंत्री जी गरीब और मजदूर भाइयों के हितों का विशेष ध्यान रखते हैं। यह जो 11 हजार सफाई कर्मचारी लगाने का फैसला सरकार ने लिया है यह ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल हैं जो कि एक ऐतिहासिक काम है। यह भी मैं माननीय सदन और सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं। इसके अलावा मैं माननीय सदन के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि जब तीन साल पहले श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो उन्होंने जोहाराबाग, झज्जर में भाषण देते हुए कहा था कि मैं आने वाली 31 तारीख से पहले इतनी बिजली दे दूंगा कि तुम बिजली बंद करना चाहोगे तो भी वह बंद नहीं होगी। यह तो पता नहीं चल पाया कि वे इतनी बिजली कहां से लाते कि बिजली बंद करने पर भी बंद नहीं होगी। इतनी बिजली देने का वायदा वे उस समय बड़े जोरशोर से कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि एक बार वोट देकर हमारी सरकार बनवा दो तो हरेक गांव में हम नोट छापने की मशीन भिजवा देंगे। कुछ बड़े-बड़े गांवों के लोग भी यह बात सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत बड़ा गांव है एक मशीन में तो पता नहीं हमारा नम्बर पड़ेगा या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि ज्यादा बड़े गांव वालों को 2-3 नोट छापने की मशीनें दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें आप सिर्फ हमें वोट दे दें। स्पीकर सर, ऐसे-ऐसे लोग जनता की आंखों में धूल झोंककर विधान सभा में आ जाते हैं। इस पर मुझे एक मिसाल याद आ रही है कि एक बार कहीं पर झूठे लोगों की एक बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो रही थी। उसमें कई बड़े-बड़े ईनाम रखे गये और यह ऐलान किया गया कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को पहला ईनाम दिया जायेगा। वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया। उस दौरान किसी ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या बात आज आप इतने लेट कैसे हो गये तो उसने कहा कि हमारे यहां बहुत ज्यादा काम है। काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि हमारे यहां इतनी बड़ी खोर (पशुओं को चारा डालने का स्थान) है कि वहां पर सारे देश के पशु एक साथ इकट्ठे चारा खा सकते हैं। इस पर दूसरे

[श्री नरेश कुमार प्रधान]

व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहां पर एक ऐसा बांस है जिससे जब हमारा दिल करता है तो राम जी (बादल) में सुराख करके बरसात करवा देते हैं। इस पर पहले व्यक्ति ने पूछा कि आप उस बांस को रखते कहां पर हो तो उसने कहा कि हम उस बांस को तुम्हारी वाली खोर में रखते हैं। स्पीकर सर, ऐसे ही ये लोग हैं। इनका नहीं पता कि ये कब और कहां किसकी खोर में अपना बांस रखकर खड़े हो जायें। इस बारे में इनका कोई जवाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री रमेश कुमार गुप्ता (थानेसर) : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, माननीय सदस्य डॉ० सुशील इन्दौरा ने यह प्रस्ताव लाकर जो कुटीर एवं लघु उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता जताई है इसका सरकार की लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण एवं कल्याणकारी नीतियों के कारण कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है जिससे कि किसी को कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन में कोई परेशानी हो। लेकिन इस ग्लोबलाईजेशन के युग में जब सारा संसार प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है तो अधिकतर छोटे उद्योग पुराने होने के कारण इस समय वायबल नहीं रह गए हैं। इसी प्रकार से जैसे पानीपत में पहले खड्डियों पर काम होता था लेकिन धीरे-धीरे उनकी वायबिलिटी खत्म हो गई तो उनकी जगह पावरलूम्स ने ले ली है। इससे रोजगार पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा हो ऐसी बात भी नहीं है बल्कि इसके उलट इस उद्योग के तहत पानीपत में रोजगार के अवसर कई गुणा बढ़े हैं और ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इसी प्रकार से और भी कार्य हैं जैसे कि एस०ई०जैड० की स्थापना का प्रस्ताव है ये भी रोजगार से संबंधित हैं। इससे भी रोजगार के असंख्य अवसरों का सृजन होगा। इस बारे में हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। इससे हरेक प्रकार के लोगों जैसे कारपेंटर और लुहार सभी को काम मिलेगा। इसी प्रकार से सरकार ने अनेक ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। जैसे जो डेयरीज हैं उनको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इससे भी हमारे किसान भाई डेयरी का काम करके मुनाफा कमा रहे हैं। इसी प्रकार से हथकरघा उद्योग है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के और भी उद्योग हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि कोई लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से अपना रोजगार न कर सके। लेकिन जहां तक ये जो कुछ उद्योगों की वायबिल्टी खत्म हो जाती है इस बात का संबंध है तो इसके लिए भी सरकारी दिशानिर्देशों पर बैंक्स द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर इच्छुक लोगों को लोन दिये जा रहे हैं ताकि लोग अपने उद्योगों का माईनाईजेशन कर सकें और प्रदेश में उद्योगों को भरपूर प्रोत्साहन और बढ़ावा मिले। रोजगार के प्रति सरकार पूरी तरह से चिन्तित है ताकि हरियाणा प्रगति करे यह सरकार की मंशा है। इस प्रकार से माननीय सदस्य द्वारा यह जो गैर सरकारी प्रस्ताव लाया गया है यह पूर्णतया औचित्यहीन है। इसके साथ ही स्पीकर सर, बोलने का समय देने के लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। स्पीकर सर, इसमें ऐसा था कि जिन चीजों पर कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने

के लिए ध्यान देना चाहिए वे तीन-चार चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहिए था लेकिन वे सुझाव उन्होंने नहीं दिए इसलिए ये सुझाव उनकी तरफ से मैं दे देता हूं। स्पीकर सर, सबसे पहले आज कुटीर और लघु उद्योगों को मॉडर्नाईज करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : देखिए डॉ० साहब आप इस विषय पर विस्तार से बोल चुके हैं फिर भी अगर आपके पास और कोई वैल्युएबल सुझाव हैं तो उनके बारे में आप लिखकर भिजवा दें उन पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्दौरा जी ने जो कुटीर उद्योगों के बारे में विचार रखें हैं वे तो ठीक हैं लेकिन इनके विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हरियाणा की जनता ने इनको नकार दिया है। इनके 10 एम०एल०ए० भी नहीं आये केवल 9 ही विधायक आये हैं। इनको तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। ये तो बेचारे चौटाला जी के पास अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। हरियाणा में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसने हर क्षेत्र में काम किया है। आज विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। आज फील्ड में जब पूछा जाता है कि किस पार्टी की लहर है तो जनता एक ही जवाब देती है कि किसी पार्टी की लहर नहीं है। यह पहली बार हुआ है कि एक पार्टी तीन साल से सत्ता में है और उसके बावजूद फील्ड में किसी पार्टी की लहर नहीं है। इससे पहले जितनी भी सरकारें आईं 6 महीने के बाद ही दूसरी पार्टी की लहर शुरू हो जाती थी। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने सड़कों का, बिजली का, पानी का और उद्योग बढ़ाने के लिए बहुत काम किये हैं। शिक्षा के बारे में तो इन्दौरा जी जानते ही नहीं हैं। आज हमारी सरकार ने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिये हैं जिससे हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। बी०एड० के लिए बहुत सारे कॉलेजों को मान्यता दे दी है। पहले हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग और बी०एड० की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता था और हमारा पैसा वहां पर जाता था। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था। पटवारी से जमीन की फर्द लेने के लिए भी 100-200 रुपये देने पड़ते थे। नौकरियों में तो रिश्वत और भी ज्यादा चलती थी। मास्टर लगाने के लिए डेढ़ लाख रुपये, सिपाही के 80 हजार रुपये और तहसीलदार के 5 लाख रुपये तक लिये जाते थे। भ्रष्टाचार और भयमुक्त प्रशासन का जो नारा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दिया था वह आज उस नारे पर खरी उतरती है। उनकी करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं है। मैं विधायक तो एन०सी०पी० से बना हूं लेकिन दिल ऐसा करता है कि कांग्रेस का विधायक होना चाहिए था। सभी मंत्री बहुत ही मन लगा कर काम करते हैं। चौटाला जी का सिंगापुर में 1200 करोड़ रुपये का होटल है, आस्ट्रेलिया में सबसे बड़े जमींदार हो गये हैं। सिरसा में ऐसी क्या पैदावार है कि चौटाला जी इतने धनवान हो गये? हरियाणा के दूसरे एरिया जैसे कि अम्बाला, करनाल, सोनीपत तथा पानीपत आदि तो सिरसा से कहीं आगे हैं, वहां पैदावार भी अच्छी होती है। जब हमारे पास ही इतना पैसा नहीं है कि हम दस हजार रुपये की दुकान खरीद सकें तो चौटाला के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि उसने 1200 करोड़ रुपये का होटल बना लिया तथा ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जमींदार बन गया? उन्होंने जनता की राजनीति नहीं की बल्कि अपने पेट की राजनीति की

[श्री सुखबीर सिंह]

है। लेकिन आज की सरकार जनता की राजनीति करती है। सारा पैसा जनता के लिए स्कूलों में, बी०एड० कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण पर लगाया जा रहा है जिससे लोग शिक्षित हो रहे हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए वजीफे का प्रावधान किया गया है। गरीबों के लिए भजन लाल और चौटाला ने कुछ काम नहीं किया। भजन लाल ने गरीबों के नाम से अपना पेट भरा है और चौटाला ने किसानों के नाम से अपना पेट भरा है। उन्होंने पैसे की इतनी बड़ी कीमत बना दी कि भाई को भाई मार देता है। चौटाला और भजन लाल के कारण आज भाई को भाई मार रहा है इसलिए इनको कुटीर उद्योगों की बात नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात अवश्य ही कहना चाहूंगा, आज सेज का बहुत महत्व है। सेज के कारण ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति आई थी। लेकिन एन०सी०आर० में जो जमीन सेज में एक्वायर की जाती है उसके रेट 75 लाख रुपये हैं हमारे यहां पर रेट कम है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। वह साथ लगती जमीन है उसका मुआविजा जरूर बढ़ाया जाए इसके लिए लोगों को आशा रहेगी और लोगों को इससे बहुत खुशी होगी। वे लोग आगे अपना रोजगार भी कर लेंगे जिससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और कुटीर उद्योग भी बढ़ेंगे। स्पीकर सर, आज दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी है। जब यह यूनिवर्सिटी महरौली में बनी थी तो यह ऐरिया वहां का बाहर का ऐरिया था। वहां पर लोगों को कोई आमदनी नहीं थी और लोग भूखे मरते थे। कोई भी व्यक्ति महरौली ऐरिया में रिश्ता करने के लिए नहीं जाता था लेकिन आज महरौली ऐरिया की बहुत बड़ी कीमत है क्योंकि अब वहां पर यूनिवर्सिटी बन गई है। अब हरियाणा में भी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं और एस०ई०जैड० भी बन रहे हैं। आगे इनसे सारी जनता को फायदा होगा। हम चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का समर्थन करते हैं क्योंकि जितने विकास कार्य इस सरकार ने किये हैं उतने विकास कार्य पिछले चालीस साल की सरकारों के वक्त में भी नहीं हुए थे। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सड़कें, पुल और नहरें बनेंगी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनेंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हर क्षेत्र में विकास हुआ है और इस सरकार को छत्तीस जाति का समर्थन प्राप्त है। आज प्रदेश में भयमुक्त शासन है जहां पर बहू-बेटी सुरक्षित हैं। कभी भी कहीं पर भी जाएं रात के 12 बजे भी व्यक्ति अपनी नौकरी करके घर जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर सर, पिछले राज के दौरान तो चारों तरफ बदमाशों का बोल-बाला था। हमारे यहां एक कृष्ण बदमाश था वह आज कहां है। चौटाला साहब और चौटाला साहब के लड़के उसके परममित्र थे और वे जेल में जाकर उसको मिलते थे। वह सारा अनपढ़ टोला था (विघ्न) अब पता नहीं वह कहां पर गादड़ बना छिपा बैठा है। (विघ्न) हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो। उस समय तो रोजाना गोलियां चला करती थी जिसके कारण हमारा हरियाणा प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में बदनाम हो गया था। उस समय बदमाशों के जरिये, लूट-खसोट के जरिये पैसा बनाया जाता था। जब दिल्ली में जाते थे तो वहां पर हरियाणा के लोगों से दिल्ली के लोग डरते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में भी हमारे हरियाणा प्रदेश की मार्किट गिरी हुई थी। आज सैंटर से हमारी सरकार को इतनी ग्रांट मिल रही हैं कि सारे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। जो भी कार्य हो रहे हैं वहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी का मैटीरियल लग रहा है जब कि चौटाला साहब की

सरकार के राज के समय में जो भी सड़क बनी वह साथ ही साथ टूट भी गई। उस समय जो भी मैटीरियल लगता था उसकी क्वालिटी घटिया होती थी। मैटीरियल कम ही लगता था और उन लोगों की जेबें ज्यादा भरी जाती थीं। उस समय काम की गुणवत्ता नहीं देखी जाती थी बल्कि यह देखा जाता था कि मुख्यमंत्री की कितनी इनकम होगी और मंत्रियों की कितनी इनकम होगी। उनका कोई भी एम०एल०ए० उनके पास किसी काम के लिए नहीं जाता था और अगर किसी काम के लिए जाता भी था तो कहता था कि बदली के लिए जा रहा हूं, नौकरी के लिए जा रहा हूं। जब वे उससे पूछते कि कहो कैसे आए तो एम०एल०ए० कहता था कि बस आपके दर्शन करने आया हूं और उसकी हालत यह होती थी वह काम के लिए भी नहीं कह पाते थे। उनके एम०एल०ए० इतने काबिल भी नहीं थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय एस०ई०जैड० और लघु एवं कुटीर उद्योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब बड़े उद्योग लगेंगे तो उनके साथ लघु और कुटीर उद्योग भी पनपेंगे। यह सरकार इसके लिए सुविधाएं दे रही है जिसका हम समर्थन करते हैं। बाकी चौटाला साहब का जो बैंडबाजा उठा रहे हैं ये साथी इसको छोड़ दें और जैसे गौतम जी कह रहे थे कि उनके वाली पार्टी में शामिल हो जाएं या फिर हुड्डा साहब वाली पार्टी में आ जाएं। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान (पाई) : स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, अभी थोड़ी देर पहले डॉ० इन्दौरा साहब ने कुटीर उद्योगों पर एक बहुत बड़ी भूमिका बनाई कि किस तरह से देहात के अन्दर पारम्परिक लघु उद्योग चलते थे लेकिन वे उद्योग नहीं थे। उस वक्त जो समय था उस समय के अनुसार लोगों का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था कि गांव से शहर जाने के लिए बड़ी असुविधा थी। गांव के अन्दर की जरूरत की चीज तैयार होती थी और गांव के अन्दर ही प्राप्त हो जाती थी। हमारे सारे इलाकों के अन्दर बैकवर्डनैस होती थी। स्पीकर सर, समय के साथ परिवर्तन आया है। जहां पहले एक ठठेरा काम करता था वहां अब वैल्डिंग सैट्स आए हैं, लेथ्स आई हैं और गांवों के अन्दर भी इस तरह की चीजें हुई हैं जिसके कारण गांवों में भी तरक्की हुई है। जैसे गौतम जी ने कहा यह दुरुस्त है कि पिछले राज में उद्योगों का पलायन हुआ। हरिजनों का पलायन तो हुआ ही हुआ लेकिन इसके साथ ही साथ गांवों में जो छोटे-छोटे दस्तकार थे वे भी भय के कारण शहरों में आ गये। किसी ने टंकिया बनाना शुरू की तो किसी ने कुछ और काम करना शुरू किया। किसी ने एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंट्स की रिपेयर का काम शुरू किया लेकिन उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। जो आदमी हैवी इण्डस्ट्रीज लगाएगा उसको एनसिलरीज की भी जरूरत पड़ेगी उनके साथ ही साथ एनसिलरीज की मदद के लिए हर शहर में, हर उस कॉर्नर में जहां पर बड़े उद्योग लगे हैं छोटे-छोटे ऐसे यूनिट्स भी हैं जो पार्टस बना रहे हैं या छोटे-छोटे काम कर रहे हैं। कोई टर्नर का काम करता है तो उसने एक ही मशीन लगा रखी है और वह बुश ही बनाए जा रहा है या कोई और चीज ही बनाए जा रहा है। इन लोगों की समस्या है कि समय के साथ-साथ डीज़ल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आज से पांच साल पहले तक डीज़ल इंजन जिसे जनरेटर सैट कहते हैं से बिजली का प्रयोग किया जाता था। इसके द्वारा बनाई गई बिजली का दाम और सरकारी बिजली बोर्ड से प्राप्त की जाने वाली बिजली के दाम लगभग एक से होते थे। डीज़ल के दाम बढ़ने की वजह से उसकी वर्किंग इक्नॉमी फेल हो गई जिसकी वजह से वह

13.00 बजे

[श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान]

एक या डेढ़ मैगावाट की टरबाईन नहीं लगा सकता है वह पूरी तरह से सरकार द्वारा बनाई जाने वाली बिजली पर डिपैंडैंट हो गया। इत्तिफाक से आज बिजली की कमी है और इण्डस्ट्रीज भी आज बिजली की कमी को झेल रही हैं। आज जो बड़े-बड़े ग्रुप हैं उनकी तो अपनी पॉवर जनरेशन है और उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, छोटी इकाईयां हैं और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं उनमें प्रदेश भर में बहुत भारी समस्या है। उन सभी की वॉयबलीटी बहुत कम है, इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। स्पीकर सर, स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री के फाईनांशियल लिमिट 50 लाख रुपये हैं उसको आज के समय में बढ़ा देना चाहिए। स्पीकर सर, जो चीज आज से पहले 1 लाख रुपये की थी वह बढ़कर 5 लाख रुपये और 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई है। गवर्नमैंट आफ इण्डिया इसको इन्क्रीज करती रही है and probably today it is at 50 lacs per unit. It needs to be increased at least double the amount because an industry of the size whatever was setup in 10 years ago, now takes 10 times more money to be installed. उसकी वजह से अनलैस वे छोटी-छोटी सुविधाएं स्माल स्केल इण्डस्ट्री को गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने प्रदान कर रखी हैं। उसमें एक ब्रैकेट आ जाता है जो थोड़ा सा बढ़ने की वजह से वह सुविधाएं जरूरतमंदों को प्रदान नहीं हो पाती हैं। आज एक गांव में एक लुहार ने वैल्डर सैट लगाया हुआ है और वह 12-12 घंटे बिजली के आने का इन्तजार करता रहता है कि कब बिजली आए तो मैं एक टांका लगाऊं। यह जो ग्रामीण इण्डस्ट्री है, छोटे दस्तकार और वैल्डर्ज हैं वे छोटी-छोटी दुकानें लगाकर गांवों में बैठे हुए हैं उनकी छोटी-छोटी बहुत सी समस्याएं हैं। उसमें एक घर के दो-दो और तीन-तीन आदमी काम करते हैं। उनकी तरफ मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह जो इन्दौरा जी गैर सरकारी संकल्प लेकर आए हैं इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि आज समय के साथ इन सभी चीजों में परिवर्तन हो गया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में बड़ी-बड़ी चीजें बनती हैं और यहां तक कि उसमें पंखों के और कम्प्यूटर के पार्ट्स भी बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में एस्कॉर्ट कम्पनी बड़ी होती थी अब तो मध्यम हो गयी है। सर, देहातों में लोग एस्कार्ट के लिए काम करते थे उसके लिए पुर्जे बनाने का काम करते थे। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह जो एस०सीज० को 100 गज के प्लाट देने की स्कीम बनाई है, उसी तरह से मुख्यमंत्री जी की योजना भी है कि गांवों में हुडा की तर्ज पर ग्रामीण हाऊसिंग एस्टेट बनाएंगे। इसी तरह से उन लोगों को भी इस तरह से कोई जगह देने का प्रावधान करें ताकि वे उद्योग आज जो गांवों से पलायन कर रहे हैं और वापिस आना चाहते हैं, वे वापिस अपने गांवों में चले जाएं। सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनके डोमैस्टिक खर्चे कम हो जाएं और वे वहीं पर अपने उद्योग लगा सकें। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा प्रावधान यह सरकार करेगी तो उन श्रमिकों के लिए, गरीब आदमियों के लिए बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनकी चिन्ता को लेकर एक गैर सरकारी संकल्प माननीय इन्दौरा जी इस सदन में लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां इनकी चिन्ता है, वह वाजिब है। मुझे और खुशी होती, सरकार को और खुशी होती अगर रचनात्मा सुझाव, नीतिगत सुझाव जो सही मायनों में

हमारे ग्रामीण उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, हथकरघा उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, लघु उद्योग में लगे व्यक्ति हैं उनका किस प्रकार से भला हो, के बारे में आते । स्पीकर साहब, इनके भले की और क्या-क्या योजना आ सकती है, इसके बारे में माननीय सदस्य अगर सुझाव देते तो बहुत अच्छा रहता । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रावधान मैम्बर्ज-डे पर, प्राईवेट मैम्बर्ज रैजोल्यूशन लाने की जो परम्परा आपने दोबारा से शुरू की है इसका लक्ष्य कई बार ऐसे मुद्दे जो प्रदेश और देश की जानकारी से जुड़े हैं, जो ज्वलन्त हैं, उन पर परिचर्चा करना है । इसमें राजनीतिक विरोध की सीमाएं मिट जानी चाहिए, हमें इन मुद्दों पर चर्चा करते वक्त यह भूल जाना चाहिए कि हम सदन में किस तरफ बैठे हैं । इन पर सुझाव यह आना चाहिए कि किस प्रकार से वर्ग विशेष की जो दिक्कते हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल हम कैसे निकाल सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, Before I proceed मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि यह देश गांव में रहता है, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने यह कहा कि रोजगार सृजनात्मक उद्योग ही देश की तरक्की का आधार बन सकता है, इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य गरीब व कुचले वर्गों को सही मायनों में इस देश का मालिक बनाना है । अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि ग्रामीण विकास व गांव के गरीब का उत्थान छोटी इकाईयां एवं कुटीर उद्योग व स्किल्ड डिवैल्पमैंट ही बेरोजगारी उन्मूलन का असली रास्ता और मूलमंत्र है । अध्यक्ष महोदय, कॉटेज इंडस्ट्रीज या कुटीर उद्योग की परिभाषा के बारे में Oxford English Dictionary says that "a Cottage Industry is a small business or manufacturing activity carried on a people's home". अध्यक्ष महोदय खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने कॉटेज इंडस्ट्रीज की व्याख्या करने का प्रयास किया । स्पीकर सर, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम किस परिधि के अंदर बात कर रहे हैं वह भी जानना जरूरी है, I quote Sir, the Khadi and Village Industry Commissioner Government of India. Being labour intention, Cottage Industry creates employment of opportunities on a substantial scale for the people of rural area particularly for women. It also provides supplementary employments to persons below poverty line at their door-steps. Since, the manufacturing processes are light and simple the handicapped and old people can also get employment. Those cottage industries has been creating socio-economic significance in bringing livelihood to the people thereby preventing migration of villages to urban areas. यह भी एक लक्ष्य छोटे और कुटीर उद्योगों का है । अध्यक्ष महोदय, इस सारी बात को पहचानकर हरियाणा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है उसके माध्यम से हम रूरल इम्प्लायमैंट जैनरेशन प्रोग्राम चलाते हैं । जो आर०ई०जी०पी० है इसके दो लक्ष्य हैं । अगर दस लाख रुपये तक का लोन है तो मार्जन मनी के तौर पर 25 परसैंट पैसा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड देगा और यदि 25 लाख रुपये तक का लोन है तो दस परसैंट पैसा मार्जन मनी के तौर पर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड देगा । मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हरियाणा की क्या डिवैल्पमैंट रही है किस प्रकार से रोजगार उत्पन्न किया क्योंकि यह भी इस परिचर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मार्च, 2005 से फरवरी, 2008 तक मौजूदा सरकार के समय में 1869 केसिज हरियाणा खादी और इंडस्ट्रीज बोर्ड ने क्लीयर किए और इसके माध्यम से हमने 13618 लाख 79 हजार या अध्यक्ष महोदय मैं यह कहूं कि 136 करोड़ 18 लाख 79 हजार की राशि 3 साल के अंदर

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

हमने वितरित की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्कीम के तहत रूरल इम्पलायमैंट स्कीम जो है इससे पचास हजार चार लोगों को पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में हम रोजगार दे पाए हैं। 31 करोड़ 80 लाख 86 हजार रुपये की मार्जिन मनी जो कि सरकार का हिस्सा था, वह भी इन इकाइयों को दी है जो कि इनके माध्यम से लगाई गई थीं। हरियाणा के गठन के बाद यह अपने आप में एक रिकार्ड भी है। सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं पिछले पांच वर्षों के आंकड़े भी रिकार्ड पर लाना चाहूंगा कि किस प्रकार से खादी और कुटीर उद्योग ने किस प्रकार से हरियाणा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तरक्की की है। जब हमें सरकार मिली तब क्या स्थिति थी और इनको बढ़ावा देने में, इनको प्रमोट करने में, इनके उत्थान में ओर इनको आगे ले जाने में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इस बारे में मैं साल 2000-2001 से फरवरी, 2005 तक के आंकड़े बताना चाहूंगा। 1538 केस पांच साल की अवधि में क्लीयर किए गए। हमने 3 साल में 1869 केस क्लीयर किए हैं और इन केसिज में पिछले पांच वर्षों के इनके शासनकाल में जो राशि दी गई वह कुल 94 करोड़ 79 लाख 92 हजार रुपये की राशि दी गई और इसके विपरीत हमारे तीन साल के कार्यकाल के दौरान इस सरकार ने 136 करोड़, 18 लाख 79 हजार रुपये दिये। ये साथी पांच साल के शासन काल में 19205 लोगों को रोजगार दिलवा पाए जबकि हमने 50004 लोगों को रोजगार दिया है। मार्जिन मनी पिछले पांच वर्षों में 2001 से फरवरी, 2005 तक 18 करोड़ 67 लाख थी और हमने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने तीन साल के अंदर ही दुगने के करीब 31 करोड़ 80 लाख 86 हजार रुपये की राशि दी है। जो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार है उनकी छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बारे में नीति क्या है, नीयत क्या है, लक्ष्य क्या है, रास्ता क्या है, मूलमंत्र क्या है यह जीते जागते आंकड़े उसका ज्वलंत प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो ग्रामीण रोजगार है और उससे जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार उत्पन्न किया जाता है। जिसमें छोटे-छोटे उद्योग जैसे कोई दुकान है या कोई ऐसे व्यवसाय हैं उनके द्वारा हमारे गांव के बच्चों को और गरीब लोगों को रोजगार मिले इसके लिए हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। इस योजना के तहत 12500 रुपये की सबसिडी की राशि भी दी जाती है। हरेक क्षेत्र में ट्रेनिंग का प्रावधान भी इसके अंदर है। हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं ताकि गांव के गरीब और नौजवान साथी और छोटे-छोटे दुकानदार जो छोटा-मोटा धंधा करें उसमें वे स्किल डिवैल्पमैंट भी कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को बताना चाहूंगा कि तीन वर्ष में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल में 2005-06 से 2007-08 तक 31491 लोगों को ग्रामीण रोजगार के मामले में नौजवानों को और गरीब आदमियों को इस स्कीम के माध्यम से मदद दी गई है। इसमें हमने 177 करोड़ 98 लाख 81 हजार रुपये की राशि दी है। जिसमें से 12500 रुपये की राशि सबसिडी के तौर पर दी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तीन साल में 50004 लोगों को हरियाणा खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड द्वारा और तकरीबन 31491 लोगों को हरियाणा

खादी एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दिया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 81495 लोगों को मात्र इन दो मदों में लोन देकर मदद की है और रोजगार दिया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमने किस प्रकार की जियोग्राफिकल प्रोग्रैस की है। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि अगर उसको आज जब पिछले पांच साल के आंकड़ों से कम्पेयर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2004-2005 यानि पांच साल के अन्तराल के दौरान जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी माननीय इन्दौरा साहब की पार्टी की सरकार थी उस समय 38005 केस पांच साल के अन्दर किए गये और 21 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि दी गई। इसके विपरीत तीन साल के अन्दर हमने जो राशि दी जैसा कि मैंने आंकड़े दिए हैं यह सरकार की नीतियों का आईना है कि किस प्रकार से लगातार यह संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय यह वाजिब चिन्ता जाहिर की है कि कलैस्टर डिवैल्प किये जा रहे हैं आज कोई कहीं जूती बनाने का व्यवसाय करता है कहीं कोई छाज-छलनी का व्यवसाय करता है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है। आज उन्हें प्रोमोट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से मिलकर कलैस्टर डिवैल्प करने के लिए इस प्रकार के लघु कुटीर उद्योग लगे हैं। हमने जूती बनाने वाले कलैस्टर को इस्माईलाबाद में फाईनैंशियल मदद की है। इसी प्रकार से पटसन और केन का फर्नीचर बनाने के लिए फरुखनगर, गुड़गांव में है उनको फाईनैंशियल मदद की है। लैदर और फुट वीयर बनाने के लिए ओढ़ी गांव जो भिवानी के पास है उनको फाईनैंशियल मदद की है। इसी प्रकार से कढ़ाई और फ्रेम मेकिंग का कलैस्टर गांव तालू, महेन्द्रगढ़ में कुछ फाईनैंशियल मदद पहुंचाई है। इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान है। यह नहीं है कि हमने उस तरफ से ध्यान छोड़ दिया है। इसी प्रकार के दूसरे छोटे कुटीर उद्योग हैं सरकार उनको मदद पहुंचा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की एसिसटैंश देने के लिए एक प्रोपोजल बनाकर हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को भेजी है। माननीय भारद्वाज ने बड़ी खूबसूरती के शब्दों में कहा कि इस प्रकार के कलैस्टर भिवानी में स्किल्ड डिवैल्प हो रहे हैं जो इनके यहां लकड़ी के मनके बनाते हैं। इसी प्रकार गांव मंगाली, हिसार में भी मनके बनाये जाते हैं उनको भी हमने फाईनैंशियल मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार को लिखा है और वह जल्दी ही मंजूर हो जाएगा। आदरणीय मान साहब ने स्माल स्केल इण्डिस्ट्रीज की चर्चा की। मैं इस सदन का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि स्माल स्केल इण्डिस्ट्रीज को लेकर कई इंसैंटिव हमारी सरकार ने दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल यूनिट जो बैकवर्ड एरिया में लगाये जाते हैं उनके ऊपर जो वैट का टैक्स लगता है उसकी 50 प्रतिशत राशि पांच साल तक सरकार मुफ्त लोन के तौर पर देती है। पांच साल के बाद हम वापिस लेते हैं जैसे अगर 100 रुपये वैट टैक्स देना है तो 50 रुपये की राशि दें तो पांच साल के लिए वह डैफैर्ड कर दी जाती है और इन्ट्रस्ट फ्री लोन के हिसाब से ट्रीट कर लिया जाता है और पांच साल के बाद वे वापिस कर सकते हैं ताकि जो-जो हमारे प्रान्त के अन्दर पिछड़े क्षेत्र हैं उनके अन्दर ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग आ सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फूड प्रोसैसिंग इण्डिस्ट्रीज हैं जैसे कोई पापड़ बनाने का कारखाना लगाना चाहता है, कोई छोटी फैक्ट्री लगाना चाहता है या अचार बनाने के लिए कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहता है इनके लिए 75 प्रतिशत वैट टैक्स पांच साल तक माफ किया है और इनको इन्ट्रस्ट फ्री लोन ट्रीट किया जाता है तथा पांच साल के बाद वे वापिस

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

दे दें। 88 ऐसे ब्लॉक हैं जिनके अन्दर हमने ऐसी इण्डिस्ट्रीज को बैकवर्ड घोषित किया गया है और उनके माध्यम से इसी प्रकार से सुविधा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा आपकी अनुमति से कि जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं और बड़े उद्योग हैं किसी भी प्रान्त की तरक्की के लिए कहीं न कहीं ये उद्योग और औद्योगिक क्रांति के नये संचार होते हैं। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं, दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं अगर हम आंकड़े देखें तो मौजूदा सरकार के अन्दर जो उद्योग लेकर आये हैं पहले मैं आपको लघु, माध्यमिक उद्योग और छोटे उद्योग उनके आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ष 2005-2006 से लेकर वर्ष 2007-2008 यानि तीन साल के अन्तराल में हरियाणा के अंदर 4275 नए लघु उद्योग लगाए गए, इससे जो इन्वैस्टमैंट कैटेलाइज हुई, जो पैसा आया वह तकरीबन 1098 करोड़ 29 लाख रुपये है। इतना पैसा निवेश के तौर पर इन लघु उद्योगों के माध्यम से आया है। इससे 60615 लोगों को रोजगार मिला है। 50004 लोगों को हरियाणा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के माध्यम से और 31491 लोगों को कुटीर उद्योग बोर्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार मिला है। यानि तकरीबन डेढ़ लाख लोगों को रोजगार की संख्या यही बन जाती है। आदरणीय गौतम जी ने, आदरणीय सुखबीर सिंह फरमाणा ने, आदरणीय बत्तरा साहब ने, तेजेन्द्रपाल सिंह मान ने, भारद्वाज जी ने और गुप्ता जी ने चर्चा की कि क्या कारण थे कि मौजूदा कांग्रेस की सरकार के आते ही लघु उद्योग यहां यकायक लगने लगे, यकायक निवेश पैदा होने शुरू हो गए, यकायक नए रोजगारों का सृजन शुरू हो गया। पिछले सालों के आंकड़े देखें उसमें 2000-01 से लेकर 2004-05 के बीच के 5 सालों में जो लघु उद्योग हरियाणा में आए हैं उनकी संख्या मात्र 3479 थी जबकि हमारे इन तीन सालों में यह संख्या 4275 आई है। पिछली सरकार के 5 सालों में जो निवेश आया है वह है 1856 करोड़ रुपये और हमारा जो 3 साल में निवेश आया है वह है 2477 करोड़ रुपये। उनके समय में 40776 लोगों को रोजगार मिला है जबकि हमारे तीन सालों में 60615 लोगों को रोजगार मिला है तो कहीं न कहीं यह सरकार की नीति और नियति को दर्शाता है। आदरणीय इन्दौरा साहब, मुलाना जी और तेजेन्द्रपाल जी ने भी चर्चा की कि किस प्रकार लघु, कुटीर और छोटे उद्योगों को संरक्षण दे सकते हैं। इन्दौरा जी ने एक सुझाव दिया कि एक कमेटी बना दें जो पूरी तरह से सारी बातों को देखकर इनका संरक्षण करे। इन्दौरा जी ने एक यह भी सुझाव दिया कि लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट की व्यवस्था की जाए, लोन की व्यवस्था की जाए, उन्होंने संसाधन जुटाने पर भी बल दिया। इन्दौरा जी ने ट्रेनिंग की बात की कि जो लोग लघु और कुटीर उद्योगों में लगे हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए ताकि ये वाकई में प्रोफिटेबल बनें। आदरणीय तेजेन्द्रपाल सिंह जी ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट बढ़ाने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि जहां हम हमेशा रोजगार सृजन करने की बात करते थे वहीं आजाद हिन्दुस्तान में एक और क्रांतिकारी कानून श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार लेकर आई है कि कानून द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। आज से पहले किसी सरकार ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। नेशनल रूरल इम्पलायमैंट गारंटी एक्ट जिसे देश के 596 जिलों में एक अप्रैल से यू०पी०ए० की सरकार ने लागू किया है। इस प्रकार एक और कानून

हमारी सरकार लेकर आई है, इन्दौरा साहब, यह आपकी जानकारी के लिए भी है and it is called "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006." यह जो 2006 का कानून है इससे माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्माल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज को कानूनी संरक्षण का अमली जामा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्रेडिट की बात की, लिमिट बढ़ाने की बात की। इस कानून के माध्यम से कानून की पुस्तिका में हमेशा-हमेशा के लिए श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लिख दिया कि माइक्रो इंडस्ट्रीज को, मीडियम इंडस्ट्रीज को, स्माल इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से किस व्यवस्था से और किस प्रणाली से संरक्षण देंगे। I would like to draw the attention of this House to two-three provisions of this Act. अगर आप इसकी ओपनिंग पढ़ें तो इसमें स्पष्ट लिखा है :--

> "An act to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto.
>
> And whereas it is expedient to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto."

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं इसके दो-तीन प्रावधानों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो बात इन लोगों ने कही है उसको पहले से ही कानूनी अमलीजामा पहनाया हुआ है। अगर इसकी धारा-7 की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूं जिसमें लिखा है :--

> "7. (1) Notwithstanding anything contained in section 11B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government may, for the purposes of this Act, by notification and having regard to the provisions of sub-sections (4) and (5), classify any class or classes of enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of people, cooperative society, partnership firm, company or undertaking, by whatever name called, —
>
> (a) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as
>
> (i) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees ;
>
> (ii) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or"

जो इन्होंने कहा है वह इसमें कवर हो गया है।

> "(iii) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees;"

सर, यह हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है।

> "(b) In case of the enterprises engaged in providing or rendering of services, as

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

(i) a micro enterprise, where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees ;

(ii) a small enterprise, where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees ; or

(iii) a medium enterprise, where the investment in equipment is more than two crore rupees but does not exceed five crore rupees."

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended for 10 minutes ?

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : The time of the House is extended for ten minutes.

गैर-सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं इसके स्टेचुटरी प्रोविजंस भी पढ़कर सुनाता हूं जिसके सैक्शन-9 में लिखा है :--

"9. (1) The Central Government may, from time to time, for the purposes of facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises, particularly of the micro and small enterprises, by way of development of skill in the employees, management and enterpreneurs, provisioning for technological upgradation, providing marketing assistance or infrastructure facilities and cluster development of such enterprises with a view to strengthening backward and forward linkages, specify, by notification, such programmes, guidelines or instructions, as it may deem fit."

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने क्रेडिट फैसेलिटीज के बारे में कहा है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के सैक्शन-10 में हमने पहले ही अमलीजामा पहना रखा है जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूं :--

"10. The policies and practices in respect of credit to the micro, small and medium enterprises shall be progressive and such as may be specified in the guidelines or instructions issued by the Reserve Bank, from time to time, to ensure timely and smooth flow of credit to such enterprises, minimize the incidence of sickness among and enhance the competitiveness of such enterprises."

स्पीकर सर, इसके अन्दर तीसरा प्रावधान यह है कि परचेज प्रेफ्रैंस को स्टेचुटरी अमलीजामा पहली बार पहनाया गया है। इससे जो चीजें खरीदनी हैं उनको सरकार के द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

"11. For facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government may, by order notify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or departments, as the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises."

वह भी एड कर लिया गया है। सरकार द्वारा सभी एड कर लिये गये हैं। इनके लिए एक स्पैशल फण्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है ताकि इनकी मदद की जा सके। माननीय सदस्य ने जो बात की है मैं उसको और आगे ले जाता हूं। सर, इसमें कहा गया है कि—

"12. There shall be constituted, by notification, one or more Funds to be called by such name as may be specified in the notification and there shall be credited thereto any grants made by the Central Government under section-13.

13. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, credit to the Fund or Funds by way of grants for the purposes of this Act, such sums of money as that Government may consider necessary to provide."

भारत सरकार एक गारंटी देगी जिससे एक फण्ड बन जायेगा और उससे इन उद्योगों की मदद की जायेगी। सर, इसके अलावा इसी कानून के अन्दर यह प्रावधान भी होगा क्योंकि स्पीकर सर, जो ये छोटे-छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग हैं कल को अगर उनसे कोई सप्लाई ले लें और उनको पेमैंट न दें तो वे क्या करेंगे? भारत सरकार उस फण्ड को देगी यह इसमें स्पष्ट लिखा है कि फण्ड बनाया जायेगा और वह फण्ड इसको फिर आगे फाईनैंस करेगा। इस बात को कानूनी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। स्पीकर सर, श्रीमती सोनिया गांधी की कांग्रेस सरकार के द्वारा यह बात भी देखी गई कि अगर कोई किसी छोटे और कुटीर उद्योग के मालिक से पैसा ले और पैसा उसको वापिस न दे इस पर वह बेचारा तो अदालतों के अन्दर जायेगा और वर्षों तक निर्णय नहीं होगा इसलिए उसका भी एक नायाब प्रावधान इस कानून के अन्दर किया गया है। Speaker Sir, I would like to draw attention of this August House that in section-15, it is clearly mentioned that —

"15. Where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or, where there is no agreement in this behalf, before the appointed day :

Provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed forty five days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance."

स्पीकर सर, सैक्शन-16 के अन्दर यह लिखा है कि अगर वह 45 दिन के आगे चला जायें तो उसे छोटे और कुटीर उद्योग को three times of the bank rate of interest देना पड़ेगा। यह भी प्रावधान इसमें किया गया है। अब डिस्प्यूट रिड्रैसल मैकेनिज्म बनाया गया है। इसके लिए एक काऊंसिल बना दी गई है और इस प्रकार के जो विवाद हैं वे सैक्शन-18 के तहत उस काऊंसिल को जायेंगे और अगर कोई व्यक्ति या संस्था लघु और कुटीर उद्योगों

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

के हित में दिए गए उस काउंसिल के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहेगा तो उसे 75 प्रतिशत राशि पहले जमा करवानी पड़ेगी। इस प्रकार का सेफ मैकेनिज्म इसमें बनाया गया है और लघु एवं कुटीर उद्योगों की परिभाषा पहली बार सोनिया गांधी जी की सरकार ने बदल दी है और माईक्रो, स्मॉल और मीडियम जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनके अन्दर भी 3-3 परिभाषायें एड की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचे। मुझे लगता है कि यह कानून अपने आप में एक इतिहास है और लघु एवं कुटीर उद्योगों के संरक्षण के लिए इस देश के अन्दर उठाया गया आज तक का शायद यह सबसे बड़ा और ठोस कदम है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने रोजगार सृजन करने के लिए जो प्रयास किया है उसी का यह नतीजा निकला है। इस बारे में बहुत थोड़े और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 33 हजार करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट पिछले तीन सालों में अब तक हमारे पास आ चुकी है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सर, पिछले 40 वर्षों में 42 हजार करोड़ रुपये के करीब इन्वैस्टमैंट हुई थी। हमारे कार्यकाल के दौरान 33 हजार करोड़ रुपये का निवेश अकेले जमीन पर लग चुका है और इसके अलावा 66 हजार करोड़ रुपये के उद्योग इस समय हमारे पास पाईपलाईन में हैं। जिनकी प्रपोजल हमारे पास इस समय रिसीव हो गई है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमेरिका और कैनेडा में यात्रा की थी उससे भी जो रिनाऊन अमेरिकन और कैनेडियन कम्पनियां हैं उन्होंने 3750 करोड़ रुपये का निवेश किया है। स्पीकर सर, स्टेट में अब तक 10,500 करोड़ रुपये की डारेक्ट फॉरेन इनवैस्टमैंट आई है। जो अपने आप में और प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, आपने निर्यात की चिन्ता की थी इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि 2006-07 में प्रदेश का निर्यात 30 हजार करोड़ रुपये का था और इसके अलावा हमारे पास एच०एस०आई०आई०डी०सी० के पास पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मोड में बहुत से मेगा प्रोजैक्ट आये हैं जिनसे हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत सारी इनवैस्टमैंट होगी। एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें रोजगार का सृजन हो और जिसमें छोटे और कुटीर उद्योगों को लाभ मिले। बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों को भी लाभ मिले और बड़े उद्योग भी प्रदेश में आयें खेती के अन्दर नई जान आये, नई रोशनी आये। औद्योगिक क्रान्ति से प्रदेश में महरूम न रहे, इस सरकार ने इसके लिए सतत प्रयास किये हैं। यही सब बातें थी जिनका मैं ब्योरा देना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस कानून की मैंने चर्चा की है वह "National Rural Employment Guarantee Act." है। इसके बाद इन्दौरा जी जो प्रस्ताव लेकर आये हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि in the light of all issues that he has raised, are already taken care of by this force of statute passed by the Parliament of India. Either he should withdraw his resolution or this House should reject this resolution ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही लोग महत्व के विषय पर इस सदन में चर्चा हुई। मैं श्री शादी लाल बतरा, श्री नरेश मलिक, श्री रामकुमार गौतम, डॉ० शिवशंकर भारद्वाज, श्री नरेश शर्मा, श्री मान साहब, श्री सुखबीर सिंह फरमाणा, श्री मांगे राम गुप्ता व और साथी जो इस विषय पर बोले हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं तथा बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और बहुत से

अच्छे सुझाव भी रखे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तारीफ करने के साथ-साथ उन्होंने सरकार को अच्छे सुझाव भी दिये हैं। माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में बहुत सी ऐसी बातें बताई जिससे कुटीर उद्योग को लाभ होता है लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एक सोच है कि कुटीर उद्योग की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि संशोधन करके माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को अपने पास रख लें और इस तरफ थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दें या कमेटी बनाकर इसका और अध्ययन करवा लें। मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रस्ताव को एडॉप्ट करना चाहिए और इसको पास करना चाहिए।

Mr Speaker : Question is—

> This House expresses its great concern over the continuous demotion of the cottage industries, particularly traditional industries in the State as the cottage industry is only capable to provide employment to the skilled and unskilled labourer class of the rural areas of the State.

The motion was lost.

The resolution was rejected.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 24th March, 2008.

*13.39 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 24th March, 2008).

44395 —H.V.S.—H.G.P., Chd.